

RAPID REVISION SERIES

800 High Probable
Topics for
UPSC Prelims 2021
(Current Affairs + Static Portion)

हिंदी

Full Compilation

ECONOMY

Make the best use of this document by combining free explanation videos of these topics, Current Affairs Quiz, Static Quiz, CSAT Quiz, & 3 Full Mocks on [rrs.iasbaba.Com](https://rrs.iasbaba.com) (A Free Initiative targeting UPSC PRELIMS 2021)

Q.1) शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह हमेशा किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है।
2. शुद्ध घरेलू उत्पाद अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों को दर्शाता है।
3. इसका उपयोग IMF/WB द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करने के लिए किया जाता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Q.1) Solution (b)

शुद्ध घरेलू उत्पाद को देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे किसी देश के आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक माना जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद (NDP) की गणना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से देश की पूंजीगत संपत्ति जैसे मशीनरी, आवास और वाहनों के मूल्यहास के मूल्य को घटाकर की जाती है।

NDP का सूत्र इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

$$NDP = GDP - \text{मूल्यहास}$$

इस प्रकार, NDP हमेशा GDP से कम होता है।

NDP का उपयोग अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों को दिखाने के लिए किया जाता है, जिन्होंने ऐतिहासिक समय अवधि में मूल्यहास के स्तर को कम करने की कोशिश की है।

विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में NDP का उपयोग नहीं किया जाता है। यह मूल्यहास की विभिन्न दरों के कारण है जो विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं द्वारा निर्धारित की जाती है।

Q.2) निम्नलिखित में से कौन सा आधार है जिस पर IMF विश्व के देशों को क्रय शक्ति समता (PPP) में श्रेणीबद्ध करता है?

- a) शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)
- b) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)
- c) सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
- d) सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

Q.2) Solution (d)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP): यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

यह देश के भीतर या बाहर मौजूद देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखता है। इसमें देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को शामिल नहीं किया गया है। इसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है:

$$\text{GNP} = \text{GDP} + \text{NR} - \text{NP}$$

जहां

GDP = सकल घरेलू उत्पाद

NR = शुद्ध आय प्राप्तियां

NP = विदेशी परिसंपत्तियों के लिए शुद्ध बहिर्वाह

यह राष्ट्रीय आय है जिसके अनुसार आईएमएफ विश्व के देशों को मात्रा के मामले में- क्रय शक्ति समता पर स्थान देता है। यह राष्ट्रीय आय की अधिक विस्तृत अवधारणा है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक पहलू के बारे में इंगित करता है अर्थात् अर्थव्यवस्था की आंतरिक और बाहरी शक्ति।

Q.3) निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आर्थिक विकास और असमानता के बीच संबंध की व्याख्या करता है?

- a) कुजनेट वक्र (Kuznets Curve)
- b) लाफर वक्र (Laffer Curve)
- c) फिलिप्स वक्र (Phillips Curve)
- d) गिनी गुणांक (Gini Coefficient)

Q.3) Solution (a)

कुजनेट वक्र (Kuznets Curve) का उपयोग इस परिकल्पना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि आर्थिक विकास शुरू में अधिक असमानता की ओर जाता है, इसके बाद असमानता में कमी आती है।

इस विचार का प्रस्ताव सबसे पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री 'साइमन कुज्नेट्स' द्वारा रखा गया था। जैसा कि आर्थिक विकास बेहतर उत्पादों के निर्माण से होता है, यह आम तौर पर उन श्रमिकों और निवेशकों की आय को बढ़ाता है जो नवाचार की पहली लहर में भाग लेते हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण इसका एक आम उदाहरण है। हालांकि, यह असमानता श्रमिकों और निवेशकों के रूप में अस्थायी हो जाती है, जो शुरू में जल्द ही एक ही या बेहतर उत्पादों की पेशकश करने में मदद करके पीछे रह गए थे। इससे उनकी आय में सुधार होता है।

Q.4) फिलिप्स वक्र (Phillips Curve) दर्शाता है:

- a) किसी अर्थव्यवस्था के सरकारी खर्च और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के बीच संबंध।
- b) आर्थिक प्रगति और पर्यावरण क्षरण के बीच संबंध।
- c) मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध।
- d) किसी विशेष वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय और घरेलू आय में परिवर्तन के बीच संबंध।

Q.4) Solution (c)

फिलिप्स वक्र (Phillips Curve) ए डब्ल्यू फिलिप्स (A. W. Phillips) द्वारा विकसित एक आर्थिक अवधारणा है। इसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का स्थिर और व्युत्क्रम संबंध है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती है, जिसे बदले में अधिक नौकरियां और कम बेरोजगारी का नेतृत्व करना चाहिए। हालांकि, मूल अवधारणा 1970 के दशक में मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation) की घटना के कारण कुछ हद तक अप्रमाणित अनुभवजन्य रही, जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों के उच्च स्तर थे।

उपभोक्ता और श्रमिकों की अपेक्षाओं के आलोक में फिलिप्स वक्र को समझना, यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध लंबे समय में, या संभावित रूप से अल्पावधि में भी नहीं हो सकता है।

Q.5) हाल ही में समाचारों में रहे 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (Inverted Duty Structure)' के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक ऐसी स्थिति है जहां तैयार माल पर कर की दर उपयोग किये गए आदानों (inputs) पर कर की दर से अधिक होती है।
2. सीमा शुल्क के मामले में 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' प्रचलित है।
3. इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

- a) केवल 1
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q.5) Solution (b)

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) एक ऐसी स्थिति है जहां उपयोग किए गए आदानों पर कर की दर तैयार माल पर कर की दर से अधिक होती है।

टायर उद्योग की एक काल्पनिक स्थिति लें; खरीदे गए प्राकृतिक रबर (इनपुट) पर कर की दर 10% है जबकि रबर के टायर पर कर की दर 5% है। यहां चूंकि इनपुट पर कर की दर तैयार माल पर कर की दर से अधिक है, इसलिए एक उलटी कर संरचना है।

सामान्य स्थिति यह है कि उपयोग किए गए इनपुट पर कर तैयार माल की कर दर से कम होता है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) आमतौर पर सीमा शुल्क (आयात शुल्क) के मामले में प्रचलित है।

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) हमारे जीएसटी सिस्टम में कई प्रशासनिक समस्याओं का कारण बन रही है:

- करदाताओं के पास कर विभाग के पास धनवापसी दावों के रूप में जमा क्रेडिट होगा।
- इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) सरकार के लिए एक राजस्व हानि है क्योंकि उसे पहले से चुकाए गए कर (इनपुट्स में) को वापस करना पड़ता है।
- जीएसटी के तहत, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) की पहचान वस्तुओं के लिए की जाती है न कि सेवाओं के लिए। या दूसरे शब्दों में, 'इनपुट गुड' के लिए मान्यता है न कि 'इनपुट सेवाओं' के लिए।

Q.6) गिग इकॉनमी (Gig Economy) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक बाजार प्रणाली है जिसमें संगठन अल्पकालिक कार्यों के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।
2. भारत में 50% से अधिक नए रोजगार गिग इकॉनमी कंपनियों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.6) Solution (c)

गिग इकॉनमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं और संगठन अल्पकालिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।

भारत में अनुमानित 56% नए रोजगार गिग इकॉनमी कंपनियों द्वारा ब्लू-कॉलर और व्हाइट-कॉलर कार्यबल दोनों में उत्पन्न किए जा रहे हैं। इस घातीय वृद्धि के कुछ कारण हैं:

- डिजिटल युग में, कार्यकर्ता को एक निश्चित स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं है - काम कहीं से भी किया जा सकता है, इसलिए नियोजक किसी परियोजना के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन भूगोल से बंधे बिना कर सकते हैं।
- लगता है जैसे भविष्य की पीढ़ी के कैरियर के लिए यह काफी अलग रवैया है।
- वे ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो वे करना चाहते हैं बजाय उसके जो उनके आंतरिक आग्रह को संतुष्ट नहीं कर सकता है।

- यह व्यवसायों के लिए भी उपयुक्त है। गिग इकॉनमी में, वे भविष्य निधि, भुगतान छुट्टी, और कार्यालय स्थान जैसे लाभों के संदर्भ में संसाधनों की बचत करते हैं।

Q.7) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मूल्यहास (depreciation) के कारण होने वाले नुकसान की कटौती के बाद यह सकल घरेलू उत्पाद है।
2. किसी राष्ट्र की जनसंख्या से विभाजित NNP प्रति व्यक्ति आय देता है

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) solution (b)

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या NNP उन सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जो एक राष्ट्र के नागरिकों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जो एक वर्ष के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहते हैं।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) से मूल्यहास को घटाकर प्राप्त मूल्य के रूप में भी जाना जाता है।

किसी राष्ट्र के वास्तविक विकास को निर्धारित करने के लिए NNP महत्वपूर्ण मेट्रिक्स में से एक है। यह मापता है कि देश एक निश्चित अवधि में कितना उपभोग करने में सक्षम है।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है:

$$NNP = GNP - \text{मूल्यहास}$$

जब हम NNP को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय प्राप्त होती है।

Q.8) आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास (Economic growth and Economic Development) के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आर्थिक विकास एक मात्रात्मक अवधारणा है जबकि आर्थिक संवृद्धि एक गुणात्मक अवधारणा है।
2. आर्थिक विकास का अर्थ है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि जबकि आर्थिक संवृद्धि का अर्थ है जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर में सुधार।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.8) Solution (d)

आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) से तात्पर्य किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन (GNP) या प्रति व्यक्ति आय के वास्तविक उत्पादन में समय के साथ वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास (Economic Development) का तात्पर्य देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना में प्रगतिशील परिवर्तन के साथ-साथ आय, बचत और निवेश के मामले में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के उर्ध्व गति से है।

आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) सकल घरेलू उत्पाद के घटकों में से एक है जो – उपभोग, सरकारी खर्च, निवेश, शुद्ध निर्यात में क्रमिक वृद्धि से संबंधित है। जबकि आर्थिक विकास (Economic Development) मानव पूंजी सूचकांक के विकास, असमानता के आंकड़ों में कमी, और संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जो आम जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।

आर्थिक विकास एक मात्रात्मक अवधारणा है जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। इसमें HDI (मानव विकास सूचकांक), लिंग संबंधी सूचकांक (GDI), मानव गरीबी सूचकांक (HPI), शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर आदि शामिल हैं।

Q.9) निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिदृश्य पर लागू व्यवहार अर्थशास्त्र के नज सिद्धांत (Nudge Theory) का उदाहरण हो सकता है?

- 1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
- 2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- 3. स्वच्छ भारत मिशन

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Q.9) Solution (b)

नज सिद्धांत (Nudge theory) के अनुसार: सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार को बनाए रखने के लिए लोगों को अनुस्मारक और सकारात्मक सुदृढीकरण की आवश्यकता होती है।

व्यवहारिक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण का एक तरीका है जो आर्थिक निर्णय लेने की व्याख्या करने के लिए मानव व्यवहार में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को लागू करता है। वास्तव में, लोगों द्वारा किए गए निर्णय अक्सर शास्त्रीय अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों से

विचलित होते हैं। मानव व्यवहार के मनोविज्ञान पर आधारित, व्यवहारिक अर्थशास्त्र वांछनीय व्यवहार के प्रति लोगों को 'नज (Nudge)' करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

व्यवहारिक अर्थशास्त्र से अंतर्दृष्टि को नियोजित करने वाली कई भारतीय योजनाओं को सफलता मिली है। उदाहरण के लिए:

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना, गिव अप (एलपीजी सब्सिडी)।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) ने शौचालयों के निर्माण के अलावा व्यवहार में बदलाव पर जोर दिया है। इसने जानकारी दी गई है, शौचालयों के उपयोग को और अधिक आकर्षक बनाया है, लोगों से भावनात्मक अपील की गई है, नए सामाजिक मानदंडों पर जोर दिया है, सार्वजनिक रूप से मनाया गए स्वच्छता चैंपियन की शुरुआत, और स्वच्छता के बारे में गांधी की कुछ शिक्षाओं से सुधार परियोजना को प्रमुखता से जोड़ा गया है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल, बाल लिंगानुपात में गिरावट को दूर करने और लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसका केंद्रीय लक्ष्य लड़कियों को बोझ के रूप में देखने के बजाय उन्हें मनाने के पक्ष में एक सामाजिक मानदंड को बढ़ावा देना रहा है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग लोगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र को लागू नहीं करता है।

Q.10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिभार (Surcharge) भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) में जाता है और इसका उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
2. उपकर (Cess) भारत के समेकित कोष (Consolidated Fund) में जाता है और इसे किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (d)

केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया उपकर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा लगाया गया कर है। आम तौर पर, उपकर को तब तक लगाया रखा जाता है जब तक सरकार को उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल जाता है। उपकर भारत के समेकित कोष में जाता है लेकिन केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही खर्च किया जा सकता है।

अधिभार किसी भी कर पर लगने वाला एक शुल्क है, जो पहले से चुकाए गए कर पर लगाया जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क या कर है। मुख्य अधिभार व्यक्तिगत आयकर (उच्च आय स्लैब पर और सुपर रिच पर) और कॉर्पोरेट आयकर पर है। अधिभार भारत की समेकित निधि में जाता है और इसे किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया जा सकता है।

Q. 11) गरीबी शीर्ष गणना (Poverty Head Count) अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह उस जनसंख्या के अनुपात को मापता है जिसकी प्रति व्यक्ति आय आधिकारिक गरीबी रेखा से नीचे है।
2. यह गरीबी की गहराई और गंभीरता को इंगित करता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 11) Solution (a)

गरीबी शीर्ष गणना अनुपात उस जनसंख्या के अनुपात को मापता है जिसकी प्रति व्यक्ति आय/उपभोग व्यय आधिकारिक गरीबी रेखा से नीचे है या सरल शब्दों में, यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या को मापता है।

हेडकाउंट अनुपात एक सरल उपाय है। यह व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और कट-ऑफ बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जिसके नीचे लोगों को गरीब माना जाता है। यह गरीबी की गंभीरता को नहीं दर्शाता है।

गरीबी अंतर अनुपात (PGR) गरीबी की गहराई को इंगित करता है; PGR जितना अधिक होगा, गरीबों की स्थिति उतनी ही खराब होगी। जहां गरीब लोगों की संख्या गरीबी के प्रसार को इंगित करती है, वहीं PGR गहराई को इंगित करता है।

Q. 12) बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index - MPI) की गणना में संकेतक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?

1. पोषण (Nutrition)
2. व्यवसाय (Occupation)
3. खाना पकाने का ईंधन (Cooking fuel)
4. मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality)

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3 और 4

d) केवल 1 और 4

Q. 12) Solution (b)

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 100 से अधिक विकासशील देशों को कवर करने वाली तीव्र बहुआयामी गरीबी का एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना है।

यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में गंभीर अभावों को पकड़कर पारंपरिक मौद्रिक गरीबी उपायों को पूरा करता है, जिसका सामना व्यक्ति एक साथ करता है।

MPI की गणना प्रत्येक सर्वेक्षण किए गए परिवार को पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और घरेलू परिसंपत्तियों के आधार पर 10 मापदंडों पर स्कोर करके की जाती है।

नीति आयोग भारत में एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी है।

Q. 13) समावेशी विकास आर्थिक विकास है जो पूरे समाज में उचित रूप से वितरित किया जाता है और सभी के लिए अवसर पैदा करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन समावेशी विकास को बढ़ावा देगा?

1. कौशल निर्माण कार्यक्रम
2. स्वयं सहायता समूहों का निर्माण
3. विनिवेश
4. सुशासन

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये:

- a) केवल 2 और 3
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 3 और 4
- d) केवल 1, 2 और 4

Q. 13) Solution (d)

समावेशी विकास का अर्थ है आर्थिक विकास जो रोजगार के अवसर पैदा करता है और गरीबी को कम करने में मदद करता है। इसका अर्थ है गरीबों द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा में आवश्यक सेवाओं तक पहुंच होना। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना शामिल है।

कौशल-निर्माण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, सुशासन सभी अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे।

Q. 14) भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था?

1. रंगराजन समिति

2. हाशिम समिति
3. अभिजीत सेन समिति

उपरोक्त कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिये;

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 14) Solution (b)

रंगराजन समिति: योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 22 रुपये प्रतिदिन की गरीबी रेखा के सुझाव पर राष्ट्रीय आक्रोश की पृष्ठभूमि में समिति का गठन किया गया था।

उद्देश्य:

- अंतर्राष्ट्रीय गरीबी आकलन के तरीकों की समीक्षा करना और यह बताना कि क्या ये इन पर आधारित हैं; भारत में अनुभवजन्य गरीबी अनुमान के लिए एक विशेष विधि विकसित की जा सकती है।
- यह सिफारिश करने के लिए कि गरीबी के इन अनुमानों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता और हकदारियों से कैसे जोड़ा जा सकता है।

हाशिम समिति: शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग ने प्रोफेसर एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। हाशिम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए तीन चरणों की पहचान प्रक्रिया की सिफारिश की थी, जिसमें इस क्रम में शेष शहरी परिवारों का स्वतः बहिष्कार, स्वतः समावेश और स्कोरिंग सूचकांक शामिल है। अनुशासित कार्यप्रणाली मुख्य रूप से आवासीय, सामाजिक और व्यावसायिक कमजोरियों का निवारण करने पर जोर देती है।

अभिजीत सेन समिति: इसका गठन वायदा व्यापार और कृषि वस्तुओं की मुद्रास्फीति के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया गया था।

Q. 15) निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है:

1. लैंगिक असमानता सूचकांक
2. बहुआयामी गरीबी सूचकांक
3. वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक
4. असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये;

- a) केवल 2 और 3
- b) केवल 1, 2 और 4
- c) केवल 2, 3 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q. 15) Solution (b)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) प्रत्येक वर्ष पांच समग्र सूचकांक जारी करता है: मानव विकास सूचकांक (HDI), असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI), लैंगिक विकास सूचकांक (GDI), लैंगिक असमानता सूचकांक (GII), और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक सामाजिक आर्थिक सूचकांक है जिसे आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा के सापेक्ष पहुंच को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सूचकांक वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है।

Q. 16) निम्नलिखित पर विचार करें:

1. सामाजिक और आर्थिक असमानता
2. कम उपयोग किए गए संसाधन (Underutilized resources)
3. वित्तीय समावेशन
4. जनसंख्या विस्फोट

उपरोक्त में से किसे भारत में गरीबी का कारण माना जा सकता है?

- a) केवल 1, 2 और 4
- b) केवल 1, 2 और 3
- c) केवल 2, 3 और 4
- d) केवल 1, 3 और 4

Q. 16) Solution (a)

तेजी से बढ़ती जनसंख्या: भारत की जनसंख्या में वर्षों से तीव्र वृद्धि हुई है। पिछले 45 वर्षों के दौरान, यह प्रति वर्ष 2.2% की दर से बढ़ी है, जिसका अर्थ है, औसतन; प्रत्येक वर्ष देश की जनसंख्या में लगभग 17 मिलियन लोग जुड़ते हैं। इससे उपभोग की वस्तुओं की मांग भी अत्यधिक बढ़ी है।

कम उपयोग किए गए संसाधन: देश में, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में अल्परोजगार और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इससे कृषि उत्पादन कम हुआ है और जीवन स्तर में भी गिरावट आई है।

बेरोजगारी: बेरोजगारी भारत में गरीबी का एक अन्य कारक है। लगातार बढ़ती आबादी के कारण नौकरी चाहने वालों की संख्या अधिक हो गई है। हालांकि, रोजगार की इस मांग को पूरा करने के लिए अवसरों में पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है।

सामाजिक कारक: आर्थिक और वाणिज्यिक के अलावा, भारत में गरीबी उन्मूलन में बाधा डालने वाले सामाजिक कारक भी हैं। इस संबंध में कुछ बाधाएं विरासत, जाति व्यवस्था, कुछ परंपराओं आदि के नियम हैं।

वित्तीय समावेशन आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता को मजबूत करता है और गरीबों के बीच बचत की अवधारणा का निर्माण करता है। वित्तीय समावेशन समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह वंचित आबादी के समग्र आर्थिक विकास में मदद करता है।

Q. 17) लॉरेंज वक्र (Lorenz Curve) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक अर्थव्यवस्था में आय के वितरण का प्रतिनिधित्व करता है।
2. 60° कोणों पर रेखा पूरी तरह से समान आय वितरण दर्शाती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 17) Solution (a)

एक अर्थव्यवस्था में आय का वितरण लॉरेंज वक्र द्वारा दर्शाया जाता है।

लॉरेंज वक्र (आय वक्र का वास्तविक वितरण), मैक्स लॉरेंजिन 1906 द्वारा विकसित धन का एक चित्रमय वितरण, जनसंख्या के किसी भी प्रतिशत द्वारा अर्जित आय के अनुपात को दर्शाता है। 45° कोण पर रेखा पूरी तरह से समान आय वितरण को दर्शाती है, जबकि दूसरी रेखा आय के वास्तविक वितरण को दर्शाती है। विकर्ण से जितना दूर होगा, आय के वितरण का आकार उतना ही असमान होगा।

Q. 18) गिनी गुणांक (Gini coefficient) निम्नलिखित में से किस आर्थिक वक्र से प्राप्त होता है?

- a) लाफ़र वक्र (Laffer Curve)
- b) कुज़नेट वक्र (Kuznets curve)
- c) फिलिप्स वक्र (Phillips curve)
- d) लॉरेंज कर्व (Lorenz Curve)

Q. 18) Solution (d)

गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र से लिया गया है, जिसे किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

गिनी गुणांक जनसंख्या में आय समानता की डिग्री को मापता है।

गिनी गुणांक 0 (पूर्ण समानता) से 1 (पूर्ण असमानता) तक भिन्न हो सकता है।

शून्य के गिनी गुणांक का अर्थ है कि सभी की आय समान है, जबकि 1 का गुणांक सभी आय प्राप्त करने वाले एकल व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

Q. 19) एक ऐसी स्थिति जिसके तहत उच्च स्तर के कौशल वाले लोगों को कम उत्पादक नौकरियों में नियोजित किया जाता है, उसे कहते हैं:

- a) अल्प-रोजगार (Under Employment)
- b) अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary Unemployment)
- c) प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)
- d) प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment)

Q. 19) Solution (a)

अल्प-रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें उच्च स्तर के कौशल वाले लोगों को कम उत्पादक रोजगार में नियोजित किया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अर्थव्यवस्था की श्रम शक्ति का उनके कौशल और अनुभव के अनुसार पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है।

उदाहरण: इंजीनियरिंग या प्रबंधन की डिग्री वाला एक व्यक्ति जो किसी फर्म में क्लर्क या अकाउंटेंट के रूप में काम करता है या पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने वाला सामाजिक विज्ञान स्नातक।

Q.20) बेरोजगारी का आकलन करने के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सामान्य स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार के रूप में अनुमानित करता है जिनके पास एक दिन में 1 घंटे के लिए भी कोई लाभप्रद कार्य नहीं था।
2. साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार के रूप में दर्ज करता है जिनके पास सर्वेक्षण की तारीख से पहले साप्ताहिक के किसी भी दिन एक घंटे के लिए भी लाभप्रद कार्य नहीं था।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 20) Solution (b)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत एक संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर भारत में बेरोजगारी को मापता है:

सामान्य स्थिति दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार के रूप में अनुमानित करता है जिनके पास सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 365 दिनों के दौरान एक प्रमुख समय के लिए कोई लाभप्रद कार्य नहीं था।

साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार के रूप में दर्ज करता है जिनके पास सर्वेक्षण की तारीख से पहले सप्ताह के किसी भी दिन एक घंटे के लिए भी लाभप्रद कार्य नहीं था।

दैनिक स्थिति दृष्टिकोण: इस दृष्टिकोण के तहत, एक व्यक्ति की बेरोजगारी की स्थिति को एक संदर्भ सप्ताह में प्रत्येक दिन के लिए मापा जाता है। जिस व्यक्ति को दिन में 1 घंटा भी लाभकारी काम नहीं मिलता है, उसे उस दिन के लिए बेरोजगार कहा जाता है।

Q. 21) ओपन मार्केट ऑपरेशंस/ खुला बाज़ार संचालन (Open Market Operations) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बाजार में रुपये की तरलता की स्थिति को समायोजित करने के लिए आरबीआई का एक मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण है।
2. जब बाजार में अतिरिक्त तरलता होती है तो आरबीआई खुले बाजार के संचालन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 21) Solution (a)

ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या ओएमओ (OMOs), मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री है।

ओएमओ का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति या मौजूदा तरलता को नियंत्रित करना है। मुद्रास्फीति की स्थिति के मामले में, आरबीआई एक संकुचित मौद्रिक नीति अपनाता है, यानी यह सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है और वित्तीय प्रवाह से अतिरिक्त धन को अवशोषित करता है।

मंदी की प्रवृत्ति के बीच, आरबीआई बाजार में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ावा देने तथा निवेश और उत्पादन के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु द्रुतगामी है। इसलिए, यह प्रतिभूतियों को खरीदता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है।

Q. 22) जी-एसएपी (G-SAP) क्या है, जो कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है?

- a) यह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर बाजार में अधिक तरलता डालने का एक कार्यक्रम है।
- b) यह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर बाजार में मुद्रा आपूर्ति को कम करने का एक कार्यक्रम है।
- c) यह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बाजार में मुद्रा आपूर्ति को कम करने का एक कार्यक्रम है।
- d) यह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बाजार में अधिक तरलता डालने का एक कार्यक्रम है।

Q. 22) Solution (d)

जी-एसएपी (G-SAP), का अर्थ सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम है। यह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बाजार में अधिक तरलता डालने का एक कार्यक्रम है। यह आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस का हिस्सा है।

आरबीआई समय-समय पर खुले बाजार संचालन (ओएमओ) के माध्यम से बाजार से सरकारी बांड खरीदता है। जी-एसएपी एक तरह से ओएमओ है लेकिन केंद्रीय बैंक द्वारा बाजारों के लिए एक अग्रिम प्रतिबद्धता है कि वह एक विशिष्ट राशि के बांड खरीदेगा। इसका मकसद बॉन्ड बाजारों को सुविधा देना है। दूसरे शब्दों में, G-SAP एक 'विशिष्ट चरित्र' वाला ओएमओ (OMO) है।

Q. 23) भारत सरकार के अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें RBI से पैसा उधार ले सकती हैं।
2. यह केन्द्रीय बैंक द्वारा एक अस्थायी तरलता व्यवस्था है।
3. इस सुविधा के तहत केंद्र और राज्य आरबीआई से 120 दिनों तक के लिए पैसा उधार ले सकते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 23) Solution (a)

अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances) केंद्र और राज्यों दोनों के लिए RBI से उधार लेने की सुविधा है। ये उधार विशुद्ध रूप से उनकी प्राप्तियों और व्यय के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन से निपटने में मदद करने के लिए हैं।

केंद्रीय बैंक केंद्र और राज्य सरकारों को उनके पुनर्भुगतान के अधीन धन उधार देता है जो "अग्रिम देने की तारीख से तीन महीने के बाद नहीं" हो। इस प्रकार केंद्र और राज्य अपनी तरलता असंतुलन से निपटने के लिए आरबीआई से 90 दिनों तक के लिए धन उधार ले सकते हैं।

अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज दर RBI की रेपो दर होती है, जो मूल रूप से वह दर है जिस पर वह बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।

Q. 24) जब अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances) की सीमा जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं, को पार कर जाता है, सरकारें आरबीआई की ओवरड्राफ्ट सुविधा का सहारा लेती हैं। इस ओवरड्राफ्ट सुविधा पर ब्याज दर कितनी होती है?

- a) रेपो दर से 4 प्रतिशत अधिक

- b) रेपो दर से 2 प्रतिशत अधिक
- c) बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक
- d) बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक

Q. 24) Solution (b)

जब अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं केंद्र और राज्य सरकारों पार कर जाती हैं तो आरबीआई की ओवरड्राफ्ट सुविधा का सहारा लेती हैं। ओवरड्राफ्ट सुविधा पर ब्याज दर रेपो दर से 2 प्रतिशत अधिक होती है।

आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इसने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई ओवरड्राफ्ट सुविधा के लाभ को नियंत्रित करने वाली शर्तों में ढील दी है, ताकि वे अपने नकदी प्रवाह और बाजार उधारी के संदर्भ में अपनी वित्तीय स्थिति का बेहतर प्रबंधन कर सकें। तदनुसार, एक तिमाही में अधिकतम दिन जिन पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें 36 दिनों से बढ़ाकर 50 दिन किया जा रहा है। इसके अलावा, लगातार दिनों की संख्या जिस पर एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकता है, उसे 14 दिनों से बढ़ाकर 21 दिन किया जा रहा है। यह सुविधा 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी।

Q. 25) मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित किया गया है।
2. आरबीआई के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
3. आरबीआई गवर्नर के पास पैनल के अन्य सदस्यों को खारिज करने की वीटो शक्ति होती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 25) Solution (b)

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित मौद्रिक नीति समिति (MPC), मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात जैसी मौद्रिक नीति दरों को निर्धारित करती है।

समिति में छह सदस्य शामिल हैं - भारतीय रिजर्व बैंक के तीन अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य। आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।

मौद्रिक नीति पर निर्णय लेने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले उर्जित पटेल समिति ने रखा था।

आरबीआई गवर्नर समिति की अध्यक्षता करते हैं लेकिन अन्य पैनल सदस्यों को खारिज करने के लिए वीटो पावर का लाभ नहीं लेते हैं, लेकिन टाई या बराबर मत के मामले में एक निर्णायक वोट देते हैं।

Q. 26) नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह बैंकों द्वारा बैंक की कुल जमा राशियों के संबंध में रिजर्व में रखी जाने वाली नकदी का प्रतिशत है।
2. यह कैश रिजर्व या तो बैंक की तिजोरी में जमा होता है या आरबीआई को भेजा जा सकता है।
3. सीआरआर आवश्यकताओं के तहत आरबीआई के पास मौजूद धन पर बैंकों को 1% का ब्याज मिलता है।
4. मुद्रास्फीति के समय आरबीआई सीआरआर को घटाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3 और 4
- d) केवल 1 और 4

Q. 26) Solution (a)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का आदेश है कि बैंक अपनी जमा राशि का एक हिस्सा नकदी के रूप में जमा करें ताकि जरूरत पड़ने पर बैंक के ग्राहकों को इसे दिया जा सके। किसी बैंक की कुल जमा राशियों की तुलना में आरक्षित निधि में रखे जाने के लिए आवश्यक नकदी का प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है।

कैश रिजर्व या तो बैंक की तिजोरी में जमा होता है या आरबीआई को भेजा जाता है। सीआरआर आवश्यकताओं के तहत आरबीआई के पास मौजूद धन पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है।

वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर के विपरीत, जिसे सोने या नकदी में बनाए रखा जा सकता है, सीआरआर को केवल नकदी में बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

नकद आरक्षित अनुपात के दो प्राथमिक उद्देश्य हैं:

- चूंकि बैंक की जमा राशि का एक हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, यह राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जब ग्राहक अपनी जमा राशि वापस चाहते हैं तो यह इसे आसानी से उपलब्ध कराता है।
- साथ ही सीआरआर मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के समय, आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है, ताकि बैंकों को अधिक धन रिजर्व में रखने की आवश्यकता हो ताकि उनके पास आगे उधार देने के लिए कम पैसा हो।

उच्च मुद्रास्फीति के समय, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन उपलब्ध न हो। उस सीमा तक, RBI नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ाता है, और बैंकों के पास उपलब्ध धन की मात्रा कम हो जाती है। यह अर्थव्यवस्था में धन के अतिरिक्त प्रवाह को रोकता है।

Q. 27) सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility-MSF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक ऐसी खिड़की है जो वाणिज्यिक बैंकों को आपात स्थिति में आरबीआई से पैसा उधार लेने में सक्षम बनाती है।
2. एमएसएफ आमतौर पर रेपो दर से अधिक होता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 27) Solution (b)

MSF या सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर वह दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के सापेक्ष अनुसूचित बैंकों को रातोंरात के लिए धन उधार देता है। आरबीआई ने इस उधार योजना को अल्पकालिक परिसंपत्ति देयता असंतुलन को अधिक प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए प्रस्तुत किया है।

तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को रेपो दर से अधिक दर पर गिरवी रखकर आरबीआई से उधार लेते हैं।

एमएसएफ मूल रूप से अधिक तरलता कुशन (cushion) प्रदान करता है। एमएसएफ दर जितनी अधिक होगी, बैंकों के साथ-साथ कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं और व्यक्तियों के लिए उधार लेना अधिक महंगा होगा। इसका उपयोग RBI द्वारा देश की वित्तीय प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

Q. 28) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए:

1. बचत खाते में जमा धन
2. चालू खाते में जमा धन
3. बैंकों में जमा सोना
4. सावधि जमा धन

उपरोक्त में से कौन बैंक की सावधि देनदारियां (time liabilities) हैं?

- a) केवल 1 और 2

- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3 और 4
- d) केवल 1 और 4

Q. 28) Solution (c)

एक बैंक की जमा उसकी देनदारियां हैं जो मांग देयता, समय देयता और अन्य मांग और समय देनदारियों के रूप में हो सकती हैं।

मांग देयताएं: मांग देनदारियों में बैंक की वे सभी देनदारियां शामिल होती हैं जो मांग पर देय होती हैं। जैसे बचत खाते में जमा धन, चालू खाते में जमा धन, नकद प्रमाण पत्र और संचयी/आवर्ती जमा, आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट/गारंटी पत्र के सापेक्ष मार्जिन, नकद क्रेडिट खाते में क्रेडिट शेष, आदि सभी मांग पर अदा की जाती है।

सावधि देयताएं: सावधि देयताएं किसी बैंक की वे देयताएं हैं जो अन्यथा मांग जैसे किसी निश्चित समय पर देय होती हैं। इनमें सावधि जमा धन, कर्मचारी सुरक्षा जमा, बचत जमा खाते का समय देयता हिस्सा, ऋण पत्र के सापेक्ष रखा गया मार्जिन (यदि मांग पर देय नहीं है), जमा सोना, आदि शामिल हैं।

अन्य मांग और समय देयताएं: इनमें वे सभी विविध देनदारियां शामिल हैं जो उपरोक्त दो प्रकार की देनदारियों में शामिल नहीं हैं। जैसे जमाराशियों पर अर्जित ब्याज, अवैतनिक लाभांश, अन्य बैंकों या जनता को देय राशि को दर्शाने वाले सस्पेंस अकाउंट या संदेही खाते की शेष राशि, अन्य बैंकों को जारी भागीदारी प्रमाण पत्र, नकद संपार्श्विक, आदि।

Q. 29) बैंक दर (Bank Rate) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह बाजार में धन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का एक अल्पकालिक मौद्रिक नीति उपाय है।
2. बैंक दर आमतौर पर रेपो दर से कम होती है।
3. बैंक दर में वृद्धि सीधे ग्राहक को दी जाने वाली उधार दरों को प्रभावित करती है, लोगों को ऋण लेने के लिए प्रतिबंधित करती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q. 29) Solution (c)

बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज की दर को "बैंक दर" कहा जाता है। इस मामले में, कोई पुनर्खरीद समझौता हस्ताक्षरित नहीं होता है, कोई प्रतिभूतियां नहीं बेची गई या संपार्श्विक शामिल नहीं होती है।

बैंक दर एक दीर्घकालिक उपाय है और यह आरबीआई की दीर्घकालिक मौद्रिक नीतियों (long-term monetary policies) द्वारा नियंत्रित होता है।

बैंक केंद्रीय बैंक से बैंक दर पर धन उधार लेते हैं और अपने ग्राहकों को उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार देते हैं, जिससे मुनाफा होता है। बैंक दर आमतौर पर रेपो दर से अधिक होती है क्योंकि यह तरलता को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

बैंक दर में वृद्धि सीधे ग्राहक को दी जाने वाली उधार दरों को प्रभावित करती है, लोगों को ऋण लेने के लिए प्रतिबंधित करती है और समग्र आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाती है।

Q.30) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए:

1. मार्जिन/सीमांत आवश्यकताएं (Margin requirements)
2. नैतिक अभिप्रेरण/ दबाव (Moral suasion)
3. चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण (Selective credit control)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है/हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 30) Solution (d)

गुणात्मक उपकरणों को आरबीआई की मौद्रिक नीति के चुनिंदा उपकरणों के रूप में भी जाना जाता है। इन उपकरणों का उपयोग क्रेडिट के विभिन्न उपयोगों के बीच विभेद करने के लिए किया जाता है; उदाहरण के लिए, उनका उपयोग आयात पर निर्यात के पक्ष में या गैर-आवश्यक ऋण आपूर्ति पर आवश्यक ऋण आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। इस पद्धति का उधारकर्ताओं और उधारदाताओं दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

- सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन: मार्जिन ऋण राशि के निश्चित अनुपात को संदर्भित करता है जो बैंक द्वारा पेश या वित्तपोषित नहीं किया जाता है। सीमांत में परिवर्तन से ऋण के आकार में परिवर्तन हो सकता है। इस उपकरण का उपयोग आवश्यक क्षेत्रों के लिए ऋण आपूर्ति को प्रोत्साहित करने और अनावश्यक क्षेत्रों के लिए इससे बचने के लिए किया जाता है। यह अनावश्यक क्षेत्रों के सीमांत को बढ़ाकर और अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों के सीमांत को कम करके किया जा सकता है।
- नैतिक अभिप्रेरण: नैतिक दबाव का मतलब आरबीआई के वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए सुझावों से है जो मुद्रास्फीति की अवधि में क्रेडिट को नियंत्रित करने में मदद करता है। आरबीआई नियमों के अनुपालन के लिए कोई सख्त कार्रवाई किए बिना भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डालता है।

- उपभोक्ता साख का नियमन: इस साधन/उपकरण में, उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री और किराया खरीद की किस्त के माध्यम से उपभोक्ताओं की ऋण आपूर्ति को विनियमित किया जाता है। यहां, किस्त राशि, डाउन पेमेंट, ऋण अवधि आदि जैसी सुविधाएं अग्रिम रूप से तय की जाती हैं, जो देश में क्रेडिट और मुद्रास्फीति की जांच करने में मदद करती हैं।

Q. 31) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए:

- सरकारी व्यय में वृद्धि
- मजदूरी में वृद्धि
- उच्चतर कर
- निर्यात में वृद्धि

अर्थव्यवस्था में मांगजनित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation) के लिए उपरोक्त में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं??

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 3 और 4
- केवल 1 और 4

Q. 31) Solution (d)

मुद्रास्फीति का अर्थ है सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। मुद्रास्फीति के मुख्य दो प्रकार हैं:

- मांगजनित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation)
- लागतजनित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation)

मांगजनित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की वह अवधि है जो समग्र मांग में तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। यह तब होता है जब आर्थिक विकास बहुत तेज होता है।

मांगजनित मुद्रास्फीति का अर्थ है:

- अधिक मांग और 'बहुत कम वस्तुओं का पीछा करते हुए बहुत अधिक धन'।
- अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार/पूर्ण क्षमता पर (या अत्यंत निकट) है।
- अर्थव्यवस्था लंबी अवधि की प्रवृत्ति दर की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।
- गिरती बेरोजगारी दर।

मांगजनित मुद्रास्फीति के कारण हैं:

- उपभोग और निवेश में अत्याधिक विश्वासपूर्ण फर्मों के साथ त्वरित वृद्धि हो रही है।

- मुद्रा के अत्यधिक निम्न मूल्यांकन के कारण निर्यात में अचानक वृद्धि हुई है।
- सरकारी व्यय बहुत अधिक है।
- मुद्रास्फीति में वृद्धि की उम्मीद अक्सर मुद्रास्फीति में वृद्धि की ओर ले जाती है। श्रमिक और फर्म अपनी कीमतें बढ़ाकर मुद्रास्फीति की ओर ले जाएंगे।
- अत्यधिक मौद्रिक वृद्धि होती है, जब बहुत कम वस्तुओं का पीछा करते हुए प्रणाली में बहुत अधिक धन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु की 'कीमत' बढ़ जाती है।
- जनसंख्या में वृद्धि हुई हो।

Q. 32) धीमी वृद्धि और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी की विशेषता वाली अर्थव्यवस्था में स्थिति जो एक ही समय में बढ़ती कीमतों के साथ होती है, कहलाती है:

- a) स्कीवफ्लेशन (Skewflation)
- b) मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation)
- c) अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति (Hyperflation)
- d) दौड़ती मुद्रास्फीति (Running inflation)

Q. 32) Solution (b)

मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation) की विशेषता धीमी आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी-या आर्थिक स्थिरता है- जो एक ही समय में बढ़ती कीमतों (यानी मुद्रास्फीति) के साथ होती है। स्टैगफ्लेशन को वैकल्पिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के साथ संयुक्त मुद्रास्फीति की अवधि के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

मुद्रास्फीतिजनित मंदी के कारण हैं:

- तेल की कीमतों में वृद्धि स्टैगफ्लेशन, अक्सर आपूर्ति पक्ष शॉक के कारण होता है। उदाहरण के लिए, बढ़ती कमोडिटी की कीमतें, जैसे कि तेल की कीमतें, व्यावसायिक लागतों में वृद्धि का कारण बनेंगी (परिवहन अधिक महंगा) और अल्पकालिक कुल आपूर्ति बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगी। यह उच्च मुद्रास्फीति दर और कम जीडीपी का कारण बनता है।
- गिरती उत्पादकता, यदि कोई अर्थव्यवस्था गिरती उत्पादकता का अनुभव करती है - श्रमिक अधिक अक्षम होते जा रहे हैं; लागत बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा।
- संरचनात्मक बेरोजगारी में वृद्धि, यदि पारंपरिक उद्योगों में गिरावट आती है, तो हमें अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी और कम उत्पादन मिल सकता है। इस प्रकार हम उच्च बेरोजगारी प्राप्त कर सकते हैं - भले ही मुद्रास्फीति भी बढ़ रही हो।

Q. 33) मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक लक्ष्य के रूप में मुद्रास्फीति दर को निर्दिष्ट करने और उस दर को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को समायोजित करने की रणनीति है।
2. भारत में, हर पांच साल में एक बार आरबीआई के परामर्श से सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

3. वर्तमान में भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्य $\pm 2\%$ के टालरेंस बैंड (tolerance band) के साथ 5% है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 33) Solution (a)

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण केंद्रीय बैंक की एक लक्ष्य के रूप में मुद्रास्फीति दर को निर्दिष्ट करने और उस दर को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को समायोजित करने की एक रणनीति है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण मुख्य रूप से मूल्य स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित है, लेकिन यह भी माना जाता है कि यह आर्थिक विकास और स्थिरता का समर्थन करता है।

आरबीआई और सरकार ने 2015 में एक नीतिगत ढांचे पर सहमति व्यक्त की, जिसमें विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित किया गया था।

मई 2016 में, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया था। अधिनियम केंद्र को हर पांच साल में एक बार आरबीआई के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति देता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1924 के तहत 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य को उसी स्तर पर रखा गया है, जो पिछले पांच वर्षों के लिए था, जो $\pm 2\%$ के टालरेंस बैंड (tolerance band) के साथ 4% है।

Q. 34) अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उधारदाताओं को नुकसान होता है जबकि उधारकर्ताओं को मुद्रास्फीति से लाभ होता है।
2. अल्पावधि में अर्थव्यवस्था में निवेश मुद्रास्फीति द्वारा बढ़ाया जाता है।
3. बढ़ती महंगाई के साथ मुद्रा का मूल्य बढ़ता है।
4. मुद्रास्फीति के साथ, एक अर्थव्यवस्था की निर्यात योग्य वस्तुओं को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1, 2 और 3
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 2 और 4

d) 1, 2, 3 और 4

Q. 34) Solution (c)

अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के बहुआयामी प्रभाव व्यक्ति और समष्टि (micro and macro) दोनों स्तरों पर होते हैं। यह आय का पुनर्वितरण करता है, सापेक्ष कीमतों को विकृत करता है, रोजगार, कर, बचत और निवेश नीतियों को अस्थिर करता है और यह अर्थव्यवस्था में मंदी और महामंदी (depression) ला सकता है। मुद्रास्फीति के प्रभावों को इस प्रकार देखा जा सकता है:

1. लेनदारों और देनदारों पर: मुद्रास्फीति लेनदारों से देनदारों को धन का पुनर्वितरण करती है, यानी उधारदाताओं को नुकसान होता है जबकि उधारकर्ता मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। विपरीत प्रभाव तब होता है जब मुद्रास्फीति गिरती है।

2. निवेश पर: अल्पावधि में मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिलता है क्योंकि:

- उच्च मुद्रास्फीति उच्च मांग को इंगित करती है और उद्यमियों को अपने उत्पादन स्तर का विस्तार करने का सुझाव देती है।
- मुद्रास्फीति जितनी अधिक होगी, ऋण की लागत उतनी ही कम होगी।

3. बचत पर: मुद्रा रखना एक बुद्धिमान आर्थिक निर्णय नहीं रहता है क्योंकि मुद्रा मुद्रास्फीति में हर वृद्धि के साथ मूल्य खो देती है, यही कारण है कि लोग अधिक बार बैंकों का दौरा करते हैं और अपने पास कम से कम पैसा रखने की कोशिश करते हैं और बैंकों के साथ अपने बचत खातों में अधिकतम पैसे डालते हैं।

4. निर्यात पर: मुद्रास्फीति के साथ, एक अर्थव्यवस्था की निर्यात योग्य वस्तुओं को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त होते हैं। इसके कारण, निर्यात की मात्रा बढ़ जाती है (हालांकि निर्यात का मूल्य घटता है) और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में निर्यात आय में वृद्धि होती है।

Q. 35) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सीपीआई में, मुद्रास्फीति को लेनदेन के पहले चरण में भुगतान की गई कीमत को ट्रैक करके मापा जाता है जबकि लेनदेन के अंतिम चरण में भुगतान की गई कीमत का उपयोग डब्ल्यूपीआई में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है।
2. सीपीआई बास्केट में वस्तुओं की एकमात्र कीमत शामिल होती है, जबकि डब्ल्यूपीआई बास्केट में आवास शिक्षा, मनोरंजन जैसी सेवाएं भी वस्तुओं के साथ शामिल होती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 35) Solution (d)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई): एक अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय के प्रतिनिधि वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी/बास्केट में मूल्य परिवर्तन के आकलन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक उपाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) कहलाता है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI): इसे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मूल्य सूचकांक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो बड़े पैमाने पर बिक्री के लिए वस्तु के मूल्य परिवर्तन को मापता है, अर्थात् लेन-देन के प्रारंभिक चरण में, जब माल एक निगम द्वारा दूसरे से पुनर्विक्रय के लिए खरीदा जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के बीच अंतर की चर्चा नीचे दिए गए बिंदुओं में की गई है:

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) निर्माताओं से थोक विक्रेताओं द्वारा वस्तु की खरीद पर भुगतान की गई कीमत का पता लगाकर और आधार वर्ष की कीमतों के साथ तुलना करके मुद्रास्फीति का अनुमान लगाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के मुकाबले कीमतों में बदलाव को मापने के लिए, समय के माध्यम से, वस्तुओं की स्थिर टोकरी की समग्र कीमत की तुलना करके किया जाता है।
- भारत में, थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके विपरीत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा घोषित किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है।
- थोक मूल्य सूचकांक में, लेनदेन के पहले चरण में भुगतान की गई कीमत को ट्रैक करके मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसके विपरीत, लेन-देन के अंतिम चरण में भुगतान की गई कीमत का उपयोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है।
- WPI बास्केट में केवल वस्तु की कीमत शामिल होती है, जबकि आवास शिक्षा, मनोरंजन आदि जैसी सेवाएं भी माल के साथ CPI टोकरी में शामिल होती हैं।
- WPI पुनर्विक्रय के उद्देश्य से दो व्यावसायिक घरानों के बीच वस्तु के व्यापार पर भुगतान की गई कीमतों से संबंधित है। इसके विपरीत, सीपीआई उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के उद्देश्य से खरीदे गए वस्तुओं की कीमतों पर जोर देता है।

Q. 36) किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगातार दो तिमाहियों में गिरावट को कहा जाता है:

- a) स्लोडाउन/ सुस्त (Slowdown)
- b) डिप्रेशन (Depression)
- c) रिसेशन/ मंदी (Recession)
- d) स्टैगनेशन (Stagnation)

Q. 36) Solution (c)

एक आर्थिक मंदी को अक्सर दो लगातार तिमाहियों के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है।

आर्थिक मंदी की ओर जाता है:

- वास्तविक जीडीपी में गिरावट
- वास्तविक आय में गिरावट
- बेरोजगारी में वृद्धि
- धीमा औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री
- उपभोक्ता व्यय की कमी

मंदी से निपटने के लिए, अर्थव्यवस्थाएं आम तौर पर अपनी मौद्रिक नीतियों को सिस्टम में अधिक पैसा डालकर, यानी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करके प्रतिक्रिया करती हैं।

यह व्याज दरों को कम करके किया जाता है। सरकार द्वारा खर्च में वृद्धि और कराधान में कमी।

Q. 37) आर्थिक सुधार के संदर्भ में, वह स्थिति जब कोई अर्थव्यवस्था मंदी से उबरती है और फिर तुरंत दूसरी मंदी में बदल जाती है, कहलाती है:

- a) वी-आकार की रिकवरी
- b) के-आकार की रिकवरी
- c) डब्ल्यू-आकार की रिकवरी
- d) जेड-आकार की रिकवरी

Q. 37) Solution (c)

डब्ल्यू-आकार की रिकवरी तब होती है जब आर्थिक विकास गिरता है और बढ़ता है, लेकिन रिकवरी होने से पहले फिर से गिर जाता है।

डब्ल्यू-आकार की रिकवरी आम तौर पर अन्य प्रकार की रिकवरी की तुलना में अत्यधिक अस्थिरता की अवधि को दर्शाती है।

डब्ल्यू-आकार की मंदी, V-आकार की मंदी की तरह शुरू होती है, लेकिन फिर रिकवरी के अवास्तविक संकेत दिखाने के बाद फिर से नीचे आ जाती है।

डब्ल्यू-आकार की मंदी को "डबल-डिप मंदी/रिशोसन" (double-dip recessions) भी कहा जाता है क्योंकि पूर्ण रिकवरी प्राप्त होने से पहले अर्थव्यवस्था दो बार गिरती है।

Q. 38) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. एक एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता है।
2. सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को आरबीआई के साथ पंजीकरण की वैधानिक आवश्यकता से छूट दी गई है।

3. एनबीएफसी अपने ग्राहकों को चेक जारी नहीं कर सकती हैं।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 38) Solution (b)

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' को परिभाषित करता है-

- i. एक वित्तीय संस्थान जो एक कंपनी है;
- ii. एक गैर-बैंकिंग संस्था जो एक कंपनी है और जिसका मुख्य व्यवसाय किसी योजना या व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से जमा प्राप्त करना या किसी भी तरीके से उधार देना है;
- iii. ऐसी अन्य गैर-बैंकिंग संस्था या ऐसे संस्थानों का वर्ग, जैसा कि बैंक, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें।

एक एनबीएफसी बचत और चालू खातों की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता है।

सभी एनबीएफसी को आरबीआई के साथ पंजीकरण की आवश्यकता है, भले ही वे सार्वजनिक जमा स्वीकार करते हों या नहीं। हालांकि, कुछ प्रकार की वित्तीय कंपनियां जैसे बीमा कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां, चिट फंड कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 620 ए के तहत 'निधि' के रूप में अधिसूचित कंपनियां और मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधियों में लगी कंपनियां (कुछ शर्तों के अधीन), को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है।

एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं और इसलिए अपने ग्राहकों को चेक जारी नहीं कर सकते हैं।

Q. 39) पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. यह जोखिम भारित परिसंपत्तियों और चालू देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात है।
- 2. भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 12% की सीएआर बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- 3. बेसल III मानदंड 8% की जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के लिए पूंजी निर्धारित करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 39) Solution (c)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) एक बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के संबंध में अनुपात है। वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त लीवरेज लेने और प्रक्रिया में दिवालिया होने से रोकने के लिए केंद्रीय बैंकों और बैंक नियामकों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है।

इसे इस प्रकार मापा जाता है:

पूंजी पर्याप्तता अनुपात = (टियर I + टियर II + टियर III (पूंजीगत निधि)) / जोखिम भारित परिसंपत्तियां

जोखिम भारित परिसंपत्तियां क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को ध्यान में रखती हैं।

बेसल III मानदंड 8% की जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के लिए पूंजी निर्धारित करते हैं।

हालांकि, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 9% की सीएआर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जबकि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 12% की सीएआर बनाए रखने पर जोर दिया जाता है।

Q.40) मौद्रिक समुच्चय जिसमें प्रचलन में मुद्रा शामिल होती है + आरबीआई के साथ बैंक की जमा राशियां + आरबीआई के साथ अन्य जमा राशियां को कहा जाता है:

- a) रिजर्व मनी / आरक्षित मुद्रा
- b) नैरो (संकीर्ण) धन
- c) ब्रॉड मनी (Broad Money)
- d) नियर मनी (Near Money)

Q. 40) Solution (a)

मौद्रिक समुच्चय मुद्रा की व्यापक श्रेणियां हैं जो मुद्रा आपूर्ति को मापते हैं जैसे कि नकद और मांग जमा या बैंक क्रेडिट जिनका समग्र आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है। मौद्रिक समुच्चय का मूल्यांकन किसी देश की वित्तीय स्थिरता और समग्र स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारी उत्पन्न कर सकता है।

भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक M0, M1, M2, M3 और M4 मौद्रिक समुच्चय का अनुसरण करता है, जिन्हें क्रमशः 'रिजर्व मनी', 'नैरो मनी', 'नियर मनी', 'ब्रॉड मनी' और 'ब्रॉडर मनी' के रूप में जाना जाता है।

1. रिजर्व मनी (M0): रिजर्व मनी (M0) के घटक हैं- प्रचलन में मुद्रा + आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि + आरबीआई के साथ 'अन्य' जमाएं।
2. नैरो मनी (M1): नैरो मनी के घटक हैं- करेंसी इन सर्कुलेशन/ संचलन में मुद्राएं + बैंकिंग सिस्टम के साथ मांग जमाएं + RBI के पास 'अन्य' जमाएं।

3. नियर मनी (M2): 'नियर मनी' के घटक हैं- जनता के पास मुद्रा + बैंकों के पास जमाएं + रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाएं + डाकघर में बचत जमाएं।
4. ब्रॉड मनी (एम 3): ब्रॉड मनी (एम 3) के घटक हैं- जनता के पास मुद्रा + बैंकों के पास मांग जमा + बैंकों के साथ सावधि जमा + रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा।
5. ब्रॉडर मनी (M4): सबसे 'ब्रॉडर मनी' (M4) के घटक हैं- जनता के पास मुद्रा + बैंकों के पास मांग जमा + बैंकों के पास सावधि जमा + रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाएं + मुद्रा बाजार साधन।

Q. 41) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अर्थव्यवस्था को प्रबंधित या प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला व्यक्ति अर्थशास्त्रीय साधन (microeconomic tool) है।
2. यह ब्याज दरों और प्रचलन में मुद्रा की आपूर्ति को संबोधित करता है।
3. यह आम तौर पर सरकारी विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 41) Solution (c)

मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति देश की आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त साधनों/उपकरणों को संदर्भित करती है। मौद्रिक नीति मुख्य रूप से ब्याज दरों के प्रबंधन और प्रचलन में मुद्रा की कुल आपूर्ति से संबंधित है और आम तौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा की जाती है। भारत में, मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के अधीन है। मौद्रिक नीति प्रमुख रूप से मुद्रा और ब्याज दरों से संबंधित है। दूसरी ओर, राजकोषीय नीति के तहत, सरकार केंद्र द्वारा कराधान और खर्च से संबंधित है।

राजकोषीय नीति के माध्यम से, किसी देश की सरकार अर्थव्यवस्था संचालन के लिए कर राजस्व और सार्वजनिक व्यय के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यदि सरकार को खर्च से अधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो वह अधिशेष होता है, जबकि यदि वह कर और गैर-कर प्राप्तियों से अधिक खर्च करती है, तो वह घाटा होता है। अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, सरकार को घरेलू या विदेशों से उधार लेने की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक रूप से, सरकार अपने विदेशी मुद्रा भंडार को आकर्षित करने या अतिरिक्त धन प्रिंट करने का विकल्प भी चुन सकती है।

मौद्रिक और राजकोषीय नीति दोनों ही समष्टि अर्थशास्त्रीय उपकरण हैं जिनका उपयोग अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने या प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

मौद्रिक नीति ब्याज दरों और प्रचलन में मुद्रा की आपूर्ति को संबोधित करती है, और इसे आम तौर पर एक केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

राजकोषीय नीति कराधान और सरकारी खर्च को संबोधित करती है, और यह आम तौर पर सरकारी कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है।

Q. 42) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए:

1. कल्याणकारी कार्यक्रम
2. खुला बाजार परिचालन
3. सब्सिडी
4. कर लगाना

उपरोक्त में से कौन राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) के उपकरण हैं?

- a) केवल 1, 2 और 3
- b) केवल 1, 3 और 4
- c) केवल 2, 3 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q. 42) Solution (b)

राजकोषीय नीति के तहत सरकार के पास दो उपकरण होते हैं - कराधान और सार्वजनिक खर्च।

कराधान में आय, संपत्ति, बिक्री और निवेश पर कर शामिल हैं। एक ओर जहां अधिक करों का अर्थ सरकार के लिए अधिक आय है, वहीं इससे लोगों के हाथ में आय कम भी होती है।

सार्वजनिक खर्च में सब्सिडी, हस्तांतरण भुगतान, जैसे सरकार को वेतन कर्मचारी, कल्याण कार्यक्रम और लोक निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। जिन लोगों को धन मिलता है उनके पास खर्च करने के लिए अधिक धन होता है।

ओपन मार्केट ऑपरेशंस (Open Market Operations) तब होते हैं जब केंद्रीय बैंक सिक्योरिटीज/ प्रतिभूतियाँ खरीदती या बेचती है। इन्हें देश के निजी बैंकों से खरीदा या बेचा जाता है। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है, तो वह बैंकों के भंडार में नकदी जोड़ता है। इससे उन्हें उधार देने के लिए और धन मिलते हैं। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है, तो वह उन्हें बैंकों की बैलेंस शीट पर रखता है और अपनी नकदी होल्डिंग को कम करता है। इस प्रकार यह मौद्रिक नीति का एक उपकरण है।

Q. 43) राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह तब होता है जब एक वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व और गैर-राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है।
2. इसकी गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 43) Solution (a)

राजकोषीय घाटे की परिभाषा:

राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय (कुल करों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों) और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है। इस अंतर की गणना निरपेक्ष रूप से और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में भी की जाती है। एक आवर्ती उच्च राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार अपने धन से अधिक खर्च कर रही है।

सरकार भारत के राजकोषीय घाटे को "एक वित्तीय वर्ष के दौरान कोष में कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) से अधिक, ऋण के पुनरागमन को छोड़कर, भारत के समेकित कोष से कुल संवितरण की अधिकता" के रूप में वर्णित करती है।

राजकोषीय घाटा फॉर्मूला: राजकोषीय घाटे की गणना कैसे की जाती है?

राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय (पूंजीगत और राजस्व व्यय) – सरकार की कुल आय (राजस्व प्राप्तियां + ऋण की वसूली + अन्य प्राप्तियां)

यदि एक वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व और गैर-राजस्व प्राप्तियों से अधिक है, तो वह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटे का उल्लेख आमतौर पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र के खर्च और कुल आय के बीच का अंतर 5 लाख करोड़ रुपये है और देश की जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपये है, तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.5% है।

राजकोषीय घाटे का क्या कारण है?

कभी-कभी, सरकारें समाज के कमजोर और सुभेद्य वर्गों जैसे कि किसानों और गरीबों को हैंडआउट्स (handouts) और अन्य सहायता पर खर्च करती हैं। एक उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा हो सकता है यदि खर्च किया गया धन राजमार्गों, सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी उत्पादक संपत्तियों के निर्माण में जाता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और परिणामस्वरूप रोजगार सृजन होता है।

राजकोषीय घाटा कैसे पूरा किया जाता है?

सरकार पैसे उधार लेकर राजकोषीय घाटे की पूर्ति करती है। एक प्रकार से एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधारी आवश्यकताएँ उस वर्ष के राजकोषीय घाटे के बराबर होती हैं।

Q. 44) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए:

1. अंतरण अदायगी (Transfer Payments)
2. लाभांश और लाभ (Dividends and Profits)
3. ब्याज प्राप्तियां (Interest Receipts)
4. जीएसटी

उपरोक्त में से कौन सरकार के गैर-कर राजस्व (Non-tax revenue) का हिस्सा हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3 और 4
- d) केवल 1 और 4

Q. 44) Solution (b)

ऐसी प्राप्तियां जो कोई देनदारी नहीं पैदा करती हैं और सरकार पर दावा नहीं करती हैं, राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। ये राजस्व प्राप्तियां गैर-प्रतिदेय हैं और इन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कर राजस्व और गैर-कर राजस्व। कर राजस्व राजस्व प्राप्तियों के महत्वपूर्ण घटक हैं जिन्हें लंबी अवधि के लिए प्रत्यक्ष करें, उद्यमों और अप्रत्यक्ष करें जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में विभाजित किया गया है। दूसरी ओर, गैर-कर राजस्व, आवर्ती आय है जो सरकार द्वारा करें के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित की जाती है।

1. सरकार की राजस्व प्राप्तियां

- निगम कर
- आयकर
- सीमा शुल्क
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
- केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी और कर.

*जीएसटी या वस्तु और सेवा कर जो केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है, उसमें सीजीएसटी (केंद्रीय माल और सेवा कर), आईजीएसटी (एकीकृत माल और सेवा कर) और जीएसटी मुआवजा उपकर शामिल हैं।

2. गैर-कर राजस्व

- ब्याज प्राप्तियां
- लाभांश और लाभ
- बाह्य अनुदान
- अन्य गैर-कर राजस्व

- केंद्र शासित प्रदेशों की प्राप्ति

सरकार का खर्च:

- राजस्व व्यय
- पूंजीगत व्यय
- ब्याज भुगतान
- स्थानांतरण भुगतान- भत्ते, पेंशन
- पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान

Q. 45) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक वैधानिक निकाय है।
2. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
3. एफएसडीसी, उप-समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं।
4. यह अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म-मितव्ययी पर्यवेक्षण (macro-prudential supervision) की निगरानी करने का लक्ष्य रखती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 4
- c) केवल 2 और 3
- d) केवल 3 और 4

Q. 45) Solution (d)

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) भारत सरकार द्वारा गठित एक शीर्ष-स्तरीय निकाय है।

इस तरह की सुपर रेगुलेटरी बॉडी बनाने का विचार पहली बार 2008 में गुरु राम राजन कमेटी द्वारा रखा गया था। आखिरकार 2010 में, भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री, प्रणब मुखर्जी ने भारत का संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में सूक्ष्म-मितव्ययी और वित्तीय नियमितताओं से निपटने के लिए एक स्वायत्त निकाय स्थापित करने का फैसला किया।

एक शीर्ष-स्तरीय एफएसडीसी एक वैधानिक निकाय नहीं है।

वैश्विक आर्थिक मंदी ने दुनिया भर की सरकारों और संस्थानों पर अपनी आर्थिक संपत्ति को विनियमित करने का दबाव डाला है। इस परिषद को भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर स्थिति में लाने की भारत की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

इसमें अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म-मितव्ययी रेगुलेशन की निगरानी के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-नियामक समन्वय को बनाए रखने के तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने की परिकल्पना की गई है। परिषद को अपनी गतिविधियों के लिए अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्यों में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों (RBI, SEBI, PFRDA और IRDA) के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव (DEA), वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव, और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं।

FSDC उप-समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। परिषद आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों को अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है।

Q. 46) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बीमा संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में सूचीबद्ध विषय है।
2. भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत है।
3. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) भारत में बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 3
- d) 1 और 3

Q. 46) Solution (d)

भारत में बीमा भारत में बीमा के लिए बाजार को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों को कवर करता है। यह भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची में एक संघ सूची विषय के रूप में सूचीबद्ध है, जिसका अर्थ है कि इस पर केवल केंद्र सरकार द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है।

2021 के बजट सत्र में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है।

बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने से बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी कि उनकी शोधन क्षमता बढ़ती व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप बनी रहे। यह क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जबकि निजी इक्विटी फंडों के लिए अवधि में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

निजी इक्विटी उन फंडों और निवेशकों से बनी होती है जो सीधे निजी कंपनियों में निवेश करते हैं, या जो सार्वजनिक कंपनियों के खरीद में संलग्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक इक्विटी को हटा दिया जाता है।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक नियामक निकाय है और इसे भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। इसका गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा किया गया था, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है।

Q. 47) रणनीतिक विनिवेश (strategic disinvestment) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण का किसी अन्य इकाई को हस्तांतरण है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश के लिए दीपम (DIPAM) नोडल एजेंसी है।
3. दीपम (DIPAM) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 47) Solution (a)

जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य संस्था, निजी या सार्वजनिक को हस्तांतरित करने का निर्णय लेती है, तो प्रक्रिया को रणनीतिक विनिवेश कहा जाता है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रणनीतिक विनिवेश को निम्नानुसार परिभाषित करता है: “रणनीतिक विनिवेश का मतलब है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की सरकारी शेयरधारिता के 50 प्रतिशत तक के बड़े हिस्से की बिक्री, या प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उच्च प्रतिशत।

सार्वजनिक उद्यमों के अल्पसंख्यक शेयरों को किसी अन्य संस्था को बेचना, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, विनिवेश है। इसमें सरकार उद्यम का स्वामित्व बरकरार रखती है। दूसरी ओर, जब सरकार किसी उद्यम में बहुसंख्यक शेयर बेचती है, जो रणनीतिक विनिवेश/बिक्री है। यहां, सरकार इकाई के स्वामित्व को भी छोड़ देती है। सरकार बिक्री के लिए रखे जाने वाले उद्यमों का चयन सावधानी से करती है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग वित्त मंत्रालय के तहत विभागों में से एक है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों से संबंधित है।

Q. 48) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए:

1. सब्सिडी में रिसाव को रोकना
2. सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार

3. बढ़ती सब्सिडी
4. काले धन की वसूली

उपरोक्त में से कौन सी पहल से राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) हो सकता है?

- a) केवल 1, 2 और 3
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 2 और 4
- d) केवल 3 और 4

Q. 48) Solution (c)

भारत में, राजकोषीय समेकन या केंद्र के लिए राजकोषीय रोडमैप को बजटीय लक्ष्यों (राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा) के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें क्रमिक बजटों में प्राप्त किया जाना है।

निम्नलिखित उपायों से अर्थव्यवस्था में राजकोषीय समेकन हो सकता है:

- सब्सिडी में कटौती।
- सब्सिडी में लीकेज बंद करना।
- कर संरचना में सुधार (जीएसटी लागू करना)।
- सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार।
- काले धन की वसूली
- एफडीआई जैसे नीतिगत सुधार

उच्च आर्थिक विकास दर से सरकार को उच्च कर राजस्व प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण लाने के लिए कर राजस्व में वृद्धि आवश्यक है क्योंकि भारत में सरकारी व्यय को कम करने की सीमाएँ हैं।

Q. 49) ऑफ-बजट उधार (off budget borrowings) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये केंद्र द्वारा अन्य सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से लिए गए ऋण हैं।
2. वे भारत के राजकोषीय घाटे का एक बड़ा हिस्सा हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 49) Solution (a)

ऑफ-बजट उधार वे ऋण हैं जो सीधे केंद्र द्वारा नहीं लिए जाते हैं, बल्कि किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा लिए जाते हैं जो केंद्र सरकार के निर्देश पर उधार लेते हैं। इस तरह के उधार का उपयोग सरकार की व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

लेकिन चूंकि ऋण की देनदारी औपचारिक रूप से केंद्र पर नहीं है, इसलिए ऋण को राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। यह देश के राजकोषीय घाटे को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने में मदद करता है।

ऑफ-बजट उधार कैसे जुटाए जाते हैं?

सरकार एक कार्यान्वयन एजेंसी को ऋण के माध्यम से या बांड जारी करके बाजार से आवश्यक धन जुटाने के लिए कह सकती है।

उदाहरण के लिए, खाद्य सब्सिडी केंद्र के प्रमुख खर्चों में से एक है। 2020-21 के बजट प्रस्तुति में, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी बिल के लिए बजट की आधी राशि का ही भुगतान किया। कमी को राष्ट्रीय लघु बचत कोष से ऋण के माध्यम से पूरा किया गया था। इसने केंद्र को 2020-21 में अपने खाद्य सब्सिडी बिल को 1,51,000 करोड़ रुपये से 77,892 करोड़ रुपये करने की अनुमति दी।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी सरकार के लिए उधार लिया है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को पूर्व में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के लिए भुगतान करने के लिए कहा गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग ऑफ-बजट खर्चों को निधि देने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, उर्वरक सब्सिडी जारी करने में कमी को पूरा करने के लिए पीएसयू बैंकों के ऋण का उपयोग किया गया था।

ऑफ-बजट उधार के विभिन्न स्रोतों को देखते हुए, वास्तविक ऋण की गणना करना कठिन है। उदाहरण के लिए, यह व्यापक रूप से बताया गया था कि जुलाई 2019 में, बजट पेश करने के तीन दिन बाद, सीएजी ने 2017-18 के लिए वास्तविक राजकोषीय घाटा 3.46% के सरकारी संस्करण के बजाय सकल घरेलू उत्पाद का 5.85% आंका था।

Q.50) निम्नलिखित में से कौन-सा अर्थव्यवस्था पर घाटे के वित्तपोषण का प्रभाव है?

1. महंगाई कम करता है
2. निवेश बढ़ाता है

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 50) Solution (d)

घाटे के वित्तपोषण का अर्थ है घाटे को वित्तपोषित करने के लिए धन का सृजन करना जो राजस्व से अधिक व्यय के परिणामस्वरूप होता है। बांड की बिक्री या नए नोट की छपाई द्वारा जनता से उधार लेकर इस अंतर को कवर किया जा रहा है।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए उच्च आर्थिक विकास प्राथमिकता है। उच्च आर्थिक विकास के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। चूंकि निजी क्षेत्र भारी खर्च करने से कतराता है, इसलिए वित्तीय संसाधनों को निकालने की जिम्मेदारी सरकार पर है।

अक्सर कर और गैर-कर राजस्व दोनों ही करों के माध्यम से पर्याप्त संसाधन जुटाने में विफल रहते हैं। घाटे को अक्सर उधार या नए मुद्रा नोटों की छपाई के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

घाटे के वित्तपोषण का प्रभाव:

- नए नोट छापने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। इससे मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि होती है जिससे देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। घाटा वित्तपोषण स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति है। चूंकि घाटे के वित्तपोषण से कुल व्यय बढ़ता है और इसलिए, कुल मांग में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति का खतरा बहुत अधिक होता है।
- घाटा वित्तपोषण निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है तो कर्मचारी जीवित रहने के लिए उच्च मजदूरी की मांग करते हैं। अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है जो निवेशकों को हतोत्साहित करती है।

Q. 51) प्राथमिक घाटे (Primary Deficit) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष के उधार पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर है।
2. ब्याज भुगतान सहित, सरकार द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले उधार की राशि को जानने के लिए प्राथमिक घाटे को मापा जाता है।
3. प्राथमिक घाटे में कमी राजकोषीय स्वास्थ्य की दिशा में प्रगति दर्शाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 51) Solution (c)

प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष के उधार पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर है।

प्राथमिक घाटा ब्याज को छोड़कर सरकार की उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। यह वह राशि है जिसके द्वारा सरकार का कुल व्यय कुल आय से अधिक होता है। ध्यान दें कि प्राथमिक घाटे में किए गए ब्याज भुगतान शामिल नहीं हैं। साथ ही, प्राथमिक घाटा सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है।

आम तौर पर, जब सरकार ऋण लेती है, तो इसमें ब्याज राशि शामिल होता है। जब वह राशि मूल ऋण राशि से काट ली जाती है, तो वह प्राथमिक घाटा होता है।

प्राथमिक घाटा फॉर्मूला:

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा (कुल व्यय - सरकार की कुल आय) - ब्याज भुगतान (पिछले उधारों का)।

प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा के बीच अंतर:

- प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है।
- राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल आय के बीच का अंतर है।

प्राथमिक घाटे की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है: राजकोषीय घाटा - किए गए ब्याज भुगतान।

प्राथमिक घाटा क्या दर्शाता है?

- ब्याज भुगतान को छोड़कर, सरकार द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले उधार की राशि को जानने के लिए प्राथमिक घाटे को मापा जाता है।
- जब प्राथमिक घाटा शून्य होता है, तो राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि सरकार ने सिर्फ ब्याज भुगतान का भुगतान करने के लिए उधार का सहारा लिया है। इसके अलावा, मौजूदा ऋण में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है।

Q. 52) निम्नलिखित में से कौन सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है?

1. ऋण की वसूली
2. सीमा शुल्क
3. लाभ और लाभांश
4. विनिवेश

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3 और 4
- d) केवल 1 और 4

Q. 52) Solution (d)

पूंजी प्राप्तियां सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, विदेशों और संस्थानों से उधार और आरबीआई से उधार हैं। केंद्र द्वारा राज्यों और अन्य को दिए गए ऋण की वसूली भी पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है। बैलेंस शीट में, देनदारियों अनुभाग में पूंजीगत प्राप्तियों का उल्लेख किया जाता है। पूंजी प्राप्ति में गैर-पुनरावृत्ति की प्रकृति होती है।

सभी पूंजीगत प्राप्तियां कर-मुक्त हैं, जब तक कि इस पर कर लगाने का कोई प्रावधान न हो। पूंजीगत प्राप्तियां गैर-ऋण और ऋण प्राप्तियां दोनों हो सकती हैं।

गैर-ऋण प्राप्तियां वे हैं जो सरकार के लिए भविष्य में कोई पुनर्भुगतान बोझ नहीं उठाती हैं। कुल बजट प्राप्तियों का लगभग 75 प्रतिशत गैर-ऋण प्राप्तियां हैं।

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के उदाहरण: ऋण और अग्रिम की वसूली, विनिवेश, बोनस शेयर जारी करना, आदि।

ऋण प्राप्तियों को सरकार को चुकाना होगा। सरकारी व्यय का लगभग 25 प्रतिशत उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। ऋण प्राप्ति (या उधार) में कमी अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी छलांग हो सकती है। सरकार की अधिकांश पूंजीगत प्राप्तियां ऋण प्राप्तियां हैं।

ऋण पूंजी प्राप्तियों के उदाहरण: बाजार ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूतियां जारी करना, प्रतिभूतियां जारी करना, अल्पकालिक उधार, ट्रेजरी बिल, छोटी बचत के सापेक्ष प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधि, रिलिफ बांड, बचत बांड, स्वर्ण बांड, बाहरी ऋण, आदि, ऋण पूंजी प्राप्तियों के सभी उदाहरण हैं।

Q. 53) घाटे के बजट (deficit budgeting) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस प्रकार का बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त है।
2. यह अतिरिक्त मांग उत्पन्न करने और आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देने में मदद करता है।
3. इस प्रकार के बजट को मुद्रास्फीति के समय लागू किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 53) Solution (a)

एक सरकारी बजट को घाटे का बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो।

इस प्रकार का बजट भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त है।

मंदी के समय विशेष रूप से सहायक, घाटे का बजट अतिरिक्त मांग उत्पन्न करने और आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देने में मदद करता है।

यहां, सरकार रोजगार दर में सुधार के लिए अत्यधिक खर्च करती है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है जो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करती है।

सरकार इस राशि को सार्वजनिक उधार (सरकारी बांड जारी करके) या अपने संचित आरक्षित अधिशेष से निकालकर कवर करती है।

घाटे के बजट के गुण:

- आर्थिक मंदी के समय बेरोजगारी जैसी सार्वजनिक चिंताओं को दूर करने में मदद करता है।
- सरकार को लोक कल्याण पर खर्च करने में सक्षम बनाता है।

घाटे के बजट के दोष

- सरकार द्वारा अविवेकपूर्ण व्यय को प्रोत्साहित कर सकता है।
- कर्ज जमा कर सरकार पर बोझ बढ़ाता है।

Q. 54) लेखानुदान (Vote on account) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सरकार को थोड़े समय के लिए या पूर्ण बजट पारित होने तक अपने खर्चों को निधि देने में सक्षम बनाता है
2. यह सरकार के बजट के व्यय और राजस्व दोनों पक्षों से संबंधित है।
3. यह प्रत्यक्ष करों में बदलाव नहीं कर सकता

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 54) Solution (c)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 द्वारा परिभाषित लेखानुदान, भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान है, जो आम तौर पर नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने तक कुछ महीनों तक चलता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि को परिभाषित करता है, जहां केंद्र सरकार का सारा राजस्व करों से, ऋणों द्वारा जुटाई गई धनराशि और ऋणों पर ब्याज, और राज्यों से करों का एक हिस्सा होता है।

इसमें कहा गया है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अलावा समेकित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है, जिसके लिए केंद्र केंद्रीय बजट के दौरान एक विनियोग विधेयक पारित करता है।

हालांकि, विनियोग विधेयकों को संसद में पारित होने और कानून बनने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को कम करने के लिए केंद्र को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से सीएफआई से किसी भी राशि को वापस लेने की अनुमति की आवश्यकता होती है, लेखानुदान पारित किया जाता है।

आमतौर पर, लेखानुदान को एक औपचारिकता के रूप में माना जाता है और इस मामले पर बिना किसी चर्चा के पारित किया जाता है। इसका उपयोग निर्वाचित सरकार के अंतिम वर्ष के दौरान एक अल्पकालिक व्यय विधेयक पारित करने के लिए भी किया जाता है ताकि नई सरकार पूर्ण बजट की पुष्टि होने तक चीजों को चालू रखे। यह आमतौर पर दो महीने के लिए निर्धारित किया जाता है और प्रमुख परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन, वेतन, ऋण पर ब्याज, सब्सिडी आदि के लिए आवंटित किया जाता है।

पूर्ण बजट व्यय और राजस्व दोनों पक्षों से संबंधित है लेकिन लेखानुदान केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है।

लेखानुदान प्रत्यक्ष करों को नहीं बदल सकता क्योंकि उन्हें एक वित्त विधेयक के माध्यम से पारित करने की आवश्यकता होती है।

एक चुनावी वर्ष के दौरान, सत्तारूढ़ सरकार आम तौर पर पूर्ण बजट के बजाय लेखानुदान या अंतरिम बजट का विकल्प चुनती है। जबकि तकनीकी रूप से, सरकार के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसी नीतियां लागू करना अनुपयुक्त होगा जो एक ही वर्ष में सत्ता ग्रहण करने वाली आने वाली सरकार को स्वीकार्य हो भी सकती हैं और नहीं भी।

Q. 55) पिगोवियन कर (Pigovian Tax) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह किसी भी ऐसी गतिविधि पर एक कर है जो समाज के लिए प्रतिकूल दुष्प्रभाव पैदा करता है।
2. शराब और तंबाकू पर कर पिगोवियन कर के उदाहरण हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 55) Solution (c)

एक पिगोवियन (पिगोवियन) कर निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के खिलाफ समाज के लिए प्रतिकूल दुष्प्रभाव पैदा करने वाली गतिविधियों में संलग्न होने के लिए मूल्यांकन किया गया कर है।

इनमें पर्यावरण प्रदूषण, तंबाकू उत्पादों की बिक्री से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर दबाव और अन्य कोई दुष्प्रभाव शामिल हैं जिनका बाहरी और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पिगोवियन टैक्स/कर का उद्देश्य उन वस्तुओं या सेवाओं के निर्माता पर कर लगाना है जो समाज के लिए प्रतिकूल दुष्प्रभाव पैदा करते हैं।

पिगोवियन टैक्स का उद्देश्य नकारात्मक बाह्यता के निर्माता या उपयोगकर्ता को लागत का पुनर्वितरण करना है।

प्लास्टिक की थैलियों, तंबाकू, शराब पर कार्बन उत्सर्जन कर या कर पिगोवियन करों के उदाहरण हैं।

पिगोवियन कर नकारात्मक बाह्यता की लागत के बराबर होते हैं, लेकिन यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है और अगर अधिक अनुमान लगाया जाए तो समाज को नुकसान हो सकता है।

Q. 56) उर्वरक सब्सिडी (fertilizer subsidies) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उर्वरक सब्सिडी किसानों के खाते में जाती है।
2. सभी उर्वरकों की एमआरपी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1

- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 56) Solution (d)

एक अवधारणा के रूप में सब्सिडी की शुरुआत 1970-80 के दशक की हरित क्रांति के दौरान हुई थी।

उर्वरक सब्सिडी किसान द्वारा एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से कम कीमत पर, यानी सामान्य मांग-आपूर्ति-दर, या नियमित उत्पादन और आयात लागत से कम पर खरीद रही है।

उर्वरक सब्सिडी अंततः उर्वरक कंपनी को जाती है, भले ही यह किसान को ही लाभ हो।

2018 से पहले, जिला रेलहेड या नामित गोदाम द्वारा सामग्री भेजने और प्राप्त करने के बाद कंपनियों को प्रतिपूर्ति की गई थी।

2018 में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की शुरुआत हुई, जो सीधे रिटेलर के खाते में पैसा ट्रांसफर करेगा।

जबकि, यूरिया के लिए एमआरपी सरकार द्वारा नियंत्रित / तय की जाती है, इसे डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) आदि सहित अन्य उर्वरकों के लिए नियंत्रित किया जाता है।

यूरिया के अलावा अन्य उर्वरकों में सरकार केवल एक निश्चित प्रति टन सब्सिडी देती है। इसका मतलब है कि सब्सिडी तय है, जबकि एमआरपी परिवर्तनशील है।

Q. 57) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक उपकर (cess) नियमित कर राजस्व की तरह खर्च किया जा सकता है जबकि अधिभार (surcharge) केवल विशेष उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा सकता है।
2. उपकर और अधिभार की आय भारत के समेकित कोष में जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 57) Solution (b)

एक उपकर अन्य करों जैसे उत्पाद शुल्क और व्यक्तिगत आयकर से अलग है, जिसमें यह वर्तमान कर (कर पर कर) के अतिरिक्त लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, 30 प्रतिशत व्यक्तिगत आयकर पर 3% शिक्षा उपकर मौजूदा 30 प्रतिशत पर कर के रूप में लगाया जाता है। परिणामस्वरूप, समग्र कर दर बढ़कर 30.9 प्रतिशत (30 प्रतिशत मूल दर + 30 प्रतिशत कर दर का 3% (उपकर)) हो जाती है।

भारत में कर का भुगतान करने वाले सभी करदाताओं पर उपकर लगाया जाता है। यदि आय पर कोई कर उत्पन्न होता है, तो राशि की परवाह किए बिना, उसे उस कर पर भी कर का भुगतान करना होगा। भारत की संचित निधि को उपकर का भुगतान किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग केवल विशेष उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

भारत में उपयोग किए जाने वाले कुछ मुख्य उपकर के नाम हैं: शिक्षा उपकर, सड़क उपकर या (ईंधन उपकर), अवसंरचना उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर, कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर।

अधिभार किसी भी कर में जोड़ा गया शुल्क है जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है। अधिभार एक ऐसा शब्द है जो एक अतिरिक्त शुल्क या लेवी को संदर्भित करता है। व्यक्तिगत आयकर (उच्च आय वाले स्लैब और अति धनी) और कॉर्पोरेट आयकर दो सबसे बड़े अधिभार हैं।

अधिभार राजस्व भी भारत के समेकित कोष (सीएफआई) में जाता है, जहां इसका उपयोग किसी भी कारण से किया जा सकता है, जैसे नियमित कर राजस्व। एक अधिभार कर पर एक कर है जो किसी विशेष कारण से नहीं लगाया जाता है, और अधिभार की आय का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसे वह उपयुक्त समझता है।

अधिभार और उपकर के बीच मुख्य अंतर यह है कि, हालांकि प्रत्येक को राज्य सरकारों के साथ साझा किया जा सकता है, अधिभार को सीएफआई के पास रखा जा सकता है और हर दूसरे लेवी की तरह खर्च किया जा सकता है, जबकि सीएफआई को आवंटित होने के बाद उपकर को एक अलग फंड के रूप में रखा जाना चाहिए और केवल एक विशेष कारण के लिए ही खर्च किया जा सकता है।

Q. 58) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कर लोच (Tax elasticity) सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन के लिए कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन की दर है।
2. कर उछाल (Tax buoyancy) का तात्पर्य कर की दर में परिवर्तन के जवाब में कर राजस्व में परिवर्तन से है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 58) Solution (d)

कर उछाल सरकार की कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच इस संबंध की व्याख्या करता है। यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जब कोई कर उछाल होता है, तो उसका राजस्व बिना कर की दर बढ़ाए बढ़ता है। यह सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए कर राजस्व प्राप्ति की उच्च संवेदनशीलता को इंगित करता है।

प्रत्यक्ष करों के लिए कर उछाल सबसे अधिक होगा। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, उत्पन्न अतिरिक्त आय अमीर समूह को जा सकती है। इसका एक हिस्सा उन्हें टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है। तो अगर जीडीपी विकास दर उच्च दर्ज करती है, नौ प्रतिशत, प्रत्यक्ष आयकर संग्रह में तेजी आएगी। आम तौर पर, प्रत्यक्ष कर जीडीपी विकास दर के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

कर लोच का तात्पर्य कर की दर में परिवर्तन के जवाब में कर राजस्व में परिवर्तन से है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार कॉर्पोरेट आयकर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर देती है, तो कर राजस्व कैसे बदलता है, यह कर लोच को दर्शाता है।

Q. 59) क्राउडिंग आउट इफेक्ट (Crowding Out Effect) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज दरों में वृद्धि से निजी निवेश खर्च में कमी आती है।
2. यह तब होता है जब सरकार संकुचनकारी राजकोषीय नीति रख अपनाती है

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 59) Solution (a)

क्राउडिंग-आउट इफेक्ट/प्रभाव एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज दरों में वृद्धि से निजी निवेश खर्च में कमी आती है जिससे कि यह कुल निवेश खर्च की प्रारंभिक वृद्धि को कम कर देता है, इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है।

कभी-कभी, सरकार एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति का रुख अपनाती है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने खर्च को बढ़ाती है।

इससे ब्याज दरों में वृद्धि होती है। बढ़ी हुई ब्याज दरें निजी निवेश निर्णयों को प्रभावित करती हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट के उच्च परिमाण से अर्थव्यवस्था में कम आय भी हो सकती है।

उच्च ब्याज दरों के साथ, निवेश की जाने वाली निधियों की लागत बढ़ जाती है और ऋण वित्तपोषण तंत्र तक उनकी पहुंच प्रभावित होती है। यह अंततः कम निवेश की ओर जाता है और कुल निवेश खर्च में शुरूआती वृद्धि के प्रभाव को कम करता है।

आमतौर पर सरकारी खर्च में शुरूआती वृद्धि को उच्च करें या सरकार की ओर से उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है।

Q.60) सार्वजनिक ऋण (Public Debt) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें केंद्र सरकार की कुल देनदारियां शामिल हैं जिन्हें भारत के आकस्मिक निधि से भुगतान किया जाना है।
2. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल भारत में सार्वजनिक ऋण के स्रोत हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 60) Solution (b)

सार्वजनिक ऋण किसी देश की सरकार द्वारा उधार ली गई कुल राशि है। भारतीय संदर्भ में, सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां शामिल हैं जिन्हें भारत की संचित निधि से भुगतान किया जाना है।

केंद्र सरकार मोटे तौर पर अपनी देनदारियों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। भारत की संचित निधि के विरुद्ध अनुबंधित ऋण को सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत भारत की संचित निधि के बाहर प्राप्त अन्य सभी निधियां शामिल हैं, जहां सरकार केवल एक बैंकर या संरक्षक के रूप में कार्य करती है। दूसरे प्रकार की देनदारियों को सार्वजनिक खाता कहा जाता है।

सार्वजनिक ऋण के स्रोत इस प्रकार सूचीबद्ध हैं:

- दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां या सरकारी प्रतिभूतियां।
- ट्रेजरी बिल या टी-बिल्स
- बाह्य सहायता
- अल्प आवधिक ऋण
- केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण परिभाषा

केंद्र सरकार अपनी देनदारियों को सार्वजनिक ऋण के रूप में वर्णित करती है, जो भारत की संचित निधि के सापेक्ष अनुबंधित हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार है।

Q. 61) मुद्रा बाजार (money market) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह वित्तीय बाजार का एक खंड है जहां दीर्घकालिक प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं और उनका कारोबार किया जाता है।
2. पूंजी बाजार की तुलना में मुद्रा बाजार में जोखिम कम होता है।
3. मुद्रा बाजार अर्थव्यवस्था में धन की तरलता को बढ़ाता है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 61) Solution (b)

मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार का एक खंड है जहां अल्पकालिक प्रतिभूतियों का उधार और ऋण लिया जाता है। उधारकर्ता इसे उस नकदी हेतु श्रेणीबद्ध करते हैं जिसकी उन्हें दिन-प्रतिदिन संचालित करने की आवश्यकता होती है। ऋणदाता इसका उपयोग अतिरिक्त नकदी को काम पर लगाने के लिए करते हैं।

पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का एक खंड है जहां लंबी अवधि की प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं और उनका कारोबार किया जाता है।

हालांकि मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों में निवेश की वापसी पूंजी बाजार प्रतिभूतियों की तुलना में कम है, वे पूंजी बाजार प्रतिभूतियों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले हैं।

मुद्रा बाजार सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य बड़े संगठनों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करके देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान देता है। जिन निवेशकों को अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है, वे इसे मुद्रा बाजार में निवेश कर सकते हैं और ब्याज अर्जित कर सकते हैं।

Q. 62) निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत बाजार के साधन हैं?

1. बांड
2. शेयर
3. वाणिज्यिक पत्र (Commercial Papers)
4. जमा प्रमाणपत्र (Certificate of deposit)

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 3 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q. 62) Solution (a)

पूंजी बाजार उन सुविधाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है जहां मध्यम और लंबी अवधि के फंड (न्यूनतम 365 दिनों और उससे अधिक की अवधि के लिए), ऋण और इक्विटी दोनों को उठाया और निवेश किया जाता है।

पूंजी बाजार में कारोबार किए जाने वाले मुख्य साधन हैं - इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रिफरेंस शेयर आदि। मुद्रा बाजार में कारोबार करने वाले मुख्य साधन अल्पकालिक ऋण साधन हैं जैसे कि टी-बिल, ट्रेड बिल रिपोर्ट, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र।

पूंजी बाजार बचतकर्ताओं से अधिशेष निधियों को संस्थानों में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं जो फिर उन्हें उत्पादक उपयोग में निवेश करते हैं। आम तौर पर, यह बाजार ज्यादातर लंबी/दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों में कारोबार करता है।

पूंजी बाजार में प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार होते हैं। प्राथमिक बाजार स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों के नए निर्गमन के व्यापार से संबंधित है, जबकि द्वितीयक बाजार मौजूदा या पहले से जारी प्रतिभूतियों के आदान-प्रदान से संबंधित है। पूंजी बाजार में एक और महत्वपूर्ण अंतर व्यापार की सुरक्षा की प्रकृति, यानी शेयर बाजार और बांड बाजार के आधार पर किया जाता है।

Q. 63) वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह किसी देश के मुद्रा मूल्य की तुलना उसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के भारित औसत से करता है।
2. यह अपने व्यापार भागीदारों की तुलना में किसी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेतक है।
3. घटती आरईआईआर इंगित करती है कि एक देश अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो रहा है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 63) Solution (b)

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआईआर) अन्य प्रमुख मुद्राओं के सूचकांक या बास्केट के संबंध में किसी देश की मुद्रा का भारित औसत है। सूचकांक में प्रत्येक देश के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के सापेक्ष व्यापार संतुलन की तुलना करके भार निर्धारित किया जाता है।

किसी देश के आरईआईआर में वृद्धि इस बात का संकेत है कि उसका निर्यात अधिक महंगा होता जा रहा है और उसका आयात सस्ता होता जा रहा है। यह अपनी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता खो रहा है।

आरईआईआर एक राष्ट्र और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच द्विपक्षीय विनिमय दरों का औसत लेकर और फिर प्रत्येक भागीदार के व्यापार आवंटन को ध्यान में रखते हुए इसे भारित करके निर्धारित किया जाता है।

आरईआईआर का उपयोग किसी देश की मुद्रा के संतुलन मूल्य को मापने के लिए किया जा सकता है, किसी देश के व्यापार प्रवाह के अंतर्निहित कारकों की पहचान कर सकता है, और उस प्रभाव का विश्लेषण कर सकता है जो प्रतिस्पर्धा और तकनीकी परिवर्तन जैसे अन्य कारकों का किसी देश पर और अंततः व्यापार-भारित सूचकांक पर पड़ता है।

देश की मुद्रा स्फीति के लिए समायोजित राष्ट्र की नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एनईआईआर) इसकी वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआईआर) के बराबर होती है।

Q. 64) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मुद्रा का मूल्यहास (Depreciation) तब होता है जब कोई देश एक निश्चित विनिमय दर में अपनी विनिमय दर को कम करने का सचेत निर्णय लेता है।
2. मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation) तब होता है जब किसी मुद्रा के मूल्य में फ्लोटिंग विनिमय दर में गिरावट होती है।
3. मुद्रा मूल्यहास विदेशों में घरेलू सामान सस्ता बनाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 64) Solution (c)

मुद्रा का मूल्यहास तब होता है जब फ्लोटिंग विनिमय दर में मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है। आर्थिक मूल तत्त्वों, ब्याज दर में अंतर, राजनीतिक अस्थिरता, या जोखिम से बचने के कारण मुद्रा के मूल्यहास हो सकते हैं।

मुद्रा मूल्यहास विदेशी देश में घरेलू सामान सस्ता बनाता है क्योंकि इस तरह के अधिक सामान अब समान मात्रा में विदेशी मुद्रा के साथ खरीदे जा सकते हैं। इसलिए, यह निर्यात में वृद्धि की ओर जाता है।

मुद्रा अवमूल्यन तब होता है जब कोई देश अपनी विनिमय दर को एक निश्चित या अर्ध-स्थिर विनिमय दर में कम करने का सचेत निर्णय लेता है। इसलिए, तकनीकी रूप से अवमूल्यन तभी संभव है जब कोई देश किसी निश्चित विनिमय दर नीति का सदस्य हो। मुद्रा का अवमूल्यन करने से देश के निर्यात की लागत कम हो जाती है और व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है।

Q. 65) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एफडीआई मेजबान देश के वित्तीय बाजार में धन का निवेश करने की अनुमति देता है।
2. एफडीआई कुशल संसाधनों, नई और बेहतर प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान और विकास, पूंजी, रणनीतियों और प्रबंधन के हस्तांतरण में मदद करता है।
3. एफडीआई मेजबान देश की आर्थिक वृद्धि या जीडीपी में वृद्धि में मदद नहीं करता है, यह सिर्फ अर्थव्यवस्था में पूंजी जोड़ता है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 65) Solution (b)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से तात्पर्य किसी कंपनी, संस्थान या व्यक्ति द्वारा अपने देश के बाहर किसी कंपनी में किए गए निवेश से है। आम तौर पर, विकासशील देश, जिन्हें अधिक धन और संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता होती है, विदेशी कंपनियों या व्यक्तियों से निवेश का एफडीआई तरीका तलाशने का प्रयास करते हैं।

एफडीआई के माध्यम से, निवेशकों के पास मेजबान देश में व्यवसाय के संचालन पर अच्छी मात्रा में प्रबंधन नियंत्रण होता है।

दूसरी ओर विदेशी संस्थागत निवेश (FII) का तात्पर्य निवेशकों द्वारा किसी विदेशी देश की वित्तीय संपत्ति में पूंजी लगाकर किए गए निवेश से है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बनाम विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई):

दोनों प्रकार के विदेशी निवेश होने के कारण, उनके संचालन के तरीके, वे किसको लक्षित करते हैं, और दोनों से प्राप्त होने वाले रिटर्न में काफी अंतर है।

1. प्रबंधन का नियंत्रण

एफडीआई एक विदेशी कंपनी में निवेश का प्रत्यक्ष रूप होने के कारण, निवेशक अधिक रुचि रखते हैं और यहां तक कि कंपनी के प्रबंधन पर एक उच्च नियंत्रण का लाभ लेते हैं, भले ही वह विदेशी देश में हो।

इसके विपरीत, विदेशी संस्थागत निवेश केवल मेजबान देश के वित्तीय बाजार में धन का निवेश करने की अनुमति देता है और इसलिए, प्रबंधकीय निर्णयों पर अधिक पकड़ नहीं रखता है, या इसे केवल निष्क्रिय निवेशक के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2. प्रवेश और निकास मानदंड पर विनियम:

आमतौर पर, एफडीआई के प्रवेश और निकास मानदंड पर एफआईआई के विपरीत अधिक बाधाएं होती हैं जो उस मामले में काफी उदार होती हैं। उदाहरण के लिए, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र एफडीआई की अनुमति नहीं देता है।

3. हस्तांतरण की अनुमति देता है:

एफडीआई बहुत सारे कुशल संसाधनों, नई और बेहतर तकनीकों, अनुसंधान और विकास, पूंजी, रणनीतियों और प्रबंधन आदि के हस्तांतरण में मदद करता है, जबकि एफआईआई केवल मेजबान देश की वित्तीय संपत्तियों या संस्थानों में धन या पूंजी के हस्तांतरण में मदद करता है।

4. उनका क्या परिणाम होता है?

एफडीआई निश्चित रूप से दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह में परिणाम देता है, क्योंकि किसी कंपनी के नियोजन और रणनीति चरण से कार्यान्वयन और निष्पादन चरण तक व्यवस्थित होने में वास्तव में समय लगता है।

दूसरी ओर, एफआईआई के लिए, उनका निवेश क्षितिज पूरी तरह से मेजबान देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है, जो स्थिर होने पर दीर्घकालिक निवेश की ओर जाता है, और जब जोखिम होता है, तो निवेशकों द्वारा पूंजी वापस खींच ली जाती है।

5. मेजबान देश का आर्थिक विकास:

एफडीआई के परिणामस्वरूप समग्र आर्थिक विकास होता है जो न केवल मेजबान देश में पूंजी लाकर दीर्घकालिक होता है, बल्कि नई तकनीक और बुनियादी ढांचे के निवेश के माध्यम से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर बढ़ाता है, उचित प्रशिक्षण द्वारा कुशल कार्यबल में वृद्धि, आदि।

दूसरी ओर, एफआईआई सिर्फ धन लाता है, जो निश्चित रूप से मेजबान देश के सकल घरेलू उत्पाद में आर्थिक विकास या वृद्धि में मदद नहीं करता है। लेकिन यह सिर्फ अर्थव्यवस्था में पूंजी जोड़ता है।

Q. 66) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डिबेंचर जारीकर्ता की संपत्ति द्वारा समर्थित होते हैं जबकि बांड किसी भी भौतिक संपत्ति या संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं।
2. परिशोधन (liquidation) के समय, डिबेंचर धारकों को हमेशा बांडधारकों पर वरीयता दी जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 66) Solution (d)

बांड और डिबेंचर दोनों सरकार या कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण साधन हैं। ये दोनों जारीकर्ता के लिए धन उगाहने वाले साधन हैं।

बांड आम तौर पर सरकार, सरकार की एजेंसियों या बड़े निगमों द्वारा जारी किए जाते हैं जबकि सार्वजनिक कंपनियों द्वारा बाजार से पैसा जुटाने के लिए डिबेंचर जारी किए जाते हैं।

बांड जारीकर्ता की संपत्ति द्वारा समर्थित होते हैं जबकि डिबेंचर किसी भी भौतिक संपत्ति या संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं। डिबेंचर जारी करने वाले पक्ष की साख और प्रतिष्ठा पर ही जारी और खरीदे जाते हैं।

बांड की ब्याज दर आमतौर पर डिबेंचर से कम होती है। कम ब्याज दर कम जोखिम वाले कारक को दर्शाती है। दूसरी ओर, डिबेंचर उच्च ब्याज दर देते हैं लेकिन वे प्रकृति में असुरक्षित हैं इसलिए यहां जोखिम कारक अधिक है।

परिशोधन के समय, बांडधारकों को हमेशा डिबेंचर धारकों पर वरीयता दी जाती है।

Q. 67) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लंबवत एफडीआई (Vertical FDI) तब देखा जाता है जब व्यवसाय समान गतिविधियाँ करता है लेकिन एक विदेशी राष्ट्र में।
2. क्षैतिज एफडीआई (Horizontal FDI) तब होता है जब व्यवसाय विदेशों में विभिन्न गतिविधियाँ करता है लेकिन ये गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय से संबंधित होती हैं।
3. प्लेटफॉर्म एफडीआई (Platform FDI) का मतलब है कि एक व्यवसाय दूसरे देश में फैलता है लेकिन व्यवसाय से उत्पादन फिर किसी तीसरे देश को निर्यात किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 67) Solution (c)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं:

1. क्षेत्रीय एफडीआई: इस प्रकार के एफडीआई के तहत, एक व्यवसाय अपने अंतर्देशीय संचालन को दूसरे देश में विस्तारित करता है। व्यवसाय वही गतिविधियाँ करता है लेकिन एक विदेशी राष्ट्र में।
2. लंबवत एफडीआई: इस मामले में, एक व्यवसाय आपूर्ति श्रृंखला के एक अलग स्तर पर जाकर दूसरे देश में फैलता है। इस प्रकार व्यवसाय विदेशों में विभिन्न गतिविधियाँ करता है लेकिन ये गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय से संबंधित होती हैं।
3. समूह एफडीआई (Conglomerate FDI): एफडीआई के प्रकार के तहत, एक व्यवसाय एक विदेशी देश में असंबंधित व्यावसायिक गतिविधियों को करता है। यह प्रकार असामान्य है क्योंकि इसमें एक नए देश और एक पूरी तरह से नए बाजार में प्रवेश करने की कठिनाई शामिल है।
4. प्लेटफार्म एफडीआई: यहां, एक व्यवसाय दूसरे देश में फैलता है लेकिन व्यवसाय से उत्पादन फिर तीसरे देश में निर्यात किया जाता है।

Q. 68) पार्टिसिपेटरी नोट्स (Participatory notes) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पार्टिसिपेटरी नोट्स ऑफशोर/ अपतटीय डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट/साधन हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने के लिए किया जाता है।
2. पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से निवेश करने वाली किसी भी संस्था को सेबी के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 68) Solution (a)

पार्टिसिपेटरी नोट्स जिन्हें पी-नोट्स भी कहा जाता है, भारतीय शेयरों के साथ अंतर्निहित संपत्ति के रूप में अपतटीय डेरिवेटिव साधन हैं। इन उपकरणों का उपयोग शेयर बाजारों में निवेश करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग भारत के बाहर भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों में निवेश करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इन्हें अपतटीय व्युत्पन्न साधन भी कहा जाता है।

पार्टिसिपेटरी नोट्स दलालों और सेबी के साथ पंजीकृत एफआईआई द्वारा जारी किए जाते हैं। निवेश इन विदेशी निवेशकों की ओर से भारत में पहले से पंजीकृत दलालों द्वारा किया जाता है।

पार्टिसिपेटरी नोट्स के लाभ

- गुमनामी: पार्टिसिपेटरी नोट्स में निवेश करने वाली किसी भी संस्था को सेबी के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सभी एफआईआई को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना होगा। यह बड़े हेज फंडों को अपनी पहचान बताए बिना अपना संचालन करने में सक्षम बनाता है।
- व्यापार में आसानी: पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से व्यापार करना आसान है क्योंकि वे अनुबंध नोटों की तरह हैं जिन्हें पुष्टि और वितरण द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है।
- कर बचत: कुछ संस्थाएं कुछ पसंदीदा देशों के कर कानूनों का लाभ उठाने के लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से अपने निवेश को रूट करती हैं।

पी-नोट्स के नुकसान

- साधन की गुमनाम प्रकृति के कारण, निवेशक भारतीय नियामकों की पहुंच से बाहर हो सकते हैं।
- पी-नोटों का उपयोग धनी भारतीयों के साथ धनशोधन में किया जा रहा है, जैसे कंपनियों के प्रवर्तक, इसका उपयोग बेहिसाब धन वापस लाने और अपने स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने के लिए करते हैं।

Q. 69) शेयर बाजार के संदर्भ में, "बीटा" (Beta) शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बीटा समग्र शेयर बाजार में बदलाव के लिए स्टॉक की कीमत की प्रतिक्रिया को मापता है।
2. अगर बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार से ज्यादा उतार-चढ़ाव वाला है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 69) Solution (c)

बीटा एक संख्यात्मक मान है जो किसी शेयर के उतार-चढ़ाव को समग्र शेयर बाजार में बदलाव के लिए मापता है।

बीटा समग्र शेयर बाजार में बदलाव के लिए स्टॉक की कीमत की प्रतिक्रिया को मापता है। बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना पर, उदाहरण के लिए एनएसई निफ्टी एक विशेष स्टॉक रिटर्न के लिए, एक पैटर्न विकसित होता है जो बाजार के जोखिम के लिए स्टॉक के खुलेपन को दर्शाता है। इससे निवेशक को यह तय करने में मदद मिलती है कि क्या वह जोखिम भरे स्टॉक के लिए जाना चाहता है जो बाजार के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध है (बीटा 1 से ऊपर), या कम अस्थिर (बीटा 1 से नीचे) के साथ।

बीटा जितना अधिक होगा, स्टॉक का जोखिम भागफल उतना ही अधिक होगा। अगर बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार से ज्यादा उतार-चढ़ाव वाला है। इस उपाय की जानकारी रखने वाले बहुत से निवेशक अपने निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

Q.70) निम्नलिखित में से कौन सा/से बुल मार्केट (Bull market) का संकेतक है/हैं?

1. उच्च बेरोजगारी दर
2. स्टॉक की कीमतों में उछाल
3. देश की जीडीपी में गिरावट

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 70) Solution (b)

एक बुल मार्केट वित्तीय बाजारों में एक समय की अवधि है जब किसी संपत्ति या प्रतिभूति की कीमत लगातार बढ़ती है।

बुल मार्केट की आमतौर पर स्वीकृत परिभाषा तब होती है जब स्टॉक की कीमतों में 20% की दो गिरावट के बाद 20% की वृद्धि होती है।

बुल मार्केट के तीन प्रमुख संकेतक इस प्रकार हैं:

1. देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ता है: यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद पिछले अवधि से अधिक है, तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता खर्च भी अधिक है और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था का एक सामान्य संकेतक है।
2. स्टॉक की कीमतों में वृद्धि: जब स्टॉक की कीमत बढ़ती है, तो अधिक लोगों को विश्वास होता है कि भविष्य में बाजार में ऊपर जाना जारी रहेगा और अधिकांश प्रमुख सूचकांक भी उसी के अनुसार बढ़ेंगे।
3. देश में रोजगार दर में वृद्धि: अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अर्थ है व्यवसायों में वृद्धि जिसका अर्थ है कार्यबल में वृद्धि। बुल मार्केट में ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

एक बुल मार्केट आमतौर पर निवेशकों को लाभ कमाने के कई अवसर प्रस्तुत करता है, क्योंकि स्टॉक की कीमतें आम तौर पर बोर्ड के चारों ओर बढ़ जाती हैं।

Q. 71) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सीएसआर एक निगम/ कॉर्पोरेशन के व्यवसाय मॉडल और संस्कृति में सामाजिक रूप से लाभकारी कार्यक्रमों और प्रथाओं का एकीकरण है।
2. भारत में सीएसआर की अवधारणा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा शासित है।
3. कंपनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपने पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 3% सीएसआर गतिविधियों में खर्च करना होता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 71) Solution (b)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एक स्व-विनियमन व्यवसाय मॉडल है जो एक कंपनी को सामाजिक रूप से जवाबदेह होने में मदद करता है - अपने, अपने शेयरधारकों और जनता के प्रति।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का अभ्यास करके, जिसे कॉर्पोरेट नागरिकता भी कहा जाता है, कंपनियां इस बात के प्रति सचेत हो सकती हैं कि वे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सहित समाज के सभी पहलुओं पर किस तरह के प्रभाव डाल रही हैं।

भारत में, सीएसआर की अवधारणा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 द्वारा शासित है।

भारत दुनिया का पहला देश है जिसने संभावित सीएसआर गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक ढांचे के साथ सीएसआर खर्च को अनिवार्य किया है।

अधिनियम अनिवार्य करता है कि प्रत्येक कंपनी जिस पर सीएसआर मानदंड लागू होता है, बोर्ड की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का गठन करेगी।

अधिनियम के भीतर सीएसआर प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक कारोबार:

- 1,000 करोड़ और अधिक, या
- नेट वर्थ/शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपये और अधिक, या
- शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये और अधिक

अधिनियम के तहत कंपनियों को तीन ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता है।

यदि कोई कंपनी सीएसआर खर्च से संबंधित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहती है, अव्यतीत राशि (unspent amount) को स्थानांतरित करने और उपयोग करने के लिए, कंपनी को न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो कि 25 लाख रुपये तक बढ़ सकता है।

इसके अलावा, ऐसी कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो अनुपालन में चूक करता है, एक सजा के लिए उत्तरदायी होगा जो कि एक साल के लिए कारावास है जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना जो 5 लाख रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ हो सकता है।

Q. 72) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के रूप में योग्य हैं?

1. कंपनी परिसर में पौधरोपण
2. विकलांग लोगों के लिए नौकरियाँ
3. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान
4. स्वच्छ भारत कोष में योगदान
5. राजनीतिक दल में योगदान

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1, 2, 3 और 4
- c) केवल 3 और 4
- d) केवल 3, 4 और 5

Q. 72) Solution (c)

सीएसआर के तहत एक कंपनी द्वारा की जा सकने वाली सांकेतिक गतिविधियों को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किया गया है। गतिविधियों में शामिल हैं:

- भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जिसमें निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता शामिल है, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है।
- शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण,
- ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (Human Immunodeficiency Virus), एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम (Acquired Immune Deficiency Syndrome) और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना,

- पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना;
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं आदि के कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान।

सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों को सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाता है:

- व्यवसाय के सामान्य क्रम में की जाने वाली गतिविधियाँ (कंपनी परिसर में पेड़ लगाना, विकलांग लोगों के लिए नौकरी और ईंधन कुशल कार्यालय करें)
- भारत के बाहर की गई गतिविधि
- सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां जो केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाती हैं, उन्हें सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा।
- अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान सीएसआर गतिविधि के रूप में नहीं माना जाएगा।
- गतिविधि 2013 अधिनियम की अनुसूची VII के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- मैराथन/पुरस्कार/धर्मार्थ योगदान/विज्ञापन/टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजन आदि जैसे एकमुश्त आयोजन सीएसआर व्यय के भाग के रूप में योग्य नहीं होंगे।
- किसी भी अधिनियम/विनियमों के कानून (जैसे श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि) की पूर्ति के लिए कंपनियों द्वारा किए गए व्यय को कंपनी अधिनियम के तहत सीएसआर व्यय के रूप में नहीं गिना जाएगा।

Q. 73) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक सांविधिक निगम (statutory corporation) एक विभाग उपक्रम (department undertaking) की तुलना में अधिक सरकारी नियंत्रण और विनियमन के अधीन है।
2. एक सांविधिक निगम जनता से धन उधार नहीं ले सकता है, जबकि एक विभाग उपक्रम जनता से धन उधार ले सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 73) Solution (d)

विभागीय उपक्रमों को किसी देश के सार्वजनिक उद्यमों (public enterprises) के सबसे सामान्य और स्थापित रूपों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह के उद्यम को उस देश की सत्तारूढ़ सरकार द्वारा ही वित्तपोषित और संगठित और प्रबंधित किया जाता है। विभागीय उपक्रमों के कुछ उदाहरण भारतीय रेलवे, डाक और तार, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि हैं।

सांविधिक निगम संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाए गए सार्वजनिक उद्यम हैं। अधिनियम अपनी शक्तियों और कार्यों, अपने कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों और सरकारी विभागों के साथ इसके संबंधों को परिभाषित करता है।

विभाग के उपक्रम और सांविधिक निगमों के बीच मुख्य अंतर हैं:

- एक विभागीय उपक्रम के रूप में एक अलग कानूनी इकाई नहीं है, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, सांविधिक निगम की एक अलग कानूनी इकाई है, इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- एक विभागीय उपक्रम की निधि में सरकार द्वारा किया गया बजटीय आवंटन होता है। लेकिन एक सांविधिक निगम के फंड में सरकार द्वारा पूर्ण रूप से योगदान की गई शेयर पूंजी और सरकार या जनता से निगम द्वारा उधार ली गई धनराशि शामिल होती है।
- एक विभागीय उपक्रम एक सांविधिक निगम की तुलना में अधिक सरकारी नियंत्रण और विनियमन के अधीन है।
- एक विभागीय उपक्रम जनता से धन उधार नहीं ले सकता है। लेकिन एक सांविधिक निगम जनता से धन उधार ले सकता है।
- एक विभागीय संगठन किसी अधिनियम द्वारा नहीं बनाया जाता है, जबकि एक सांविधिक निगम संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा बनाया जाता है।

Q. 74) निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) की स्थापना का उद्देश्य है?

1. सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे का विकास
2. संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्राप्ति
3. नियोजित संसाधन आवंटन की प्राप्ति

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 74) Solution (d)

भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) या सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कहा जाता है। ये कंपनियां पूर्ण या आंशिक रूप से भारत सरकार या कई राज्य या क्षेत्रीय सरकारों में से एक या दोनों भागों में एक साथ स्वामित्व में हैं। इन संस्थाओं और उनकी सहायक कंपनियों के लिए काम करने वाले अधिकारी राजपत्रित अधिकारी हैं।

निम्नलिखित बिंदु भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को उजागर करते हैं:

- सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे का विकास: सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता, विशेष रूप से बुनियादी और भारी उद्योगों और परिवहन और संचार सुविधाओं की अपर्याप्तता, कम से कम विकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन का निकटतम कारण है। चूंकि अवसंरचनात्मक उद्योगों के विकास के लिए भारी प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें लंबी अवधि शामिल होती है और बहुत कम प्रारंभिक प्रतिफल प्राप्त होता है, निजी निवेशक ऐसी निवेश परियोजनाओं से दूर हो जाते हैं। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उन उद्योगों को विकसित करना सही है जिनमें निजी क्षेत्र असमर्थ है और आवश्यक संसाधनों को लगाने और इसमें शामिल जोखिमों को उठाने के लिए तैयार नहीं है।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्राप्ति: भारत सरकार की औद्योगिक नीति का एक घोषित उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करना रहा है। इसलिए सरकार ने लगातार आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के स्थान को प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- नियोजित संसाधन आवंटन की प्राप्ति: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को योजनाकारों और नीति निर्माताओं को देश की विकास रणनीतियों के अनुरूप बेहतर संसाधन आवंटन प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लघु और कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करके गरीबी को कम किया जा सके और आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से व्यापार की स्थिति के संतुलन में सुधार किया जा सके।

Q. 75) विनिवेश (disinvestment) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. विनिवेश से राजकोष पर राजकोषीय बोझ बढ़ जाता है।
2. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को भारत की संचित निधि में रखा जाता है।
3. विनिवेश निधि का उपयोग बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 3
- c) केवल 1 और 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 75) Solution (b)

विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन, आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, परियोजनाएं, या अन्य अचल परिसंपत्ति।

सरकार राजकोष पर राजकोषीय बोझ को कम करने, या विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए विनिवेश करती है, जैसे कि अन्य नियमित स्रोतों से राजस्व की कमी को पूरा करना। कुछ मामलों में, संपत्ति के निजीकरण के लिए विनिवेश किया जा सकता है।

भारत में विनिवेश के मुख्य उद्देश्य:

- राजकोष पर राजकोषीय बोझ को कम करना
- सार्वजनिक वित्त में सुधार
- निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना
- वित्त पोषण वृद्धि और विकास कार्यक्रम
- बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और बढ़ावा देना

वित्त मंत्रालय के तहत एक अलग विभाग है जो सरकार के लिए विनिवेश से संबंधित सभी कार्यों को देखता है जिसे निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के रूप में जाना जाता है।

सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) का गठन किया जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को रखा जाता है।

Q. 76) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने पिछले दो वर्षों में लगातार मुनाफा कमाया है और सकारात्मक निवल संपत्ति है उन्हें मिनीरत्न का दर्जा दिया जा सकता है।
2. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनके पास नवरत्न का दर्जा है और पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25000 करोड़ रुपये से अधिक है, को महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 76) Solution (b)

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड नीचे दिए गए हैं:

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा देने के लिए मानदंड

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले सीपीएसई महारत्न का दर्जा देने के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

- नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो
- सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध
- पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार।
- पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति।
- पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर के बाद एक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ।
- महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति/अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए।

नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंडः

मिनीरत्न श्रेणी - I और अनुसूची 'ए' सीपीएसई, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है, और चयनित छह में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर है। प्रदर्शन पैरामीटर, अर्थात्,

- निवल मूल्य से शुद्ध लाभ।
- उत्पादन/सेवाओं की कुल लागत के लिए जनशक्ति लागत।
- मूल्यहास पूर्व लाभ, नियोजित पूंजी पर ब्याज और कर।
- टर्नओवर के लिए ब्याज और करों से पूर्व लाभ।
- प्रति शेयर आय।
- अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन।

मिनीरत्न का दर्जा देने के लिए मानदंडः

जिन सीपीएसई ने पिछले तीन वर्षों में लगातार मुनाफा कमाया है और सकारात्मक निवल संपत्ति है, वे मिनीरत्न का दर्जा देने के लिए पात्र हैं।

Q. 77) निम्नलिखित में से कौन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) है/हैं?

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
3. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
4. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2

- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3 और 4
- d) केवल 1 और 4

Q.77) Solution (d)

महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं:

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. कोल इंडिया लिमिटेड
4. गेल (इंडिया) लिमिटेड
5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. एनटीपीसी लिमिटेड
8. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
9. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

Q. 78) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बीच अंतर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एनएसई के लिए बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स (SENSEX) है, जबकि बीएसई के लिए यह निफ्टी (Nifty) है।
2. सेंसेक्स इंडेक्स का मूल्य 50 सबसे बड़ी और सबसे अधिक बार कारोबार करने वाली कंपनियों से प्राप्त होता है।
3. बीएसई देश का सबसे पुराना वित्तीय बाजार है, जो अपने ग्राहकों को हाई स्पीड ट्रेडिंग की पेशकश करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 78) Solution (c)

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange -BSE):

- यह महाद्वीप का प्राचीन प्रतिभूति विनियम है, जिसे पहले वर्ष 1875 में 'द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन' के नाम से जाना जाता था।
- 1957 में, बीएसई को भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, 1956 के तहत देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी।
- सेंसेक्स को 1986 में पहली इक्विटी इंडेक्स के रूप में पेश किया गया था, जो 10 से अधिक क्षेत्रों में एक्सचेंज की शीर्ष 30 व्यापारिक कंपनियों की पहचान करने के लिए आधार प्रदान करता है। वर्ष 1995 में, बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम (बीओएलटी) शुरू किया गया था।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange -NSE):

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे युवा स्टॉक एक्सचेंज है जो 1992 में अस्तित्व में आया था।
- अपनी स्थापना के समय, इसने देश में पहली बार उन्नत इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली की शुरुआत की जिसने कागज आधारित निपटान प्रणाली को हटा दिया।
- निफ्टी लोकप्रिय सूचकांक है, जिसे 1995 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक्सचेंज के प्रदर्शन को मापने के आधार के रूप में कार्य करने के लिए पेश किया गया था। यह एक्सचेंज पर कारोबार करने वाली शीर्ष 50 कंपनियों को सूचीबद्ध करता है।

Q. 79) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए:

1. वचन पत्र /प्रोमिसरी नोट्स (Promissory notes)
2. डिबेंचर
3. शेयर

उपरोक्त में से कौन से ऋण बाजार के साधन हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 79) Solution (a)

ऋण बाजार:

- एक ऋण साधन एक निश्चित आय संपत्ति है जो ऋणदाता (या दाता) को मूलधन वापस पाने के अलावा उस पर एक निश्चित ब्याज अर्जित करने की अनुमति देता है, जबकि जारीकर्ता (या लेने वाला) इसका उपयोग लागत पर धन जुटाने के लिए कर सकता है।

- ऋण जारीकर्ता (या लेने वाले) के हिस्से पर उधार ली गई राशि को ब्याज के साथ समय पर चुकाने के लिए कानूनी दायित्व के रूप में कार्य करता है।
- एक ऋण साधन कागज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है।
- बांड, डिबेंचर, पट्टे, प्रमाण पत्र, विनिमय के बिल और वचन पत्र ऋण साधनों के उदाहरण हैं।

एक इक्विटी बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें कंपनियों के शेयर जारी और कारोबार किए जाते हैं, या तो एक्सचेंजों या ओवर-द-काउंटर बाजारों के माध्यम से। शेयर बाजार के रूप में भी जाना जाता है, यह बाजार अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

Q.80) शेयर बाजार के संदर्भ में "पेनी स्टॉक्स" (Penny Stocks) शब्द का क्या अर्थ है?

- a) ये ऐसे स्टॉक हैं जो उच्च लाभांश का भुगतान नहीं करते हैं क्योंकि कंपनी आय को फिर से निवेश करना पसंद करती है ताकि इसे तेजी से बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके।
- b) ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी कीमतें आंतरिक मूल्य से अधिक होती हैं और इन्हें अधिक मूल्य वाला माना जाता है।
- c) ये ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत कम कीमत पर व्यापार करते हैं, जिनका बाजार पूंजीकरण बहुत कम होता है, ज्यादातर तरल होते हैं, और आमतौर पर एक छोटे एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं।
- d) ये उन कंपनियों के शेयर होते हैं जिनकी देनदारियां कम होती हैं और आमदनी स्थिर होती है और जो नियमित लाभांश का भुगतान करती हैं।

Q. 80) Solution (c)

पेनी स्टॉक्स:

- पेनी स्टॉक वे होते हैं जो बहुत कम कीमत पर व्यापार करते हैं, जिनका बाजार पूंजीकरण बहुत कम होता है, ज्यादातर तरल होते हैं, और आमतौर पर एक छोटे एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं।
- भारतीय शेयर बाजार में पेनी स्टॉक्स की कीमत 10 रुपये से कम हो सकती है।
- ये स्टॉक प्रकृति में सट्टेबाजी वाले होते हैं और तरलता की कमी, शेयरधारकों की कम संख्या, बड़ी लार्ज बिड-आस्क स्प्रेड (large bid-ask spread) और सूचना के सीमित प्रकटीकरण के कारण अत्यधिक जोखिम भरा माना जाता है।
- पेनी स्टॉक्स के लिए बहुत सारे डाउनसाइड हैं, क्योंकि वे कीमतों में हेराफेरी, अचानक डीलिटिंग और नियामक जांच के लिए प्रवण हैं।
- कोई भी हजारों शेयर खरीदकर स्टॉक को स्थानांतरित कर सकता है और बिना कोई संकेत छोड़े स्पाइक बना सकता है यह जानने के लिए कि कीमत में उछाल वास्तविक है या हेरफेर हुआ है।
- साथ ही, पेनी स्टॉक में घोटालों की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वे अक्सर राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनियमित नहीं होते हैं।
- इन सभी जोखिमों के कारण, स्टॉक एक्सचेंज इस प्रकार के स्टॉक को एक अलग श्रेणी में रखते हैं, जिसे ट्रेड-टू-ट्रेड बास्केट (trade-to-trade basket) कहा जाता है। इस श्रेणी में, किसी भी इंटराडे शेयर ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। लेन-देन को अनिवार्य

रूप से सकल आधार पर तय किया जाना है, जिसका अर्थ है कि आपको उसी दिन शेयरों को वितरित करना होगा यदि आपने उन्हें बेचा है या यदि आपने उन्हें खरीदा है तो डिलीवरी लें।

Q. 81) निम्नलिखित कथनों के संबंध में पर विचार करें:

1. भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के सभी अंतरराष्ट्रीय दृश्य और अदृश्य आर्थिक लेनदेन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है।
2. व्यापार संतुलन वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात से संबंधित है।
3. चालू खाता घाटा तब होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 81) Solution (a)

भुगतान संतुलन (BOP) सभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान किसी देश के दृश्यमान और अदृश्य होते हैं। दूसरे शब्दों में, बीओपी विवरण एक देश के निवासियों और अन्य देशों के निवासियों के बीच एक निश्चित अवधि के भीतर सभी आर्थिक लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक साधन है।

बीओपी का विश्लेषण इसके दो प्रमुख उप-विभागों अर्थात (i) चालू खाता, और (ii) पूंजी खाते के संदर्भ में किया जा सकता है।

व्यापार संतुलन (बीओटी): बीओटी केवल माल (या दृश्यमान वस्तुओं) के निर्यात और आयात से संबंधित है। यह सेवाओं में व्यापार से संबंधित नहीं है। बीओटी में शुद्ध शेष देश के निर्यात और आयात में भिन्न का मौद्रिक मूल्य दिखाएगा।

सेवाओं में व्यापार संतुलन (बीओएस): बीओएस सेवाओं में व्यापार के कारण शुद्ध प्राप्ति दिखाता है, (या जिसे अदृश्य भी कहा जाता है)।

चालू खाते पर शेष राशि व्यापार संतुलन (बीओटी) और बीओएस (सेवाओं का संतुलन) का सकल या योग है।

चालू खाते पर शेष एक वर्ष के दौरान किसी देश की सभी मौजूदा विदेशी मुद्रा आय और वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय (ex) के रूप में इसकी देनदारियों को दर्शाता है। इसकी विदेशी मुद्रा आय वस्तु के निर्यात और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से उत्पन्न होने वाली प्राप्ति से आती है। इसका विदेशी मुद्रा व्यय वस्तु के आयात और विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारण भुगतान पर किया जाता है। जाहिर है, बीओटी और बीओएस की तरह, भुगतान संतुलन का चालू खाता निम्नलिखित तीन परिणामों में से कोई भी दिखा सकता है:

- चालू खाता घाटा: ये होगा। जब आयात < निर्यात।

- चालू खाता अधिशेष: ये होगा। जब आयात > निर्यात।
- चालू खाता शेष: ये होगा। जब आयात = निर्यात।

Q. 82) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पूंजी खाता राष्ट्र की संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन को दर्शाता है।
2. पूंजी खाते का प्रमुख घटक शुद्ध अंतरण आय (net transfer income) है।
3. पूंजी खाता लेनदेन के सामान्य रूपों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 82) Solution (b)

पूंजी खाता:

- पूंजी खाते में अंदर और बाहर प्रवाह निवेश, ऋण, बैंकिंग बैलेंस और वास्तविक संपत्ति मूल्य के माध्यम से परिसंपत्ति मूल्य में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। पूंजी खाता राष्ट्र की संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन को दर्शाता है।
- पूंजी खाता चालू खाते की तुलना में कम तात्कालिक और अधिक अदृश्य होता है।
- एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश और ऋण पूंजी खाते के प्रमुख घटक हैं।

वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात, निवेश आय और शुद्ध हस्तांतरण आय चालू खाते के प्रमुख घटक हैं।

Q. 83) निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी देश के चालू खाता शेष/बैलेंस को प्रभावित करते हैं?

1. मुद्रास्फीति
2. राष्ट्रीय आय
3. विनिमय दरें

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 83) Solution (d)

चालू खाता

किसी देश का चालू खाता शेष उसकी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं:

- मुद्रास्फीति: यदि किसी देश की मुद्रास्फीति दर उन देशों के सापेक्ष बढ़ जाती है जिनके साथ वह व्यापार करता है, तो उसके चालू खाते में कमी की उम्मीद की जाएगी। देश पर उच्च कीमतों के कारण, देश में उपभोक्ता और निगम विदेशों में अधिक सामान खरीदेंगे (उच्च स्थानीय मुद्रास्फीति के कारण), जबकि अन्य देशों में देश के निर्यात में गिरावट आएगी।
- राष्ट्रीय आय: यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय में अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो इसके चालू खाते में कमी होने की उम्मीद है, अन्य चीजें समान हैं। जैसे-जैसे वास्तविक आय स्तर (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) बढ़ता है, वैसे ही वस्तुओं की खपत भी बढ़ती है। खपत में उस वृद्धि का एक प्रतिशत सबसे अधिक संभावना विदेशी वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग को दर्शाएगा।
- सरकारी प्रतिबंध: यदि किसी देश की सरकार आयातित वस्तुओं (अक्सर टैरिफ के रूप में संदर्भित) पर कर लगाती है, तो उपभोक्ताओं के लिए विदेशी वस्तुओं की कीमतें प्रभावी रूप से बढ़ जाती हैं। घर में उत्पादित वस्तुओं के सापेक्ष आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आयात हतोत्साहित होगा और चालू खाते की शेष राशि में वृद्धि की उम्मीद है। टैरिफ के अलावा, सरकार कोटा या आयात पर अधिकतम सीमा लागू करके अपने आयात को कम कर सकती है।
- विनिमय दरें: विनिमय दरों के उपयोग के माध्यम से प्रत्येक देश की मुद्रा को अन्य मुद्राओं के संदर्भ में महत्व दिया जाता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की सुविधा के लिए मुद्राओं का आदान-प्रदान किया जा सके, बाजार और सरकारी बलों के कारण अधिकांश मुद्राओं के मूल्यों में समय के साथ उतार-चढ़ाव हो सकता है, यदि किसी देश की चालू खाता शेष/बैलेंस कम हो जाता है, अन्य चीजें समान रहती हैं, तो देश द्वारा निर्यात किया गया सामान आयात करने वाले देशों के लिए अधिक महंगा हो जाएगा, यदि इसकी मुद्रा मजबूत होती है, तो परिणामस्वरूप, ऐसे सामानों की मांग में गिरावट आएगी।

Q. 84) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भुगतान संतुलन विवरण में लेन-देन की रिकॉर्डिंग डबल एंट्री बुक-कीपिंग (double entry book-keeping) द्वारा की जाती है।
2. देश की ब्याज दरों में वृद्धि विदेशों से पूंजी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 84) Solution (a)

भुगतान संतुलन का निर्माण डबल एंट्री बुक-कीपिंग के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। इस प्रणाली के तहत एक लेन-देन भुगतान संतुलन में समान मूल्यों के साथ दो प्रविष्टियों द्वारा दर्शाया जाता है। इन प्रविष्टियों में से एक को क्रेडिट और दूसरे को डेबिट नामित किया गया है।

भुगतान संतुलन में प्रविष्टियाँ कैसे दर्ज की जाती हैं, इसे नियंत्रित करने वाले कुछ बुनियादी नियम हैं। एक क्रेडिट प्रविष्टि दर्ज की जाती है जब लेनदेन एक विदेशी निवासी से एक घरेलू निवासी द्वारा रिसीप्ट को उत्पन्न करता है। रिसीप्ट स्वयं निवासी की विदेशी संपत्ति या विदेशी मुद्राओं की शेष राशि में वृद्धि का रूप ले सकती है। इसका रूप जो भी हो, रसीद को डेबिट प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाता है। इसके विपरीत, कोई भी लेनदेन जो किसी निवासी द्वारा किसी विदेशी निवासी को भुगतान को जन्म देता है उसे डेबिट प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाता है। इस लेन-देन से होने वाले भुगतान को क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाता है।

उच्च ब्याज दरें विदेशी निवेश को आकर्षित करती हैं, जिससे देश की मुद्रा की मांग और मूल्य में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, कम ब्याज दरें विदेशों से पूंजी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

Q. 85) निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन (BOP) पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा?

- a) ब्याज दर में वृद्धि
- b) करों में वृद्धि
- c) पूंजी प्रवाह में वृद्धि
- d) मुद्रास्फीति दर में वृद्धि

Q. 85) Solution (d)

मुद्रास्फीति दर में वृद्धि का भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भुगतान संतुलन बिगड़ सकता है क्योंकि घरेलू मुद्रास्फीति आयात खर्च को प्रोत्साहित करती है, यह देखते हुए कि आयात अपेक्षाकृत सस्ता दिखाई देता है, और निर्यात बिक्री को कम करता है, क्योंकि विदेशों में निर्यात अधिक महंगा दिखाई देता है।

ब्याज दरों में वृद्धि से मुद्रा की मूल्यवृद्धि हो सकती है क्योंकि मुद्रा की मांग बढ़ती है। इसलिए, सकारात्मक रूप से भुगतान संतुलन को प्रभावित करते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में पूंजी प्रवाह में वृद्धि का किसी देश के भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कर ढांचे में वृद्धि का बीओपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यदि किसी देश की सरकार आयातित वस्तुओं पर कर लगाती है तो उपभोक्ताओं के लिए विदेशी वस्तुओं की कीमतें प्रभावी रूप से बढ़ जाती हैं। देश में उत्पादित वस्तुओं के सापेक्ष आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आयात हतोत्साहित होगा और चालू खाते की शेष राशि में वृद्धि की अपेक्षा की जाती है। उसी समय एक देश की सरकार, उदाहरण के लिए, विदेशी बाजारों में निवेश करने वाले स्थानीय निवेशकों द्वारा आय खाते पर एक विशेष कर लगा सकती

है। एक कर लोगों को विदेशी बाजारों में निवेश के लिए अपना धन भेजने से हतोत्साहित करेगा और इसलिए, देश के पूंजी खाते में वृद्धि कर सकता है।

Q. 86) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक अनिवासी ऋणदाता से एक भारतीय इकाई द्वारा लिया गया ऋण है।
2. ईसीबी का उपयोग शेयर बाजार में निवेश के लिए नहीं किया जा सकता है।
3. इसका ढांचा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (Export Import Bank of India) द्वारा तय किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) केवल 1 और 3

Q. 86) Solution (a)

बाहरी वाणिज्यिक उधार एक भारतीय इकाई द्वारा एक अनिवासी ऋणदाता से न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ लिया गया ऋण है।

भारतीय निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) द्वारा विदेशी धन तक पहुंच की सुविधा के लिए उनका भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार में वाणिज्यिक बैंक ऋण, क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, प्रतिभूतिकृत लिखत जैसे फ्लोटिंग दर नोट और निश्चित दर बांड आदि, आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसियों से ऋण और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन), एडीबी, एफआईसी, सीडीसी, आदि जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की निजी क्षेत्र की खिड़की से आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसियों और वाणिज्यिक उधार से ऋण शामिल हैं।

ईसीबी का उपयोग शेयर बाजार में निवेश या अचल संपत्ति में सट्टेबाजी के लिए नहीं किया जा सकता है।

डीईए (आर्थिक मामलों का विभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक, ईसीबी दिशानिर्देशों और नीतियों की निगरानी और विनियमन करता है।

ईसीबी के लाभ (Advantages of ECB):

- कम ब्याज दर वाली अर्थव्यवस्थाओं से उधार लेने पर फंड की लागत आमतौर पर बाहरी स्रोतों से सस्ती होती है।
- बड़े बाजार की उपलब्धता से कंपनियों को वैश्विक अभिकर्ताओं की बड़ी आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर हासिल की जा सकने वाली चीजों की तुलना में बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिल सकती है।
- यह उधारकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है और विश्व स्तर पर अवसरों के लिए अच्छा प्रदर्शन करता है।
- कम लागत वाले फंड के मार्ग कंपनियों की लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं और आर्थिक विकास में सहायता कर सकते हैं।

Q. 87) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने की स्वतंत्रता और इसके विपरीत वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार निष्पादित करने की दृष्टि से है।
2. आईएमएफ की स्थिति और दायित्वों के अनुरूप भारत चालू खाते पर पूरी तरह से परिवर्तनीय हो गया है।
3. भारत में आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 87) Solution (d)

मुद्रा परिवर्तनीयता का अर्थ घरेलू मुद्रा (रुपये) को अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं (जैसे डॉलर आदि) में बदलने की स्वतंत्रता है।

चालू खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है रुपये को डॉलर आदि में बदलने की स्वतंत्रता और इसके विपरीत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के लिए। इसमें उपहार, दान आदि जैसे एकतरफा हस्तांतरण करने/प्राप्त करने के लिए मुद्राओं को परिवर्तित करने और ब्याज, लाभांश आदि का भुगतान/प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी शामिल है।

भारत में, 1993 से पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता है। यह भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ अनुच्छेद VIII की स्थिति और दायित्वों को स्वीकार करने के बाद था।

पूंजी खाता परिवर्तनीयता विदेशी निवेशकों की भारतीय वित्तीय संपत्ति (शेयर, बांड, आदि) और भारतीय निवेशकों की विदेशी वित्तीय संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता है। इसमें वित्तीय संपत्तियों में निवेश करने की स्वतंत्रता शामिल है।

भारत में आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता है। इसका मतलब है कि पूंजी की आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध हैं।

Q. 88) निम्नलिखित में से कौन-सा/से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्यवृद्धि का प्रभाव है/हैं?

1. इससे देश का निर्यात बढ़ता है
2. विदेश से आने वाले प्रेषणों का मूल्य घटता है
3. यह मुद्रास्फीति में वृद्धि की ओर जाता है

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2

- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) केवल 1 और 3

Q. 88) Solution (b)

मुद्रा प्रशंसा विदेशी मुद्रा बाजारों में एक मुद्रा के सापेक्ष दूसरे के मूल्य में वृद्धि को दर्शाती है।

किसी मुद्रा का मूल्य निरपेक्ष रूप से नहीं मापा जाता है। इसे हमेशा मुद्रा के सापेक्ष मापा जाता है।

देश अपनी आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक साधन के रूप में मुद्रा मूल्य वृद्धि का उपयोग करते हैं।

जब किसी देश की मुद्रा का अभिमूल्यन होता है, तो अर्थव्यवस्था पर इसके कई अलग-अलग प्रभाव हो सकते हैं:

- मुद्रा का अभिमूल्यन अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बनाती है। इससे देश के निर्यात में कमी आती है।
- विदेशों से आने वाले प्रेषणों का मूल्य घरेलू मुद्रा में घट जाता है।
- आयात सस्ता हो जाता है और इस प्रकार समग्र वृद्धि और आयात होता है।
- समग्र मुद्रास्फीति घट सकती है क्योंकि आयात सस्ता हो जाएगा।
- घरेलू मुद्रा की लगातार अभिमूल्यन बीओपी को प्रतिकूल बना सकती है।

Q. 89) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मुद्रा अवमूल्यन तब होता है जब एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है।
2. मुद्रा अवमूल्यन देश के निर्यात की लागत को कम करता है, जिससे उन्हें वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 89) Solution (b)

मुद्रा अवमूल्यन तब होता है जब कोई देश अपनी विनिमय दर को एक निश्चित या अर्ध-स्थिर विनिमय दर में कम करने का सचेत निर्णय लेता है।

मुद्रा मूल्यहास तब होता है जब एक मुद्रा के मूल्य में एक अस्थायी विनिमय दर में गिरावट होती है।

व्यापार असंतुलन से निपटने के लिए कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है। अवमूल्यन से देश के निर्यात की लागत कम हो जाती है, जिससे वे वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, जिससे आयात की लागत बढ़ जाती है। यदि आयात अधिक महंगे हैं, तो घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उन्हें खरीदने की संभावना कम होती है, जिससे घरेलू व्यवसायों को और मजबूती मिलती है। क्योंकि निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है, आमतौर पर भुगतान संतुलन बेहतर होता है क्योंकि व्यापार घाटा कम हो जाता है। संक्षेप में, एक देश जो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है वह अपना घाटा कम कर सकता है क्योंकि सस्ते निर्यात की अधिक मांग है।

Q.90) मुद्रा के मूल्यहास होने पर निम्नलिखित में से किसकी हानि होती है?

1. आयातित कच्चा माल खरीदने वाली फर्में
2. निर्यात उद्योग में नौकरी पाने वाले श्रमिक
3. विदेश में छुट्टियां मनाने वाले निवासी

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 90) Solution (c)

मुद्रा अवमूल्यन के प्रभाव:

- विनिमय दर का अवमूल्यन निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा और विदेशियों को सस्ता दिखाई देगा। इससे निर्यात की मांग बढ़ेगी।
- अवमूल्यन का मतलब है कि पेट्रोल, भोजन और कच्चे माल जैसे आयात अधिक महंगे हो जाएंगे। इससे आयात की मांग में कमी आएगी।
- अवमूल्यन उच्च आर्थिक विकास का कारण बन सकता है।
- निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी और आयात अधिक महंगा होने के कारण, हमें उच्च निर्यात और कम आयात देखना चाहिए, जिससे चालू खाता घाटा कम होगा।

इस प्रकार मुद्रा मूल्यहास या अवमूल्यन होने पर निम्नलिखित की हानि होती है:

- आयात खरीदने वाले उपभोक्ता
- विदेश में छुट्टियां मनाने वाले निवासी
- आयातित कच्चा माल खरीदने वाली फर्में

- जो निश्चित आय/मजदूरी पर हैं
- विदेशी निर्यातक

मुद्रा का अभिमूल्यन होने पर निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

- निर्यातकों
- घरेलू पर्यटन उद्योग
- निर्यात उद्योग में रोजगार पाने वाले श्रमिक

Q. 91) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली (floating exchange rate system) के तहत केंद्रीय बैंक विनिमय दर को अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख मुद्राओं से जोड़कर आधिकारिक विनिमय दर निर्धारित करता है।
2. फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली अधिमूल्यन (appreciation) तथा मूल्यहास (depreciation) दोनों को रोकती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 91) Solution (d)

फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली:

- इस प्रणाली के तहत, बाजार को विनिमय दर के मूल्य को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने की अनुमति है।
- विनिमय दर मांग और आपूर्ति की तत्वों द्वारा निर्धारित की जाती है।
- यदि किसी कारण से विनिमय दर में उतार-चढ़ाव होता है, तो सरकार कभी हस्तक्षेप नहीं करती है और बाजार को कार्य करने और विनिमय दर का सही मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देती है।
- इस तरह की प्रणाली के लाभ हैं: विनिमय दर बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अच्छी तरह से काम कर रहे विदेशी मुद्रा बाजारों में निर्धारित की जाती है।
- विनिमय दर घरेलू मुद्रा के सही मूल्य को दर्शाती है जो विदेशी निवेशकों के बीच विश्वास स्थापित करने में मदद करती है।
- एक देश आसानी से आईएमएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से धन/ऋण प्राप्त कर सकता है यदि विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित है।

- अस्थायी विनिमय दर प्रणाली का एकमात्र दोष यह है कि विनिमय दर में दिन-प्रतिदिन के आधार पर बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता है, इस प्रकार मौद्रिक अधिमूल्यन या मूल्यहास को नहीं रोकता है।

Q. 92) प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर (Managed Floating Exchange rate) के उप-वर्गीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एडजस्टेड पैग सिस्टम (adjusted peg system) के तहत एक देश अपनी विनिमय दर को नई मांग और आपूर्ति की स्थिति में समायोजित करता रहता है।
2. क्रॉलिंग पेग सिस्टम (crawling peg system) के तहत एक देश एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली को तब तक बनाए रखने की कोशिश करता है जब तक कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त न हो जाए, उसके बाद उसका अवमूल्यन हो जाता है।
3. डर्टी फ्लोटिंग प्रणाली (dirty floating system) में विनिमय दर काफी हद तक मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है लेकिन कभी-कभी किसी देश का केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजारों से अत्यधिक उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) केवल 1 और 3

Q. 92) Solution (c)

प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर:

प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर स्थिर और अस्थायी विनिमय दर के दो चरम सीमाओं के बीच में स्थित है। ऐसी प्रणाली के तहत, विनिमय को बाजार की शक्तियों (मांग और आपूर्ति) द्वारा स्वतंत्र रूप से और निर्धारित करने की अनुमति है। लेकिन जब कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो देश के केंद्रीय बैंक विनिमय दर को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं।

प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर के अंतर्गत मुख्यतः तीन उप श्रेणियां हैं:

- **एडजस्टेड पैग सिस्टम:** इस प्रणाली में, एक देश को एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली को तब तक धारण करने का प्रयास करना चाहिए, जब तक कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त न हो जाए। एक बार जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जाता है, तो देश को मुद्रा के अवमूल्यन करना होगा तथा अन्य संतुलित विनिमय दर अपनाना होगा।
- **क्रॉलिंग पेग सिस्टम:** इस प्रणाली में, एक देश अपनी विनिमय दर को नई मांग और आपूर्ति की स्थिति में समायोजित करता रहता है। प्रणाली की आवश्यकता है कि संकट के समय मुद्रा का अवमूल्यन करने के बजाय, एक देश को विनिमय दर पर नियमित जांच का पालन करना चाहिए और जब आवश्यकता हो तो छोटे अवमूल्यन करना चाहिए।

- क्लीन फ्लोटिंग: क्लीन फ्लोट सिस्टम में, विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। बाजार की शक्तियों के अनुसार और बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के विनिमय दर की मूल्य वृद्धि या मूल्यहास होता है। यह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के समान है।
- डर्टी फ्लोटिंग: डर्टी फ्लोट सिस्टम में, विनिमय दर काफी हद तक मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों (अब तक क्लीन फ्लोटिंग के समान) द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन कभी-कभी देशों के केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करते हैं। जो विदेशी मुद्रा बाजारों से अत्यधिक उतार-चढ़ाव को सुगम बनाने या हटाने के लिए होता है।

Q. 93) विस्तारित निधि सुविधा (Extended Fund Facility -EFF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विश्व बैंक की ऋण सुविधा है।
2. यह देशों को भुगतान संतुलन की मध्यम और लंबी अवधि की समस्याओं से निपटने में मदद करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 93) Solution (b)

विस्तारित निधि सुविधा (Extended Fund Facility -EFF):

- विस्तारित निधि सुविधा आईएमएफ के फंड की उधार सुविधा है और इसे 1974 में स्थापित किया गया था ताकि देशों को भुगतान समस्याओं के मध्यम और दीर्घकालिक संतुलन को दूर करने में मदद मिल सके।
- EFF एक ऐसे देश के लिए निर्धारित है जो संरचनात्मक कमजोरियों के कारण भुगतान संतुलन की समस्या से पीड़ित है और जिसे मूलभूत आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है।
- एक ईएफएफ एक विस्तारित अवधि में संरचनात्मक असंतुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक नीतियों सहित व्यापक कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता है।
- विस्तारित व्यवस्थाओं को आम तौर पर तीन साल की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाता है, लेकिन गहरे और निरंतर संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए 4 साल तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया जा सकता है।
- EFF के तहत आहरित राशि को साढ़े चार से दस वर्षों में 12 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाना होता है।
- जब कोई देश आईएमएफ से उधार लेता है, तो वह आर्थिक और संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने के लिए नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक ईएफएफ के तहत, विशिष्ट परिस्थितियों सहित इन प्रतिबद्धताओं से व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतियों के अलावा, संस्थागत या आर्थिक कमजोरियों को दूर करने के लिए संरचनात्मक सुधारों पर एक मजबूत ध्यान देने की आशा की जाती है।

Q. 94) वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अन्य प्रमुख मुद्राओं के सूचकांक या बास्केट के संबंध में किसी देश की मुद्रा का भारित औसत है।
2. किसी देश के आरईईआर में वृद्धि इस बात का संकेत है कि उसका आयात अधिक महंगा होता जा रहा है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 94) Solution (a)

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (Real Effective Exchange Rate -REER):

- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) किसी देश के मुद्रा मूल्य की तुलना उसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के भारित औसत से करती है।
- यह अपने व्यापार भागीदारों की तुलना में किसी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेतक है।
- देश में प्रत्येक व्यापारिक भागीदार के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखने के लिए सूत्र को भारित किया जाता है।
- किसी देश के आरईईआर में वृद्धि इस बात का संकेत है कि उसका निर्यात अधिक महंगा होता जा रहा है और उसका आयात सस्ता होता जा रहा है। यह अपनी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता खो रहा है। आरईईआर का बढ़ना यह दर्शाता है कि एक देश अपनी प्रतिस्पर्धा में बढ़त खो रहा है।
- आरईईआर एक राष्ट्र और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच द्विपक्षीय विनिमय दरों का औसत निकालकर और फिर प्रत्येक भागीदार के व्यापार आवंटन को ध्यान में रखते हुए इसे भारित करके निर्धारित किया जाता है।
- आरईईआर का उपयोग किसी देश की मुद्रा के संतुलन मूल्य को मापने के लिए किया जा सकता है, किसी देश के व्यापार प्रवाह के अंतर्निहित कारकों की पहचान करने के लिए, और अन्य कारकों, जैसे प्रतिस्पर्धा और तकनीकी परिवर्तन, का किसी देश पर और अंततः व्यापार-भारित सूचकांक का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

Q. 95) नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (NEER) और 'रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट' (REER) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब NEER गुणांक 1.0 से ऊपर होता है तो यह दर्शाता है कि घरेलू मुद्रा का मूल्य आयातित मुद्राओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
2. देश में मुद्रास्फीति में वृद्धि के मामले में मुद्रा का NEER, मुद्रा के REER से अधिक हो जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 95) Solution (d)

नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (एनईईआर):

एनईईआर का उपयोग विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) बाजार के भीतर किसी देश की मुद्रा की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और मजबूती को मापने के लिए किया जाता है। एनईईआर को मुद्रा के रूप में एक उपाय के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है; इसके बजाय, यह एक व्यापक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, आमतौर पर एक सूचकांक में।

एक एनईईआर गुणांक जो 1.0 से ऊपर है, यह दर्शाता है कि घरेलू मुद्रा का मूल्य आयातित मुद्राओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। यदि एनईईआर गुणांक 1.0 से नीचे है, तो यह दर्शाता है कि घरेलू मुद्रा का मूल्य आयातित मुद्राओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

यदि किसी देश की मुद्रा अस्थायी विनिमय दरों वाली अन्य मुद्राओं की बास्केट के सापेक्ष बढ़ती है, तो एनईईआर में वृद्धि होगी। यह संकेत देता है कि घरेलू मुद्रा की प्रत्येक इकाई के लिए औसतन अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है।

जब मुद्रास्फीति के भार को एनईईआर के साथ समायोजित किया जाता है, तो हमें 'रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) प्राप्त होती है।

इसलिए, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मुद्रा का आरईआर मुद्रा के एनईईआर से अधिक हो जाता है।

Q. 96) क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पीपीपी का उपयोग दुनिया भर में विभिन्न देशों में आय के स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है।
2. पीपीपी विनिमय दरों का उपयोग वैश्विक गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए विश्व के कुछ सबसे गरीब देशों की राष्ट्रीय गरीबी रेखा को बदलने के लिए किया जाता है।
3. पीपीपी के मामले में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 96) Solution (b)

क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity -PPP):

- क्रय शक्ति समता (पीपीपी) मैक्रोइकॉनॉमिक विश्लेषकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक लोकप्रिय मीट्रिक है जो "वस्तुओं की टोकरी" दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न देशों की मुद्राओं की तुलना करती है।
- विभिन्न देशों में आय के स्तर की तुलना करने के लिए दुनिया भर में क्रय शक्ति समता का उपयोग किया जाता है। पीपीपी इस प्रकार प्रत्येक देश के डेटा को समझना और उसकी व्याख्या करना आसान बनाता है।
- पीपीपी विनिमय दरों का उपयोग वैश्विक गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों की राष्ट्रीय गरीबी रेखा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।
- भारत में गरीबी के आकलन के लिए, तेंदुलकर समिति ने 2004-05 के लिए गरीबी रेखा की गणना एक स्तर पर की, जो पीपीपी के संदर्भ में, प्रति दिन 33 रुपये के बराबर थी।
- क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के मामले में, भारत 8.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है। चीन 24.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि यूएसए 20.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है।
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है।
- पीपीपी के आधार पर जीडीपी को विभिन्न मुद्राओं वाले देशों के बीच अधिक आसानी से तुलनीय संख्या में बदलने का प्रयास करता है।
- दो मुद्राओं के लिए क्रय शक्ति समता की गणना माल और सेवाओं की एक टोकरी/बास्केट का उपयोग करके की जाती है - किराया, किराने का सामान, यात्रा, मनोरंजन, ईंधन, कपड़े आदि।
- 2020 में, भारत के लिए क्रय शक्ति समानता 22 स्थानीय मुद्रा इकाइयाँ (LCU) प्रति अंतर्राष्ट्रीय डॉलर थी। INR और USD के बीच आधिकारिक विनिमय दर 75 रुपये प्रति अंतर्राष्ट्रीय डॉलर है।
- इसका मतलब है कि भारत में आपको वही सामान/सेवाएं खरीदने के लिए सिर्फ 22 रुपये चाहिए जो आप यूएस में 1 डॉलर में खरीद सकते हैं न कि 75 रुपये क्योंकि यहां जीवन निर्वाह की लागत कम है। इसका मतलब है कि आप भारत में 1 डॉलर के बराबर रुपये के साथ 75 को 22 से विभाजित, यानी समान सामान / सेवाओं की 3.4 यूनिट खरीद सकते हैं।

Q. 97) जे-वक्र प्रभाव (J-curve effect) क्या है?

- a) यह एक प्रकार के उत्पाद की मात्रा को दर्शाता है जिसे एक एजेंट दूसरे प्रकार के उत्पाद की प्रत्येक मात्रा के लिए निर्यात करेगा जिसे वह आयात करता है।
- b) यह एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जिसमें किसी देश का व्यापार संतुलन सुधरने से पहले उसकी मुद्रा के मूल्यहास होने के पश्चात और अधिक बिगड़ जाती है।
- c) इसका अर्थ है कि एक फर्म किसी विशेष वस्तु या सेवा का जितना अधिक उत्पादन करती है, उतनी ही अधिक दक्षता में उसे लाभ होता है।
- d) यह उन निर्यात-आयात संयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके प्रति निर्धारित देश उदासीन है।

Q. 97) Solution (b)

जे-वक्र (J-curve) :

- एक जे-वक्र एक प्रवृत्ति को दर्शाता है जो एक तेज गिरावट के साथ शुरू होती है और उसके बाद एक नाटकीय वृद्धि होती है।
- ट्रेडलाइन शुरुआती बिंदु से सुधार में समाप्त होती है।
- अर्थशास्त्र में, जे-वक्र दिखाता है कि कैसे मुद्रा मूल्यहास एक व्यापार असंतुलन के गंभीर रूप से बिगड़ने का कारण बनता है जिसके बाद पर्याप्त सुधार होता है।
- जे-वक्र चिकित्सा और राजनीति विज्ञान सहित अन्य क्षेत्रों में देखे जाते हैं। प्रत्येक मामले में, यह एक प्रारंभिक हानि को दर्शाता है जिसके बाद एक महत्वपूर्ण लाभ उस स्तर तक पहुंच जाता है जो प्रारंभिक बिंदु से अधिक हो जाता है।

अर्थशास्त्र में, इसका उपयोग अक्सर व्यापार संतुलन पर कमजोर मुद्रा के प्रभावों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। पैटर्न इस प्रकार है:

- किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के तुरंत बाद, आयात अधिक महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है, जिससे व्यापार घाटा बिगड़ता है (या कम से कम एक निम्न व्यापार अधिशेष)।
- इसके तुरंत बाद, देश के निर्यात की बिक्री मात्रा में तेजी से वृद्धि शुरू होती है, उनकी अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों के कारण।
- उसी समय, घर पर उपभोक्ता स्थानीय रूप से उत्पादित सामान अधिक खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे आयात की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं।
- समय के साथ, राष्ट्र और उसके भागीदारों के बीच व्यापार संतुलन वापस उछलता है और यहां तक कि पूर्व-अवमूल्यन समय से भी अधिक हो जाता है।
- जब किसी देश की मुद्रा की मूल्य वृद्धि होती है, अर्थशास्त्रियों ने ध्यान दिया, एक रिवर्स जे-वक्र हो सकता है।

Q. 98) विभिन्न प्रकार के व्यापार समझौतों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पीटीए (PTA) देशों के बीच आर्थिक एकीकरण का पहला चरण है।
2. सीईपीए (CEPA) में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते सीईसीए की तुलना में व्यापक दायरा है।
3. सीईसीए (CECA) मुख्य रूप से व्यापार निवेश और सेवाओं के संदर्भ में टैरिफ कटौती और सहयोग से संबंधित है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) केवल 1 और 3

Q. 98) Solution (a)

एक तरजीही व्यापार समझौता (पीटीए) एक व्यापारिक ब्लॉक है जो भाग लेने वाले देशों के कुछ उत्पादों के लिए तरजीही पहुंच प्रदान करता है। यह टैरिफ को कम करके किया जाता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से समाप्त करके नहीं। एक पीटीए एक व्यापार समझौते के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। यह आर्थिक एकीकरण का पहला चरण है।

व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) भारत और अन्य देशों के बीच आर्थिक समझौतों के रूप हैं

सीईसीए सीईपीए के लिए एक प्रारंभिक प्रयास है। सीईपीए के पक्षों और मदों के मामले में भी व्यापक गुंजाइश है।

सीईसीए ज्यादातर टैरिफ को खत्म करने या घटाने से संबंधित है जबकि सीईपीए की चिंताएं निवेश और सेवाओं को जोड़ने के साथ समान हैं।

भारत का सीईसीए है: मलेशिया, सिंगापुर के साथ

भारत का सीईपीए है: जापान, दक्षिण कोरिया के साथ

Q. 99) जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल (GAAR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक कर-अपवंचन विरोधी कानून है।
2. GAAR के प्रावधान प्रत्यक्ष कर संहिता 2010 के तहत आते हैं।
3. यह कर अधिकारियों को पार्टिसीपेटरी नोट को लक्षित करने की अनुमति देता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q.99) Solution (c)

जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल (General anti-avoidance rule -GAAR):

- यह भारत के आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X-A के तहत एक कर-अपवंचन विरोधी कानून है।
- इसे वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है।
- GAAR मूल रूप से प्रत्यक्ष कर संहिता 2009 में प्रस्तावित किया गया था और विशेष रूप से करों से बचने के लिए की गई व्यवस्था या लेनदेन पर लक्षित था। प्रत्यक्ष कर संहिता 2010 और प्रत्यक्ष कर संहिता 2013 में भी गार प्रावधान मौजूद थे। हालांकि, प्रत्यक्ष कर संहिता अस्तित्व में नहीं आया और भारत में इसे लागू नहीं किया गया।

- गार को अंततः भारत में 2012 में पेश किया गया था।
- यह नियम कर अधिकारियों को कर लाभ से इनकार करने की अनुमति देता है, अगर कोई सौदा कर से बचने के अलावा किसी अन्य वाणिज्यिक उद्देश्य के बिना पाया जाता है।
- यह कर अधिकारियों को सहभागी नोट (participatory note) को लक्षित करने की अनुमति देता है। गार के तहत, निवेशक को यह साबित करना होगा कि करों से बचने के लिए सहभागी नोट सेट नहीं किया गया था।
- यह अधिकारियों को दोहरे कराधान से बचाव के लाभों से इनकार करने की भी अनुमति देता है, अगर टैक्स हेवन में किए गए सौदे करों से बचने के लिए पाए जाते हैं।

Q.100) निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है?

- a) सोना
- b) विशेष आहरण अधिकार
- c) आईएमएफ के साथ रिजर्व स्थिति
- d) विदेशी मुद्रा संपत्ति

Q. 100) Solution (d)

विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्ति है, जिसमें बांड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA)
- सोना
- विशेष आहरण अधिकार
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ रिजर्व स्थिति

विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा योगदान विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सोना, एसडीआर और रिजर्व है।

विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य:

- इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरबीआई के पास बैकअप फंड हो, यदि उनकी राष्ट्रीय मुद्रा तेजी से अवमूल्यन या पूरी तरह से दिवालिया हो जाती है।
- यदि विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि के कारण रुपये का मूल्य घटता है तो आरबीआई भारतीय मुद्रा बाजार में डॉलर बेचता है ताकि भारतीय मुद्रा के मूल्यहास की जांच की जा सके।

- विदेशी मुद्रा के अच्छे स्टॉक वाले देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी छवि होती है क्योंकि व्यापारिक देश अपने भुगतान के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं।
- एक अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी व्यापार को आकर्षित करने में मदद करता है और व्यापारिक भागीदारों में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करता है।

Q. 101) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (WB) के कामकाज में अंतर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आईएमएफ का लक्ष्य मध्यम आय वाले और निम्न आय वाले देशों को सहायता प्रदान करके गरीबी को कम करना है।
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का प्राथमिक फोकस आर्थिक विकास है जबकि विश्व बैंक (WB) का आर्थिक स्थिरता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 101) Solution (d)

दोनों संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (WB), वाशिंगटन, डी.सी (D.C.) में स्थित हैं, और 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौते के हिस्से के रूप में स्थापित किए गए थे।

ब्रेटन वुड्स समझौता एक मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली थी जिसने निश्चित विनिमय दरों पर परिवर्तनीय मुद्राओं की एक प्रणाली की शुरुआत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के बीच मुख्य अंतर उनके संबंधित उद्देश्यों और कार्यों में निहित है। आईएमएफ दुनिया की मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता की देखरेख करता है, जबकि विश्व बैंक का लक्ष्य मध्यम-आय और निम्न-आय वाले देशों को सहायता प्रदान करके गरीबी को कम करना है।

अपने मिशन को बनाए रखने के लिए, आईएमएफ आर्थिक गतिविधियों की निगरानी करता है, सदस्यों को नीति निर्धारण उपकरण और विश्लेषण प्रदान करता है, और सदस्य देशों को ऋण भी प्रदान करता है।

विश्व बैंक तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करता है जो देशों को विशिष्ट परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र बनाना या स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना।

इस प्रकार आईएमएफ का प्राथमिक फोकस सदस्य देशों की आर्थिक स्थिरता है जबकि डब्ल्यूबी का आर्थिक विकास और संवृद्धि है।

Q. 102) निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है?

- a) निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र

- b) अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक
- c) बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी
- d) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

Q. 102) Solution (b)

विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है।

विश्व बैंक समूह पांच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है, और विश्व बैंक का मूल संगठन, पहले दो सूचीबद्ध संगठनों, आईबीआरडी (IBRD) और आईडीए (IDA) को सामूहिक नाम दिया गया है:

- पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
- बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)
- निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)

अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक (IIB) एक बहुपक्षीय विकास संस्थान है जिसका मुख्यालय बुडापेस्ट, हंगरी में है। IIB अपने सदस्यों की अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने के उद्देश्य से परियोजनाओं के मध्यम और दीर्घकालिक वित्तपोषण में विशेषज्ञता रखता है, जिसका एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव होगा।

IIB के सदस्य राष्ट्र: बल्गारिया, क्यूबा, चेक गणराज्य, हंगरी, मंगोलिया, रोमानिया, रूस, स्लोवाकिया और वियतनाम हैं।

Q. 103) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. IFC सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर विशेष रूप से केंद्रित है।
2. इसका उद्देश्य गरीबी कम करने के लिए लाभकारी और वाणिज्यिक परियोजनाओं में निवेश करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 103) Solution (c)

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाहकार और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है।

आईएफसी (IFC) विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन, डीसी में है।

इसकी स्थापना 1956 में, विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्र की शाखा के रूप में, गरीबी में कमी और विकास को बढ़ावा देने के लिए लाभकारी और वाणिज्यिक परियोजनाओं में निवेश करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी।

आईएफसी (IFC) का घोषित उद्देश्य लोगों के लिए गरीबी से छुटकारा और बेहतर जीवन स्तर हासिल करने के लिए निजी उद्यम के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, सुलभ और प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देना, व्यवसायों और अन्य निजी क्षेत्र की संस्थाओं का समर्थन करना, और रोजगार पैदा करना और उन लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। जो गरीबी से पीड़ित या अन्यथा सुभेद्य हैं।

आईएफसी (IFC) का निवेश आमतौर पर इसके विकासशील सदस्य देशों में किया जाता है। IFC के समझौते के लेख में कहा गया है कि IFC उत्पादक निजी उद्यमों में निवेश करेगा। निजी स्वामित्व की आवश्यकता उन उद्यमों को अयोग्य नहीं ठहराती है जो आंशिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में हैं यदि ऐसे उद्यम स्थानीय वाणिज्यिक और कॉर्पोरेट कानून के तहत आयोजित किए जाते हैं, बाजार के संदर्भ में और लाभप्रदता मानदंड के अनुसार मेजबान सरकार के नियंत्रण से मुक्त संचालित होते हैं, और/या पूरी तरह या आंशिक रूप से निजीकरण होने की प्रक्रिया में हैं।

IFC परियोजनाओं और कंपनियों को ऋण के माध्यम से, आमतौर पर सात से बारह वर्षों के लिए वित्तपोषित करता है। आईएफसी मध्यस्थ बैंकों, पट्टे पर देने वाली कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को आगे उधार देने के लिए भी ऋण देता है।

Q. 104) विश्व बैंक समूह (World Bank group) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले विश्व व्यापार संगठन से जुड़ना होगा।
2. भारत निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का सदस्य नहीं है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 104) Solution (b)

विश्व बैंक समूह बनाने वाले संगठन सदस्य देशों की सरकारों के स्वामित्व में हैं, जिनके पास नीति, वित्तीय या सदस्यता मुद्दों सहित सभी मामलों पर संगठनों के भीतर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है।

सदस्य देश विश्व बैंक समूह को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। ये निकाय संगठनों के लिए सभी प्रमुख निर्णय लेते हैं।

इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए, किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में शामिल होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) में सदस्यता आईबीआरडी में सदस्यता पर सशर्त है।

ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो कभी भी आईसीएसआईडी (ICSID) के सदस्य नहीं रहे हैं।

जबकि भारत ने आईसीएसआईडी कन्वेंशन से इसकी अनुपस्थिति के विशिष्ट कारणों को नहीं बताया है, 2000 में, भारतीय मध्यस्थता परिषद ने भारतीय वित्त मंत्रालय को सिफारिश की थी कि भारत निम्नलिखित आधारों पर आईसीएसआईडी कन्वेंशन के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता बनने से परहेज बचता है:

- मध्यस्थता के लिए सम्मेलन के नियम विकसित देशों की ओर झुका हुआ है और
- भारतीय अदालत द्वारा पुरस्कार की समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है, भले ही वह भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता हो।

Q. 105) आईएमएफ (IMF) के विभिन्न ऋण साधनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गरीबी में कमी और विकास सुविधा 36 महीने से अधिक के लिए भुगतान की अल्पकालिक शेष राशि के वित्तपोषण की पेशकश करती है।
2. विस्तारित फंड सुविधा एक मध्यम अवधि की व्यवस्था है जिसके द्वारा देश एक निश्चित राशि उधार ले सकते हैं, आमतौर पर चार से 10 वर्षों में।
3. स्टैंड-बाय व्यवस्था (Stand-By Arrangement) के तहत ऋण विशेष रूप से कम ब्याज दरों के साथ प्रशासित होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 105) Solution (b)

आईएमएफ निगरानी के रूप में अपनी सहायता प्रदान करता है, जिसे वह अलग-अलग देशों, क्षेत्रों और समग्र रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वार्षिक आधार पर आयोजित करता है। हालाँकि, कोई देश वित्तीय सहायता मांग सकता है यदि वह खुद को आर्थिक संकट में पाता है, चाहे उसकी अर्थव्यवस्था को अचानक झटका लगा हो या खराब व्यापक आर्थिक नियोजन के कारण।

एक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप देश की मुद्रा का गंभीर अवमूल्यन होगा या देश के विदेशी भंडार का एक बड़ा हास होगा। आईएमएफ की मदद के बदले में, एक देश को आम तौर पर आईएमएफ-निगरानी वाले आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (SAPs) के रूप में जाना जाता है।

तीन और व्यापक रूप से कार्यान्वित सुविधाएं हैं जिनके द्वारा आईएमएफ अपना पैसा उधार दे सकता है:

- एक स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA) भुगतान की अल्पकालिक शेष राशि का वित्तपोषण प्रदान करता है, आमतौर पर 12 से 24 महीनों के बीच, लेकिन 36 महीने से अधिक नहीं।
- विस्तारित फंड सुविधा (EFF) एक मध्यम अवधि की व्यवस्था है जिसके द्वारा देश एक निश्चित राशि उधार ले सकते हैं, आमतौर पर चार से 10 वर्षों में। विस्तारित फंड सुविधा (EFF) का उद्देश्य व्यापक आर्थिक नियोजन के भीतर संरचनात्मक समस्याओं का समाधान करना है जो भुगतान असमानताओं के पुराने संतुलन का कारण बन रहे हैं। वित्तीय और कर क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण के माध्यम से संरचनात्मक समस्याओं का समाधान किया जाता है।
- आईएमएफ द्वारा दी जाने वाली तीसरी मुख्य सुविधा को गरीबी में कमी और विकास सुविधा (PRGF) के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास की नींव रखते हुए सबसे गरीब सदस्य देशों में गरीबी को कम करना है। ऋण विशेष रूप से कम ब्याज दरों के साथ प्रशासित होते हैं।

Q. 106) निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रकाशित की जाती है/हैं?

1. विश्व निवेश रिपोर्ट
2. विश्व आर्थिक आउटलुक
3. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 106) Solution (d)

बहुपक्षीय निगरानी में वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक प्रवृत्तियों की निगरानी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सदस्यों की नीतियों से स्पिलओवर (spillover) का विश्लेषण करना शामिल है।

अपने विश्व आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में, आईएमएफ वर्ष में दो बार बहुपक्षीय निगरानी पर प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है:

1. विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO)
2. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (GFSR)
3. राजकोषीय मॉनिटर (FM)

विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO) विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें दबाव डालने वाले मुद्दों जैसे कि लंबी वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल और वैश्विक वित्तीय संकट से चल रही आर्थिक सुधार के मुद्दों को संबोधित किया जाता है।

वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (GFSR) वैश्विक वित्तीय बाजारों और संभावनाओं का अप-टू-डेट मूल्यांकन (up-to-date assessment) प्रदान करता है और असंतुलन और कमजोरियों को उजागर करता है जो वित्तीय बाजार स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।

एफएम मध्यम अवधि के वित्तीय अनुमानों को अद्यतन करता है और सार्वजनिक वित्त में विकास का आकलन करता है।

आईएमएफ (IMF) अपने विश्व आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक (REO) रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा 1991 से विश्व निवेश रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट क्षेत्रीय और देश के स्तर पर दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रुझानों और इसके योगदान में सुधार के नए उपायों पर केंद्रित है।

Q. 107) निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है?

1. विश्व विकास रिपोर्ट
2. वैश्विक आर्थिक संभावनाएं
3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 107) Solution (a)

विश्व विकास रिपोर्ट (WDR) 1978 से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) या विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। प्रत्येक WDR आर्थिक विकास के एक विशिष्ट पहलू का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। पिछली रिपोर्टों ने कृषि, युवा, इक्विटी, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण, राज्य की भूमिका, संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं, श्रम, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जोखिम प्रबंधन और गरीबी जैसे विषयों पर विचार किया है।

ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स एक विश्व बैंक समूह की प्रमुख रिपोर्ट है जो उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की जांच करती है। यह साल में दो बार जनवरी और जून में जारी किया जाता है। जनवरी संस्करण में सामयिक नीति चुनौतियों का गहन विश्लेषण शामिल है जबकि जून संस्करण में विश्लेषणात्मक छोटे अंश निहित हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट (GCR) विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट "अपने नागरिकों को उच्च स्तर की समृद्धि प्रदान करने के लिए देशों की क्षमता का आकलन करती है"। यह बदले में इस बात पर निर्भर करता है कि कोई देश उपलब्ध

संसाधनों का कितनी उत्पादकता से उपयोग करता है। इसलिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक उन संस्थानों, नीतियों और कारकों के समूह को मापता है जो आर्थिक समृद्धि के स्थायी वर्तमान और मध्यम अवधि के स्तर को निर्धारित करते हैं।

Q. 108) मुद्राओं के विशेष आहरण अधिकार (SDR) बास्केट में शामिल हैं:

1. जापानी येन (Japanese Yen)
2. चीनी युआन (Chinese Yuan)
3. रूसी रूबल (Russian Rubble)

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 108) Solution (b)

विशेष आहरण अधिकार (SDR) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम मुद्रा साधन है, जो आंतरिक लेखांकन उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करता है।

एसडीआर के मूल्य की गणना अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी युआन और ब्रिटिश पाउंड सहित प्रमुख मुद्राओं की भारित टोकरी/बास्केट से की जाती है।

एसडीआर ब्याज दर (SDRi) सदस्य देशों से लिए गए ब्याज दर की गणना के लिए आधार प्रदान करती है जब वे आईएमएफ से उधार लेते हैं और आईएमएफ में उनके पारिश्रमिक लेनदार पदों के लिए सदस्यों को भुगतान करते हैं।

किसी देश का कोटा (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में योगदान की गई राशि) एसडीआर में अंकित (व्यक्त) किया जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एसडीआर भी शामिल है।

Q. 109) भारत निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय व्यापार समझौते का सदस्य है?

1. आसियान (ASEAN)
2. अपेक (APEC)
3. आरसीईपी (RCEP)

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2

- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q. 109) Solution (d)

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN):

- यह एक आर्थिक संघ है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देश शामिल हैं, जो अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और एशिया में अपने सदस्यों और अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है।
- आसियान का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना और जो सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से था।
- सदस्य: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC):

- यह प्रशांत रिम में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर-सरकारी मंच है जो पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है।
- APEC को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उच्चतम स्तर के बहुपक्षीय ब्लॉकों और सबसे पुराने मंचों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव डालता है।
- सदस्य: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलम, कनाडा, चिली, चीनी ताइपे, हांगकांग, चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पेरू, कोरिया गणराज्य, फिलीपींस गणराज्य, रूसी संघ, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP):

- यह एशिया-प्रशांत देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है।
- सदस्य: ब्रुनेई-दारुस्सलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड।
- भारत 2011 में अपनी स्थापना के समय से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) मसौदा समिति का सदस्य था, लेकिन नवंबर 2019 में, उसने बाहर निकलने का फैसला किया।
- भारत मुख्य रूप से चीन से निर्मित वस्तुओं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कृषि और डेयरी उत्पादों की डंपिंग की चिंताओं के कारण सौदे से बाहर हो गया, संभावित रूप से अपने घरेलू औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा था।

Q.110) विश्व बैंक समूह (World Bank Group) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आईडीए (IDA) विकासशील देशों में निवेशकों को गैर-व्यावसायिक जोखिम के खिलाफ गारंटी प्रदान करता है।

2. आईबीआरडी (IBRD) सबसे गरीब देशों की सरकारों को ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 110) Solution (d)

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA):

- यह विश्व बैंक का हिस्सा है जो विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। 173 शोयरधारक राष्ट्रों की देखरेख में, आईडीए का लक्ष्य शून्य से कम ब्याज ऋण (जिसे "क्रेडिट" कहा जाता है) और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और लोगों के रहने की स्थिति में सुधार करने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्रदान करके गरीबी को कम करना है।
- आईडीए दुनिया के 74 सबसे गरीब देशों के लिए सहायता के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है और इन देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं के लिए दाता निधि का सबसे बड़ा स्रोत है।
- आईडीए रियायती शर्तों पर धन उधार देता है। इसका मतलब यह है कि आईडीए क्रेडिट में शून्य या बहुत कम ब्याज शुल्क होता है और पुनर्भुगतान 30 से 40 वर्षों तक बढ़ाया जाता है, जिसमें 5 से 10 साल की छूट अवधि भी शामिल है।
- आईडीए ऋण संकट के जोखिम वाले देशों को अनुदान भी प्रदान करता है।

पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD):

- यह 189 सदस्य देशों के स्वामित्व वाली एक वैश्विक विकास सहकारी संस्था है।
- विश्व के सबसे बड़े विकास बैंक के रूप में, यह मध्य-आय और क्रेडिट योग्य निम्न-आय वाले देशों को ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन उत्पाद और सलाहकार सेवाएं प्रदान करके विश्व बैंक समूह के मिशन का समर्थन करता है, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के प्रतिक्रिया का समन्वय करता है।

बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA):

- यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो राजनीतिक और आर्थिक जोखिम बीमा की पेशकश करके विकासशील देशों में निवेश को बढ़ावा देती है।
- एजेंसी का उद्देश्य विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास का समर्थन करना, गरीबी कम करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

Q. 111) मराकश समझौते के कारण किसकी स्थापना हुई थी:

- a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- b) विश्व व्यापार संगठन
- c) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
- d) विश्व आर्थिक मंच

Q. 111) Solution (b)

मराकश समझौता, मराकश घोषणा द्वारा उत्पन्न, 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों द्वारा मराकश, मोरक्को में हस्ताक्षरित एक समझौता था, जो 8 साल के उरुवे दौर की परिणति को चिह्नित करता है और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करता है, जो आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था।

Q. 112) 1995 में गैट (GATT) के प्रतिस्थापन के रूप में WTO का गठन किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गैट में संस्थागत संरचना का अभाव था।
2. GATT के नियम केवल वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के लिए थे; इसमें बौद्धिक संपदा के पहलू शामिल नहीं थे।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 112) Solution (c)

टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) कई देशों के बीच एक कानूनी समझौता था, जिसका समग्र उद्देश्य टैरिफ या कोटा जैसे व्यापार बाधाओं को कम या समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था।

इसकी प्रस्तावना के अनुसार, इसका उद्देश्य "पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद आधार पर टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं और वरीयताओं को समाप्त करना" था।

GATT पर पहली बार व्यापार और रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (ITO) बनाने के लिए बातचीत करने वाली सरकारों की विफलता का परिणाम था।

गैट का कोई संस्थागत अस्तित्व नहीं था, लेकिन इसका एक छोटा सचिवालय है जबकि विश्व व्यापार संगठन अपने स्वयं के मुख्यालय और कर्मचारियों के साथ एक अंतर सरकारी संगठन है।

गैट का दायरा केवल वस्तु के व्यापार तक ही सीमित था जबकि विश्व व्यापार संगठन में सेवा क्षेत्र के भीतर व्यापार किए गए वस्तु और व्यापार दोनों शामिल हैं।

GATT 1 जनवरी, 1995 तक प्रभावी रहा, जब विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना 123 देशों द्वारा 15 अप्रैल, 1994 को उरुग्वे दौर समझौतों के हिस्से के रूप में मारकेश में समझौते के बाद की गई थी।

Q. 113) विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए::

1. विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च प्राधिकरण सामान्य परिषद (General Council) है, जिसकी कम से कम हर दो साल में बैठक होनी चाहिए।
2. विश्व व्यापार संगठन में सभी प्रमुख निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा लिए जाते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 113) Solution (d)

विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है, जिसकी बैठक सामान्यतया हर दो वर्ष में होती है। यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है, जो सभी देश या सीमा शुल्क संघ हैं। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय ले सकता है।

प्रत्येक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बीच, दैनिक कार्य तीन निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिनकी सदस्यता समान होती है; वे केवल संदर्भ की शर्तों से भिन्न होते हैं जिसके तहत प्रत्येक निकाय का गठन किया जाता है:

- सामान्य परिषद
- विवाद निपटान निकाय
- व्यापार नीति समीक्षा निकाय

विश्व व्यापार संगठन खुद को एक नियम-आधारित, सदस्य-संचालित संगठन के रूप में वर्णित करता है - सभी निर्णय सदस्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं, और नियम सदस्यों के बीच वार्ताओं के परिणाम होते हैं।

विश्व व्यापार संगठन समझौता उन वोटों की भविष्यवाणी करता है जहां आम सहमति नहीं बन सकती है, किंतु सर्वसम्मति की प्रथा निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हावी है।

Q. 114) विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है/हैं?

1. किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. उर्वरकों पर सब्सिडी

3. किसानों को आपदा राहत

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 114) Solution (b)

कृषि पर समझौते (AoA) में सदस्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न कृषि नीतियां शामिल हैं। इनमें आयात पर टैरिफ (बाजार पहुंच) में कमी, निर्यात सब्सिडी (निर्यात प्रतिस्पर्धा) को समाप्त करना और घरेलू सब्सिडी (घरेलू समर्थन) में कमी और इसे अनुमेय प्रकार की सब्सिडी तक सीमित करना शामिल है।

ग्रीन बॉक्स में उन प्रकार की सब्सिडी शामिल हैं जो व्यापार को विकृत नहीं करती हैं या जो केवल न्यूनतम विकृति का कारण बनती हैं। इसलिए उन्हें सब्सिडी की अनुमति है और इस प्रकार गैर-परिवर्तनशील योग्य सब्सिडी हैं।

ग्रीन बॉक्स सब्सिडी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जैसे फसल की विफलता के दौरान किसानों को आय सहायता का प्रावधान, पर्यावरण की रक्षा के लिए किसानों को प्रोत्साहन, अनुसंधान और विकास के लिए सब्सिडी, गरीब लोगों को खाद्य सहायता आदि।

ये सब्सिडी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं; उत्पादन और कीमतों के मौजूदा स्तर को प्रभावित (विघटित) किए बिना।

इस प्रकार सदस्य देश बिना किसी सीमा के ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दे सकते हैं; बशर्ते वे प्रासंगिक मानदंडों का पालन करें।

'ग्रीन बॉक्स' उपायों में कई प्रकार के समर्थन उपाय या सब्सिडी शामिल हैं।

वे मूल रूप से दो सहायता समूहों से मिलकर बने हैं:

- पहले में सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम शामिल हैं (उदाहरण के लिए, अनुसंधान, प्रशिक्षण, विपणन, प्रचार, बुनियादी ढांचा, घरेलू खाद्य सहायता या सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा स्टॉक)।
- दूसरे में सरकार द्वारा उत्पादकों को सीधे भुगतान शामिल है। इनमें मुख्य रूप से आय गारंटी और सुरक्षा कार्यक्रम (प्राकृतिक आपदाएं, फसल बीमा में राज्य का वित्तीय योगदान, आदि) शामिल हैं; संरचनाओं और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को समायोजित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम।

ग्रीन बॉक्स उपाय विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अनुकूल हैं और इसलिए इन्हें कम करने की प्रतिबद्धता से पूरी तरह छूट दी गई है।

Q. 115) विश्व व्यापार संगठन के तहत डी-मिनिमिस प्रावधान (De-Minimis provision) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर लागू है।

2. इस प्रावधान के तहत व्यापार विकृत घरेलू समर्थन विकसित देशों के लिए उत्पादन के मूल्य के 10% तक, विकासशील देशों के लिए 5% तक की अनुमति है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 115) Solution (d)

डी-मिनिमिस प्रावधान के तहत विकसित देशों को व्यापार विकृत सब्सिडी या 'एम्बर बॉक्स' सब्सिडी को कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 5% के स्तर तक बनाए रखने की अनुमति है। विकासशील देशों के लिए यह आंकड़ा 10% था।

सभी घरेलू समर्थन उपाय जिन्हें उत्पादन और व्यापार को विकृत करने के लिए माना जाता है, कृषि पर समझौते के तहत एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आते हैं। उदाहरण - इनपुट सब्सिडी जैसे बिजली, बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि पर सब्सिडी। बाजार समर्थन मूल्य (MSP) सब्सिडी भी इसी बॉक्स के अंतर्गत आती है।

Q. 116) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन (most favoured nation) का दर्जा दिया है।
- 2. भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) राष्ट्र है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 116) Solution (d)

टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT), 1994 के अनुच्छेद 1 में प्रत्येक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा (या टैरिफ और व्यापार बाधाओं के संबंध में तरजीही व्यापार की शर्तें) देने की आवश्यकता है।

तदनुसार, भारत ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तथाकथित मारकेस समझौते के लागू होने की तारीख से पाकिस्तान सहित सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा दिया।

लेकिन, भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद 2019 में पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा वापस ले लिया।

वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली, या जीएसपी, एक तरजीही टैरिफ प्रणाली है जो विभिन्न उत्पादों पर टैरिफ में कमी प्रदान करती है।

जीएसपी की अवधारणा "मोस्ट फेवर्ड नेशन" (एमएफएन) की अवधारणा से बहुत अलग है।

एमएफएन की स्थिति एक राष्ट्र द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ के मामले में समान उपचार प्रदान करती है, लेकिन जीएसपी के मामले में एक देश द्वारा विभिन्न देशों पर अंतर टैरिफ लगाया जा सकता है, जैसे कि यह एक विकसित देश है या एक विकासशील देश है।

दोनों नियम डब्ल्यूटीओ के दायरे में आते हैं।

अमेरिका ने 2019 में सामान्यीकृत सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) योजना के तहत भारत को दिए जा रहे अपने तरजीही टैरिफ को समाप्त कर दिया।

भारत ऑस्ट्रेलिया, रूस और जापान के साथ-साथ यूरोपीय संघ (ईयू) सहित अन्य देशों से जीएसपी के तहत टैरिफ वरीयता का लाभ लेना जारी रखता है।

Q. 117) निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित की जाती है/हैं?

1. ग्लोबल इनेब्लिंग ट्रेड रिपोर्ट
2. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स
3. ग्लोबल जेंडर गैप

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 117) Solution (d)

ग्लोबल इनेब्लिंग ट्रेड रिपोर्ट पहली बार 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की गई थी।

सक्षम व्यापार सूचकांक उन कारकों, नीतियों और सेवाओं को मापता है जो सीमाओं के पार और गंतव्य तक वस्तु के व्यापार की सुविधा प्रदान करते हैं। यह चार उप-सूचकांकों से बना है:

- बाजार पहुँच
- सीमा प्रशासन

- परिवहन और संचार अवसंरचना
- व्यापारिक वातावरण

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI), जिसे टेक्नोलॉजी रेडीनेस भी कहा जाता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) द्वारा पेश किए गए अवसरों का फायदा उठाने के लिए देशों की प्रवृत्ति को मापता है। यह INSEAD के सहयोग से उनकी वार्षिक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (GITR) के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट को सबसे अधिक आधिकारिक और व्यापक मूल्यांकन के रूप में माना जाता है कि आईसीटी राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा और खुशहाली को कैसे प्रभावित करता है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पहली बार 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की गई थी। सूचकांक को उन देशों में उपलब्ध संसाधनों और अवसरों के वास्तविक स्तर के बजाय देशों में संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में लिंग-आधारित अंतराल को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Q. 118) विश्व आर्थिक मंच (WEF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
2. ग्रेट रीसेट विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा COVID-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से पुनर्निर्माण करने के लिए एक पहल है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 118) Solution (b)

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की स्थापना क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab) ने 1971 में एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन के रूप में की थी। इसे शुरू में यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में नामित किया गया था। बाद में 1987 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया।

इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार करना है।

विश्व आर्थिक मंच निष्पक्ष होने का दावा करता है और यह किसी भी राजनीतिक, पक्षपातपूर्ण या राष्ट्रीय हितों से बंधा नहीं है। 2012 तक, इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था, जब इसे रद्द कर दिया गया था; यह स्विस् फेडरल काउंसिल की देखरेख में है। फाउंडेशन का सर्वोच्च शासन निकाय फाउंडेशन बोर्ड है।

ग्रेट रीसेट विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा COVID-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से पुनर्निर्माण करने का एक प्रस्ताव है। यह इस आकलन पर आधारित है कि विश्व अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है।

Q. 119) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक ट्रेडमार्क (trademark) एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक संपत्ति अधिकार है जो धारक को एक निश्चित अवधि के लिए आविष्कार के लिए विशेष अधिकार देता है।
2. एक पेटेंट (patent) उन शब्दों और डिजाइन तत्वों की सुरक्षा करता है जो किसी उत्पाद के स्रोत की पहचान करते हैं।
3. कॉपीराइट (Copyrights) लेखन, कला, वास्तुकला और संगीत जैसे साहित्यिक कार्य के मूल कार्यों की रक्षा करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 119) Solution (c)

पेटेंट:

- एक पेटेंट एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक संपत्ति अधिकार है जो धारक को एक निश्चित अवधि के लिए आविष्कार के लिए विशेष अधिकार देता है।
- एक पेटेंट एक निश्चित अवधि के लिए एक मूल आविष्कार की सुरक्षा करता है और इसे संयुक्त राज्य पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (USPTO) द्वारा प्रदान किया जाता है।
- पेटेंट की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा के डर के बिना उत्पाद का उत्पादन करने का अधिकार देकर, कंपनियों या व्यक्तियों को नए (USPTO) उत्पादों या सेवाओं को विकसित करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- पेटेंट तीन प्रकार के होते हैं: उपयोगिता पेटेंट, प्लांट पेटेंट और डिजाइन पेटेंट।

ट्रेडमार्क:

- एक ट्रेडमार्क उन शब्दों और डिजाइन तत्वों की सुरक्षा करता है जो किसी उत्पाद के स्रोत की पहचान करते हैं।
- ब्रांड नाम और कॉर्पोरेट लोगो (corporate logos) प्राथमिक उदाहरण हैं।
- एक सेवा चिह्न समान है, सिवाय इसके कि यह एक मूर्त वस्तु के बजाय सेवा प्रदाता की सुरक्षा करता है।
- "ट्रेडमार्क" शब्द का प्रयोग अक्सर दोनों पदनामों के संदर्भ में किया जाता है।

कॉपीराइट:

- कॉपीराइट लेखन, कला, वास्तुकला और संगीत जैसे "साहित्यिक कार्य/लेखकत्व के मूल कार्यों" की रक्षा करते हैं।

- जब तक कॉपीराइट प्रभाव में है, कॉपीराइट स्वामी के पास सामग्री को प्रदर्शित करने, साझा करने, प्रदर्शन करने या लाइसेंस देने का एकमात्र अधिकार है।

Q.120) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- अधिकांश ओईसीडी सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत अधिक है।
- भारत ओईसीडी का सदस्य है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

Q. 120) Solution (a)

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) 38 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है।

यह उन देशों का एक मंच है जो खुद को लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, नीतिगत अनुभवों की तुलना करने, आम समस्याओं के जवाब तलाशने, बेहतर प्रथाओं की पहचान करने और अपने सदस्यों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीतियों के समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

आम तौर पर, ओईसीडी सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक (HDI) बहुत अधिक है और उन्हें विकसित देश माना जाता है।

ओईसीडी संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पर्यवेक्षक है।

यद्यपि ओईसीडी के पास अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं है, जिसके लिए इसके सदस्यों से सर्वसम्मति से वोट की आवश्यकता होती है, इसे प्रकाशनों के साथ-साथ वार्षिक मूल्यांकन और सदस्य देशों की रैंकिंग के माध्यम से ज्यादातर आर्थिक डेटा/आंकड़ों के अत्यधिक प्रभावशाली प्रकाशक के रूप में जाना जाता है।

Q. 121) निम्नलिखित में से कौन सा/से मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य है/हैं?

- मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए
- निर्यात को प्रतिस्थापित करने के लिए
- व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- केवल 1 और 2

- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 121) Solution (c)

क्रेडिट/साख और मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है। इसमें मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर का प्रबंधन शामिल है और यह मांग पक्ष की आर्थिक नीति है जिसका इस्तेमाल मुद्रास्फीति, खपत, विकास और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी देश की सरकार द्वारा किया जाता है।

भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए धन की मात्रा का प्रबंधन करना है।

मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति को इस तरह से नियंत्रित करना था ताकि आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका विस्तार किया जा सके और साथ ही मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए इसे अनुबंधित या संकुचित किया जा सके। दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार मुद्रा आपूर्ति का विस्तार और अनुबंध करना है।
- मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए: भारत में मौद्रिक नीति का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य देश में मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। इसका अर्थ है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मूल्य स्तर, मुद्रा आपूर्ति से प्रभावित होता है। मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश के आर्थिक विकास के लिए धन और ऋण की आवश्यक आपूर्ति उपलब्ध कराना है। वे क्षेत्र जो आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, उन्हें ऋण की पर्याप्त उपलब्धता प्रदान की जाती है।
- बचत और निवेश को बढ़ावा देना: ब्याज दर को विनियमित करके और मुद्रास्फीति की जांच करके, मौद्रिक नीति बचत और निवेश को बढ़ावा देती है। ब्याज की उच्च दरें बचत और निवेश को बढ़ावा देती हैं।
- व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के लिए: तेजी और मंदी व्यापार चक्र के मुख्य चरण हैं। मौद्रिक नीति तेजी और मंदी पर रोक लगाती है।
- निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना: निर्यातोन्मुख और आयात प्रतिस्थापन इकाइयों को रियायती ऋण प्रदान करके, मौद्रिक नीति ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करती है और इस प्रकार भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने में मदद करती है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए अधिक ऋण सुनिश्चित करने के लिए: मौद्रिक नीति का उद्देश्य इन क्षेत्रों के लिए ब्याज दरों को कम करके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिक धन उपलब्ध कराना है। प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि, लघु उद्योग, समाज के कमजोर वर्ग आदि शामिल हैं।

- बुनियादी ढांचे का विकास करना: मौद्रिक नीति का उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास करना है। यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रियायती धन प्रदान करता है।

Q. 122) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
2. मुद्रास्फीति की स्थिति में, केंद्रीय बैंक रेपो दर में कमी करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 122) Solution (a)

रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।

भारत में केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए रेपो दर का उपयोग करता है। बैंकिंग में, रेपो दर 'पुनर्खरीद विकल्प' या 'पुनर्खरीद समझौता' से संबंधित है।

जब धन की कमी होती है, तो वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेते हैं जो कि लागू रेपो दर के अनुसार चुकाया जाता है।

केंद्रीय बैंक ट्रेजरी बिल या सरकारी बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों पर ये अल्पावधि ऋण प्रदान करता है।

इस मौद्रिक नीति का उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने या बैंकों की तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

सरकार रेपो दर तब बढ़ाती है जब उन्हें कीमतों को नियंत्रित करने और उधार को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है।

दूसरी ओर, जब बाजार में अधिक पैसा लगाने और आर्थिक विकास को समर्थन देने की आवश्यकता होती है, तो रेपो दर कम हो जाती है।

रेपो दर में वृद्धि का मतलब है कि वाणिज्यिक बैंकों को उन्हें दिए गए पैसे के लिए अधिक ब्याज देना पड़ता है और इसलिए, रेपो दर में बदलाव अंततः सार्वजनिक उधार जैसे होम लोन, ईएमआई आदि को प्रभावित करता है।

Q. 123) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब रिवर्स रेपो दर में वृद्धि होती है तो इससे अर्थव्यवस्था में धन का अतिरिक्त प्रवाह होता है।
2. जहां रेपो दर का उपयोग बाजार में नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वहीं रिवर्स रेपो दर का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 123) Solution (d)

रिवर्स रेपो रेट वह दर है जो किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक में अपने अतिरिक्त धन को रखने करने के लिए भुगतान करता है।

रिवर्स रेपो दर भी एक मौद्रिक नीति है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक (अर्थात भारत में आरबीआई) द्वारा बाजार में धन के प्रवाह को विनियमित करने के लिए किया जाता है।

जरूरत पड़ने पर, किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है और उन्हें लागू रिवर्स रेपो दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करता है।

एक निश्चित समय पर, आरबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली रिवर्स रेपो दर आम तौर पर रेपो दर से कम होती है।

जहां रेपो दर का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए किया जाता है, वहीं रिवर्स रेपो दर का उपयोग बाजार में नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक में जमा करने और रिटर्न अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रिवर्स रेपो दर बढ़ाता है। यह बदले में बाजार से अत्यधिक धन को अवशोषित करता है और जनता के लिए उधार लेने के लिए उपलब्ध धन को कम करता है।

Q. 124) निम्नलिखित में से कौन-सा/से राजस्व व्यय के घटक है/हैं?

- 1. विनिर्माण उपकरण
- 2. उपयोगिताएँ और किराया
- 3. कर्मचारियों का वेतन

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 124) Solution (b)

राजस्व व्यय वर्तमान अवधि में या आमतौर पर एक वर्ष के भीतर उपयोग किए जाने वाले अल्पकालिक खर्च होते हैं। राजस्व व्यय में व्यवसाय चलाने की चल रही परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय शामिल हैं, और इस प्रकार अनिवार्य रूप से परिचालन व्यय के समान ही हैं।

राजस्व व्यय में सामान्य मरम्मत और रखरखाव लागत भी शामिल होती है जो परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में पर्याप्त सुधार या विस्तार किए बिना किसी संपत्ति को कार्य क्रम में रखने के लिए आवश्यक होती है।

राजस्व व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वेतन और कर्मचारी वेतन
- कोई भी ओवरहेड खर्च, जैसे कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए वेतन, जो आम तौर पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (SG&A) के अंतर्गत आता है।
- अनुसंधान और विकास (R&D)
- उपयोगिताएँ और किराया
- व्यावसायिक यात्रा
- संपत्ति कर

पूंजीगत व्यय पूंजी के महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक कंपनी का रखरखाव करने या अक्सर, अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अतिरिक्त लाभ का सृजन करने के लिए करती है।

पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित की खरीद शामिल हो सकती है:

- दक्षता या कारखाना, जिसमें अपग्रेड या विस्तार शामिल है
- वाहन, जैसे उत्पादों की डिलीवरी के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रक
- विनिर्माण उपकरण

Q. 125) निम्नलिखित में से कौन-सा/से उपाय सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है/हैं?

1. खाद्य, उर्वरक जैसी प्रमुख सब्सिडी पर खर्च में कमी
2. पिछले कर्ज पर ब्याज भुगतान बढ़ाना
3. कराधान संरचना का सरलीकरण

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2

- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) केवल 1 और 3

Q. 125) Solution (d)

सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) कहा जाता है। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का एक संकेत है। कुल राजस्व की गणना करते समय, उधार शामिल नहीं होते हैं।

भारतीय संदर्भ में, राजकोषीय घाटे को कम करने और इस तरह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं:

सार्वजनिक व्यय को कम करने के लिए भोजन, उर्वरक, निर्यात, बिजली जैसी प्रमुख सब्सिडी पर खर्च में भारी कमी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा भोजन, उर्वरक, निर्यात प्रोत्साहन पर प्रमुख सब्सिडी पर 20,000 करोड़ रुपये के बराबर की एक बड़ी राशि खर्च किए जाते हैं। समय के साथ सब्सिडी में भारी कटौती के बिना सार्वजनिक व्यय को काफी हद तक कम करना मुश्किल है।

सार्वजनिक व्यय में कटौती के लिए एक अन्य उपयोगी उपाय पिछले कर्ज पर ब्याज भुगतान को कम करना है। भारत में, ब्याज भुगतान केंद्र सरकार के राजस्व खाते पर खर्च का लगभग 40 प्रतिशत है।

राजकोषीय घाटे को कम करने और इस तरह मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को रोकने के लिए, सरकारी व्यय को कम करने के अलावा, सरकारी राजस्व को बढ़ाना होगा। सार्वजनिक राजस्व को बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सरल कराधान संरचना के साथ मध्यम करों की नीति का पालन किया जाना चाहिए। इससे जनता के राजस्व को कम करने के बजाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। करों की उच्च सीमांत दरों से बचना चाहिए क्योंकि वे अधिक काम करने, अधिक बचत करने और अधिक निवेश करने के लिए हतोत्साहन का काम करते हैं। इसके अलावा, प्रत्यक्ष करों की उच्च सीमांत दरें (high marginal rates) करों की चोरी का कारण बनती हैं।

Q. 126) 'रिकार्डियन इक्विवैलेंट प्रोपोजिशन' (Ricardian equivalence proposition) शब्द का अर्थ है:

- a) यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों से आय के संचयी हिस्से को दर्शाता है।
- b) यह इस परिकल्पना को प्रदर्शित करता है कि आर्थिक विकास शुरू में अधिक असमानता की ओर ले जाता है, इसके बाद असमानता में कमी आती है।
- c) इसमें कहा गया है कि वर्तमान करों या भविष्य के करों से खर्च करने वाली सरकार का वित्तपोषण समग्र अर्थव्यवस्था पर समान प्रभाव डालेगा।
- d) यह बताता है कि आर्थिक विकास शुरू में पर्यावरण में गिरावट की ओर जाता है, लेकिन आर्थिक विकास के एक निश्चित स्तर के बाद, एक समाज पर्यावरण के साथ अपने संबंधों में सुधार करना शुरू कर देता है और पर्यावरणीय गिरावट का स्तर कम हो जाता है।

Q. 126) Solution (c)

रिकार्डियन इक्वीवैलेट एक आर्थिक सिद्धांत है जो कहता है कि वर्तमान करों या भविष्य के करों (और वर्तमान घाटे) से सरकारी खर्च के वित्तपोषण का समग्र अर्थव्यवस्था पर समान प्रभाव पड़ेगा।

इसका मतलब यह है कि ऋण-वित्तपोषित सरकारी खर्च में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास प्रभावी नहीं होगा क्योंकि निवेशक और उपभोक्ता समझते हैं कि भविष्य में करों के रूप में ऋण का भुगतान करना होगा।

सिद्धांत का तर्क है कि लोग कर्ज का भुगतान करने के लिए भविष्य के करों में वृद्धि की उम्मीद के आधार पर बचत करेंगे, और यह कि बड़े हुए सरकारी खर्च से कुल मांग में वृद्धि की भरपाई करेगा।

Q. 127) राजकोषीय नीति (fiscal policy) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी (counter-cyclical fiscal policy) में, सरकार मंदी के दौरान व्यय बढ़ाती है और करों को कम करती है।
2. प्रो-सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी (pro-cyclical fiscal policy) में, सरकार सार्वजनिक खर्च को कम करती है या विस्तार के समय के दौरान करों में वृद्धि करती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 127) Solution (a)

राजकोषीय नीति की चक्रीयता का तात्पर्य केवल आर्थिक स्थितियों के आधार पर सरकारी व्यय और करों की दिशा में परिवर्तन से है। ये आर्थिक विकास में उतार-चढ़ाव के आधार पर नीति निर्माताओं के निर्णयों से संबंधित हैं। चक्रीय राजकोषीय नीतियां दो प्रकार की होती हैं - काउंटर सिक्लिकल और प्रो-सिक्लिकल (counter-cyclical and pro-cyclical)।

प्रो-सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को संदर्भित करती है जो आर्थिक या व्यावसायिक चक्र की दिशा के विरुद्ध जाते हैं। इस प्रकार, एक मंदी या स्लोडाउन में, सरकार एक मांग बनाने के लिए खर्च बढ़ाती है और करों को कम करती है जो आर्थिक तेजी ला सकती है।

एक प्रो-सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में, सरकार अच्छे समय के दौरान विस्तार और मंदी के दौरान संकुचन द्वारा व्यापार चक्र को मजबूत करती है। प्रो-सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का अनुसरण करना आमतौर पर खतरनाक माना जाता है। यह व्यापक आर्थिक अस्थिरता बढ़ा सकता है, वास्तविक और मानव पूंजी में निवेश को कम कर सकता है, विकास में बाधा डाल सकता है और गरीबों को नुकसान पहुंचा सकता है।

Q. 128) राजकोषीय नीति के संदर्भ में, क्राउडिंग आउट इफेक्ट (crowding out effect) से क्या तात्पर्य है?

- a) यह एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज दरों में वृद्धि से निजी निवेश खर्च में वृद्धि होती है।

- b) यह एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज दरों में कमी से निजी निवेश खर्च में कमी आती है।
c) यह एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज दरों में कमी से निजी निवेश खर्च में वृद्धि होती है।
d) यह एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज दरों में वृद्धि से निजी निवेश खर्च में कमी आती है।

Q. 128) Solution (d)

ऐसी स्थिति जब ब्याज दरों में वृद्धि से निजी निवेश खर्च में कमी आती है, जैसे कि यह कुल निवेश खर्च की प्रारंभिक वृद्धि को कम करता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहलाता है। कभी-कभी, सरकार एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति का रुख अपनाती है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने खर्च को बढ़ाती है। इससे ब्याज दरों में वृद्धि होती है। बढ़ी हुई ब्याज दरें निजी निवेश निर्णयों को प्रभावित करती हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट के उच्च परिमाण से अर्थव्यवस्था में कम आय भी हो सकती है।

उच्च ब्याज दरों के साथ, निवेश की जाने वाली निधियों की लागत बढ़ जाती है और ऋण वित्तपोषण तंत्र तक उनकी पहुंच प्रभावित होती है। यह अंततः कम निवेश की ओर जाता है और कुल निवेश खर्च में शुरुआती वृद्धि के प्रभाव को कम करता है। आमतौर पर सरकारी खर्च में शुरुआती वृद्धि को उच्च करें या सरकार की ओर से उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है।

Q. 129) राजकोषीय गुणक (fiscal multiplier) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह उस प्रभाव को मापता है जो राजकोषीय खर्च में वृद्धि का देश के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ेगा।
2. राजकोषीय गुणक मंदी की तुलना में विस्तार के दौरान अधिक हो जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 129) Solution (a)

राजकोषीय गुणक किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर राजकोषीय प्रोत्साहन के प्रभाव को मापता है। राजकोषीय गुणक बुनियादी ढांचे या सामाजिक कार्यक्रमों के निर्माण जैसी मूर्त चीजों पर सरकारी खर्च से प्रेरित होता है।

राजकोषीय गुणक दो प्रकार के होते हैं - व्यय गुणक और राजस्व गुणक:

- व्यय गुणक: यह सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक अतिरिक्त डॉलर के उत्पादन में परिवर्तन को मापता है।
- राजस्व गुणक: यह सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व में प्रत्येक डॉलर की वृद्धि के लिए उत्पादन में परिवर्तन को मापता है।

कर्ज का उच्च स्तर राजकोषीय गुणक के प्रभाव को कम कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक उत्पादक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने से पहले किसी भी वित्तीय प्रोत्साहन का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। इसलिए, उत्पादन कम मात्रा में बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि राजकोषीय गुणक कम हो जाता है।

Q.130) ऋण-से-जीडीपी अनुपात निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर करता है?

1. ब्याज दर वृद्धि विभेदक
2. पिछली अवधि में ऋण-से-जीडीपी अनुपात
3. प्राथमिक घाटा-से-जीडीपी का अनुपात

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 130) Solution (d)

ऋण-से-जीडीपी अनुपात किसी देश के सार्वजनिक ऋण का उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से अनुपात है।

ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात जितना अधिक होगा, देश के अपने ऋण का भुगतान करने की संभावना उतनी ही कम होगी और इसके डिफॉल्ट का जोखिम उतना ही अधिक होगा, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वित्तीय हलचल हो सकती है।

ऋण-से-जीडीपी अनुपात तीन प्रमुख मापदंडों पर निर्भर करता है, अर्थात् आईआरजीडी, पिछली अवधि में ऋण-से-जीडीपी अनुपात और प्राथमिक घाटा-से-जीडीपी का अनुपात।

ब्याज दर वृद्धि विभेदक (IGRD) एक अर्थव्यवस्था में ब्याज की नाममात्र दर (r) और विकास की नाममात्र दर (g) के बीच के अंतर को संदर्भित करता है।

प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष के उधार पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर है।

Q. 131) स्टार्ट अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह योजना विशेष रूप से इच्छुक महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।
2. DPIIT नोडल एजेंसी है जिसे अन्य सरकारी विभागों के साथ स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन के समन्वय करने के लिए अधिदेशित है।
3. यह संचालन के पहले 3 वर्षों के लिए पूंजीगत लाभ कर से मुक्ति के लिए स्टार्ट अप प्रदान करता है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1

- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 131) Solution (d)

स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में भारत सरकार की एक पहल है। स्टार्टअप इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और धन सृजन करना है। स्टार्टअप इंडिया ने एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने और भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाले देश में बदलने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का प्रबंधन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया जाता है।

स्टार्टअप इंडिया योजना स्टैंड अप इंडिया योजना से अलग है। स्टार्ट अप इंडिया योजना नई पहलों और उपक्रमों को बढ़ावा देती है। जबकि स्टैंड अप इंडिया योजना इच्छुक महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। व्यक्तियों को अपने विचारों को जीवन में लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट-अप इंडिया योजना के मुख्य भागों में से एक है।

योजना की विशेषताएं हैं:

- 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल।
- पेटेंट पंजीकरण शुल्क में कमी।
- बेहतर दिवालियापन संहिता, 90-दिन की निकास खिड़की सुनिश्चित करने के लिए।
- संचालन के पहले 3 वर्षों के लिए निरीक्षण से मुक्ति।
- संचालन के पहले 3 वर्षों के लिए पूंजीगत लाभ कर से मुक्ति।
- संचालन के पहले 3 वर्षों के लिए कर से मुक्ति।
- स्व-प्रमाणन अनुपालन।
- अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक इनोवेशन हब बनाया।
- 5 लाख स्कूलों को लक्षित करना, और नवाचार से संबंधित कार्यक्रमों में 10 लाख बच्चों को शामिल करना।
- स्टार्टअप फर्मों को आईपीआर सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई योजनाएं।
- राजस्थान इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में स्टार्टअप ओएसिस (Startup Oasis) का निर्माण किया।

Q. 132) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इस योजना का उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना है।
2. मुद्रा ऋण किसी भी बैंक शाखा की भागीदारी के बिना सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे दिया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 132) Solution (a)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु / सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इन ऋणों को PMMY के तहत मुद्रा ऋणों (MUDRA loans) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मुद्रा एक पुनर्वित्त संस्थान है। मुद्रा सूक्ष्म उद्यमियों / व्यक्तियों को सीधे उधार नहीं देती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत मुद्रा ऋण किसी बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई आदि के नजदीकी शाखा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तत्वावधान में मुद्रा ने उत्पाद/योजनाएं बनाई हैं। इस सहयोग का नाम 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' दिया गया है जो लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी के वृद्धि/विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को दर्शाता है और स्नातक/विकास के अगले चरण को देखने के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान करता है।

- शिशु : 50,000/- तक के ऋणों को कवर करना
- किशोर : 50,000/- से अधिक और 5 लाख तक के ऋण को कवर करना
- तरुण : 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक के ऋण को कवर करना

Q. 133) मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी वस्तुओं/कमोडिटी की कीमत में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए बनाया गया है।
2. इसका उपयोग राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों को कृषि-बागवानी वस्तुओं के लिए खरीद और वितरण हस्तक्षेप पर उनकी कार्यशील पूंजी और अन्य खर्चों का समर्थन करने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ऋण देने के लिए किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 133) Solution (a)

मूल्य स्थिरीकरण कोष प्याज, और आलू जैसे चुनिंदा कमोडिटी की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता को अवशोषित करने के लिए बनाया गया कोई भी फंड है। बाद में दालें भी डाली गईं।

फंड में राशि का उपयोग आमतौर पर उच्च/निम्न कीमतों को कम/ऊपर लाने के उद्देश्य से गतिविधियों के लिए किया जाता है, उदाहरण के लिए, कुछ सामानों का अधिग्रहण और जब उचित हो तो उनका वितरण ताकि लागत एक सीमा के भीतर रहे।

पीएसएफ योजना राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और केंद्रीय एजेंसियों को उनकी कार्यशील पूंजी और अन्य खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की उन्नति के लिए प्रदान करती है, जो वे ऐसी वस्तुओं की खरीद और वितरण में कर सकते हैं।

नतीजतन, फंड का वास्तविक उपयोग इन उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋणों का उपयोग करने के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, उस समय की वास्तविक पहचान जिसमें सहायता की आवश्यकता है और मूल्य समर्थन उपायों के कार्यान्वयन को राज्यों पर छोड़ दिया गया है।

किसानों/थोक मंडियों से घरेलू खरीद के अलावा, फंड के समर्थन से आयात भी किया जा सकता है।

Q. 134) तेजस्विनी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह बुनियादी जीवन कौशल के साथ किशोर लड़कियों को सशक्त बनाना तथा उसके बाद बाजार आधारित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए और अवसर प्रदान करना शामिल है।
2. भारत सरकार ने इस योजना के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के साथ वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 134) Solution (c)

तेजस्विनी योजना:

यह किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है।

यह बुनियादी जीवन कौशल के साथ किशोरियों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है और उसके बाद बाजार संचालित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने या माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए और अवसर प्रदान करता है।

इसके 3 मुख्य घटक हैं:

- सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अवसरों का विस्तार
- प्रतिभागियों के कौशल को विकसित करके आजीविका के अवसरों में सुधार करना
- स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करता है।

भारत सरकार ने इस योजना के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के साथ वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

Q. 135) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अटल पेंशन योजना किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है और 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है।
2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष है।
3. अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु में, उनके योगदान के आधार पर 1000 - 5000 प्रति माह रुपये से लेकर निश्चित पेंशन प्रदान करती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) केवल 1 और 3

Q. 135) Solution (c)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(PMJJB):

- पीएमजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है जिसमें से स्वतः डेबिट सुविधा के जरिये प्रीमियम वसूल किया जा सकता है।
- यह 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों और बैंक खाता रखने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है।
- जो लोग 50 वर्ष पूरा करने से पहले योजना में शामिल होते हैं, वे प्रीमियम के भुगतान के अधीन 55 वर्ष की आयु तक जीवन कवर का जोखिम जारी रख सकते हैं।
- यह एलआईसी और अन्य भारतीय निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रशासित है।
- एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के साथ एक बीमा कंपनी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(PMJJB) में शामिल हो सकता है।
- पात्र व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाणन दिए बिना योजना में शामिल हो सकते हैं।

अटल पेंशन योजना:

- अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र जैसे सेविका, माली, डिलीवरी बॉय आदि के उद्देश्य से एक पेंशन योजना है। इस योजना ने पिछली स्वावलंबन योजना को बदल दिया था जिसे लोगों ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया था।
- योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी भारतीय नागरिक को बुढ़ापे में किसी बीमारी, दुर्घटना या बीमारी के बारे में चिंता न करनी पड़े, जिससे सुरक्षा की भावना पैदा हो। निजी क्षेत्र के कर्मचारी या ऐसे संगठन के साथ काम करने वाले कर्मचारी जो उन्हें पेंशन लाभ प्रदान नहीं करते हैं, वे भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
 - भारत का नागरिक होना चाहिए
 - 18-40 की उम्र के बीच होना चाहिए
 - कम से कम 20 वर्षों के लिए योगदान करना चाहिए
 - आपके आधार से जुड़ा एक बैंक खाता होना चाहिए
 - एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये की निश्चित पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है। पेंशन का निर्धारण व्यक्ति की उम्र और योगदान राशि के आधार पर किया जाएगा।

Q. 136) प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना है।
2. यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की एक उप-योजना है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 136) Solution (d)

प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत लाभ:

- निर्माण क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है और व्यापार/सेवा क्षेत्र में यह 10 लाख रुपये है।
- पीएमईजीपी के तहत सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का)
 - सामान्य वर्ग के लिए - 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण)
 - विशेष (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित) - 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण)

- कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी।

यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (KVIBs), जिला उद्योग केंद्रों (DICs) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में अंतिम संवितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी का मार्ग प्रशस्त करता है।

पात्रता:

- कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं और व्यापार/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से ऊपर के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास व्यापार / सेवा क्षेत्र में 5 लाख।
- पीएमईजीपी के तहत केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार किया जाता है।
- स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं उठाया है), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान; उत्पादन सहकारी समितियां और चैरिटेबल ट्रस्ट भी पात्र हैं।

Q. 137) भारत सरकार के पेंसिल पोर्टल का उद्देश्य है:

- बाल श्रम को खत्म करना
- बुजुर्गों के लिए शिक्षा
- स्कूलों में छोड़ने वालों की पुनः भर्ती
- महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा

Q. 137) Solution (a)

पेंसिल एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जिसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्र, राज्य, जिला, सरकारों, नागरिक समाज और आम जनता को शामिल करना है।

पोर्टल राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (NCLP) के विधायी प्रावधानों को लागू करने के लिए एक मजबूत कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र बनाता है।

चूंकि श्रम का विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए नीति का प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य एनसीएलपी (NCLP) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र को राज्य सरकार, जिले और सभी परियोजना समितियों से जोड़ना है।

पेंसिल पोर्टल में निम्नलिखित घटक हैं:

- चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम

- शिकायत कार्नर
- राज्य सरकार
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और
- अभिसरण (Convergence)

Q. 138) निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मंत्रालय की योजनाएं/पहल हैं/हैं?

1. कुसुम (KUSUM)
2. लीप (LEAP)
3. अर्पित (ARPIT)

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 138) Solution (b)

पीएम कुसुम (PM KUSUM): प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) देश में सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की योजना है।

इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर और अन्य नवीकरणीय क्षमता को कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता 34,422 करोड़ कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क सहित के साथ जोड़ना है।

लीप पहल (LEAP Initiative)

- शिक्षाविदों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम (LEAP) एक प्रमुख नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अकादमिक प्रमुखों को प्रशिक्षित करना है, जिनके भविष्य में नेतृत्व की भूमिका निभाने की संभावना है।
- इसका फोकस समूह सार्वजनिक वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में दूसरे स्तर के शैक्षणिक कार्यकर्ता हैं।
- इसमें प्रबंधकीय कौशल जैसे समस्या-समाधान, तनाव से निपटने, टीम निर्माण कार्य, संघर्ष प्रबंधन, संचार कौशल विकसित करना आदि में घरेलू और विदेशी दोनों प्रशिक्षण शामिल होंगे।
- कार्यान्वयन शीर्षक वाले विश्वविद्यालयों और शीर्ष 100 वैश्विक रैंकिंग वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के माध्यम से होगा।

अर्पित पहल (ARPIT initiative)

- शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (ARPIT) स्वयं मंच का उपयोग करते हुए 15 लाख उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास की एक अनूठी पहल है।
- ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्रों (NRC) की पहचान की जाएगी
- स्वयं (SWAYAM) - स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पारिंग माइंड्स एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (MOOCs) प्लेटफॉर्म है जिसे स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए लॉन्च किया गया है।

Q. 139) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (Sovereign Gold Bond scheme) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, स्वर्ण के ग्राम में मूल्यांकित सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं।
2. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, भुगतान बैंकों और छोटे वित्त बैंकों के माध्यम से बेचे जाते हैं।
3. इसका उद्देश्य भौतिक सोने की मांग को कम करना और घरेलू बचत का एक हिस्सा वित्तीय बचत में स्थानांतरित करना है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 139) Solution (c)

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना सरकार द्वारा नवंबर 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत शुरू की गई थी।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। वे सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो सोने के ग्राम में मूल्यांकित हैं। वे भौतिक सोना रखने के विकल्प हैं।

बांड बैंकों (छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई के माध्यम से बेचे जाते हैं।

एसजीबी सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जिन्हें सोने के ग्राम में मूल्यांकित किया जाता है। वे भौतिक सोना रखने के विकल्प हैं। निवेशकों को निर्गम मूल्य नकद में देना होगा और बांड परिपक्वता पर नकद में भुनाए जाएंगे। बांड भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।

Q.140) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
2. इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना है।
3. यह 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 1 और 3
- d) केवल 2 और 3

Q. 140) Solution (d)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है।

इसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता जोड़ने और ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम सौंपा गया है।

डीडीयू-जीकेवाई विशिष्ट रूप से गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है।

स्किल इंडिया अभियान के एक हिस्से के रूप में, यह मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया अभियानों जैसे सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

18 से 34 वर्ष की आयु के बीच देश की 180 मिलियन या 69% से अधिक युवा आबादी इसके ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें से, पिरामिड के नीचे के गरीब परिवारों के युवा जिनके पास कोई या सीमांत रोजगार नहीं है, उनकी संख्या लगभग 55 मिलियन है।

Q. 141) ब्याज दर विकास दर अंतर (IRGD) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सरकारी ऋण पर चुकाए गए ब्याज और अर्थव्यवस्था की नॉमिनल वृद्धि दर के बीच का अंतर है।
2. भारत में ब्याज दर विकास दर अंतर (IRGD) सकारात्मक है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 141) Solution (a)

ब्याज दर विकास दर अंतर (IRGD):

- यह एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर और विकास दर के बीच का अंतर है।
- संभावित उच्च विकास के भारतीय संदर्भ के साथ, भारत सरकार द्वारा चुकाए गए कर्ज पर ब्याज दर अपवाद के तौर पर नहीं बल्कि मानक के हिसाब से भारत की विकास दर से कम रही है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत में एक नकारात्मक आईआरजीडी की घटना, कम ब्याज दरों के कारण नहीं बल्कि बहुत अधिक विकास दर के कारण है, जो विशेष रूप से विकास मंदी और आर्थिक संकट के दौरान राजकोषीय नीति की प्रमुखता पर बहस को प्रेरित करती है।

Q. 142) प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति (countercyclical fiscal policy) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस नीति के तहत सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल सरकारी खर्च कम हो जाता है और मंदी के दौरान कर की दरें बढ़ जाती हैं।
2. यह नीतिगत उपाय उछाल/तेजी की अवधि के दौरान सरकारी घाटे को बढ़ाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 142) Solution (d)

व्यापार चक्र के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सरकार की राजकोषीय नीति की बड़ी भूमिका होती है। व्यापार चक्र के दो महत्वपूर्ण चरण हैं उछाल/तेजी और मंदी।

कराधान और व्यय का उपयोग करते हुए व्यावहारिक रूप से राजकोषीय नीति प्रतिक्रियाएं व्यापार चक्र के जवाब में दो तरह से जा सकती हैं: प्रतिचक्रीय और चक्रीय।

एक प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति राजकोषीय उपायों के माध्यम से उछाल या मंदी का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा रणनीति को संदर्भित करती है। यह चल रहे उछाल या मंदी की प्रवृत्ति के खिलाफ काम करता है; इस प्रकार, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है, इन दो चरणों के दौरान प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति दो अलग-अलग दिशाओं में काम करती है।

मंदी के दौरान प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति: मंदी एक व्यापार चक्र की स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था में धीमी मांग और वृद्धि में कमी होती है। यहां, सरकार की जिम्मेदारी कराधान और व्यय नीतियों को ठीक करके मांग उत्पन्न करना है। करों को कम करने और खर्च बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करने और उत्पादन में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

उछाल के दौरान प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति: उछाल की स्थिति में, आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। उछाल को बढ़ाना विनाशकारी है क्योंकि इससे मुद्रास्फीति और ऋण संकट पैदा हो सकता है और यहां सरकार की जिम्मेदारी आर्थिक गतिविधियों की गति को कम करने

की है। करों में वृद्धि और सार्वजनिक व्यय को कम करने से उछाल कम हो जाएगा। इस प्रकार, मांग में कमी उछाल के दौरान प्रतिक्रिया राजकोषीय नीति की प्रकृति होनी चाहिए।

Q. 143) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह आयुष्मान भारत योजना के घटकों में से एक है।
2. यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है।
3. इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों तक के खर्च शामिल हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 143) Solution (c)

आयुष्मान भारत, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू की गई थी। इस पहल को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता है, जो "किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है।

आयुष्मान भारत देखभाल दृष्टिकोण की निरंतरता को अपनाता है, जिसमें दो अंतर-संबंधित घटक शामिल हैं, जो हैं -

- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs)
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):

- PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- भारत में सार्वजनिक और निजी पैनेल में शामिल अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए यह 5 लाख रुपये का प्रति परिवार प्रति वर्ष कवर प्रदान करता है।
- 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर हकदार परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इन लाभों के लिए पात्र हैं।
- PM-JAY सेवा के बिंदु पर, यानी अस्पताल में लाभार्थी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है।
- PM-JAY का लक्ष्य चिकित्सा उपचार पर होने वाले विनाशकारी खर्च को कम करने में मदद करना है, जो हर साल लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेलता है।

- यह अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों के खर्च जैसे कि निदान और दवाओं को कवर करता है।
- परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- सभी पूर्व-मौजूदा स्थितियों को पहले दिन से कवर किया जाता है।
- योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं यानी लाभार्थी कैशलेस उपचार का लाभ उठाने के लिए भारत में किसी भी सार्वजनिक या निजी अस्पताल में जा सकता है।
- सेवाओं में उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करने वाली लगभग 1,393 प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें दवाएं, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सक की फीस, कमरे का शुल्क, सर्जन शुल्क, ओटी और आईसीयू शुल्क आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों के बराबर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार स्वास्थ्य परिणामों पर PM-JAY के निम्नलिखित कारण प्रभाव देखे गए:

- बेहतर स्वास्थ्य बीमा कवरेज: सभी राज्यों में, पीएमजेएवाई लागू करने वाले राज्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 54% की वृद्धि हुई, जबकि उन राज्यों में 10% की गिरावट आई।
- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में गिरावट: उन राज्यों के लिए आईएमआर में 12% की गिरावट आई, जिन्होंने नहीं किया।
- जिन राज्यों ने PM-JAY योजना को लागू किया था उन राज्यों में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है।
- 5 वर्ष से कम आयु दर में गिरावट

Q. 144) बेयर नीसिटीज इंडेक्स (Bare Necessities Index - BNI) की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन घटकों को ध्यान में रखा जाता है?

1. पीने के जल के स्रोत
2. आवास
3. बाल मृत्यु दर
4. जल निकासी व्यवस्था

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1, 2 और 3
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 3 और 4
- d) केवल 1, 2 और 4

Q. 144) Solution (d)

बीएनआई पांच आयामों पर 26 संकेतकों को सारांशित करता है - पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। सूचकांक पहुंच के तीन स्तरों पर क्षेत्रों को वर्गीकृत करता है - उच्च, मध्यम, निम्न - बेयर नीसिटीज के लिए।

1. जल: इसे पीने के जल के प्रमुख स्रोत, पीने के जल के स्रोत से दूरी, पानी लेने की विधि और पहुंच की प्रकृति जैसे संकेतकों का उपयोग करके मापा गया है।
2. स्वच्छता: इसे संकेतकों के माध्यम से मापा गया है जैसे कि घर में शौचालय तक पहुंच और घर द्वारा उपयोग किए जाने वाले शौचालय के प्रकार: पाइपड सीवर सिस्टम, सेप्टिक टैंक, ट्विन लीच पिट (twin leach pit), सिंगल पिट।
3. आवास: इसे संरचना की स्थिति, आवास के प्रकार (स्वतंत्र, फ्लैट या अन्य) और पक्के या कच्चे घर जैसे संकेतकों के माध्यम से मापा गया है।
4. सूक्ष्म पर्यावरण: यह घर की जल निकासी प्रणाली जैसे संकेतकों के माध्यम से मापा जाता है कि क्या पिछले एक वर्ष के दौरान घर में मक्खियों / मच्छरों की समस्या का सामना करना पड़ा और क्या स्थानीय निकायों / राज्य सरकार द्वारा मच्छरों से निपटने के लिए कोई प्रयास किया गया था।
5. अन्य सुविधाएं: अन्य सुविधाओं में रसोई का प्रकार (वॉटर टैप के साथ या अलग रसोई घर के साथ), आवास इकाई का वेंटिलेशन, घर द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाथरूम का प्रकार, क्या घर में घरेलू उपयोग के लिए बिजली और बिजली के तार, खाना पकाने के लिए घरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन का प्रकार क्या है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बेयर नीसिटीज से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष:

- 2012 की तुलना में 2018 में देश के सभी राज्यों में 'बेहद आवश्यकताओं' तक पहुंच में सुधार हुआ है।
- यह केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में सबसे अधिक है जबकि ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सबसे कम है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर-राज्यीय असमानताओं में कमी आई है।
- 'बेयर नीसिटीज' तक बेहतर पहुंच से आईएमआर जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है और यह शिक्षा संकेतकों में भविष्य में सुधार के साथ भी जुड़ा हुआ है।

Q. 145) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक देश के सार्वजनिक ऋण को धारणीय/ सतत माना जाता है यदि सरकार असाधारण वित्तीय सहायता के बिना अपने सभी वर्तमान और भविष्य के भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है।
2. किसी देश की ऋण स्थिरता इसकी उच्च विकास दर की ओर ले जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 145) Solution (a)

एक देश के सार्वजनिक ऋण को धारणीय माना जाता है यदि सरकार असाधारण वित्तीय सहायता के बिना या डिफॉल्ट में जाए बिना अपने सभी वर्तमान और भविष्य के भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 एक संकट के दौरान भारत में राजकोषीय नीति के इष्टतम रुख की जांच करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह विकास है जो ऋण स्थिरता की ओर ले जाता है और जरूरी नहीं कि इसके विपरीत परिस्थिति में इसके विपरीत प्रभाव उत्पन्न होंगे। कई देशों के साक्ष्य के साथ, सर्वेक्षण से पता चलता है कि विकास उच्च विकास दर वाले देशों में ऋण को धारणीय बनाता है।

Q. 146) वी-आकार के आर्थिक सुधार (V-shaped economic recovery) की विशेषता है:

1. व्यवसायों के निवेश की धीमी वापसी
2. उपभोक्ता मांग में वृद्धि
3. स्थायी बेरोजगारी

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) केवल 1 और 3

Q. 146) Solution (b)

वी-आकार का सुधार एक आर्थिक स्थिति को दर्शाती है जहाँ बाजारों में एक गंभीर मंदी बाजारों में समान रूप से मजबूत सुधार के साथ मिलती है। जिसमें एल-आकार, डब्ल्यू-आकार, यू-आकार और जे-आकार शामिल हैं।

प्रत्येक प्रकार का सुधार आर्थिक मैट्रिक्स के चार्ट के सामान्य आकार का प्रतिनिधित्व करती है जो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को मापती है। अर्थशास्त्री आर्थिक स्वास्थ्य के प्रासंगिक उपायों, जैसे रोजगार दर, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों की जांच करके इन चार्टों को विकसित करते हैं।

वी-आकार की रिकवरी में या वी-आकार की आर्थिक सुधार, अर्थव्यवस्था में तेज आर्थिक गिरावट के बाद, यह जल्दी और दृढ़ता से ठीक हो जाता है। इस तरह की रिकवरी आम तौर पर उपभोक्ता मांग और व्यावसायिक निवेश खर्च के तेजी से पुनः समायोजन के कारण आर्थिक गतिविधि में एक महत्वपूर्ण बदलाव से प्रेरित होती है।

अर्थव्यवस्था के तेजी से समायोजन और व्यापक आर्थिक प्रदर्शन के प्रमुख समग्र मेट्रिक्स में त्वरित सुधार के कारण, एक वी-आकार की रिकवरी को एक तरह की सबसे अच्छी स्थिति के रूप में माना जा सकता है जब एक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाती है।

Q. 147) रिकार्डियन तुल्यता प्रस्ताव सुझाव (Ricardian Equivalence Proposition suggests) से पता चलता है:

- a) आर्थिक मंदी को दूर करने या रोकने के लिए कुल मांग का प्रबंधन करने के लिए सक्रिय सरकारी नीति का उपयोग करना।
- b) जनसंख्या वृद्धि संभावित रूप से घातीय है, जबकि खाद्य आपूर्ति या अन्य संसाधनों की वृद्धि रैखिक है, जो अंततः जीवन स्तर को निम्न कर देती है जिससे जनसंख्या कम हो जाती है।
- c) मौजूदा करें या मौजूदा घाटे से सरकारी खर्च को वित्तपोषित करने से समग्र अर्थव्यवस्था पर समान प्रभाव पड़ेगा।
- d) जिन व्यक्तियों के पास संसाधन तक अप्रतिबंधित पहुंच है, उनके स्वयं के हित में कार्य करने की संभावना है और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से, संसाधन को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं।

Q. 147) Solution (c)

रिकार्डियन तुल्यता एक आर्थिक सिद्धांत है जो कहता है कि वर्तमान करें या भविष्य के करें (और वर्तमान घाटे) से सरकारी खर्च के वित्तपोषण का समग्र अर्थव्यवस्था पर समान प्रभाव पड़ेगा।

इसका मतलब यह है कि ऋण-वित्तपोषित सरकारी खर्च में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास प्रभावी नहीं होगा क्योंकि निवेशक और उपभोक्ता समझते हैं कि भविष्य में करें के रूप में ऋण का भुगतान करना होगा।

सिद्धांत का तर्क है कि लोग कर्ज का भुगतान करने के लिए भविष्य के करें में वृद्धि की उम्मीद के आधार पर बचत करेंगे, और यह कि बढ़े हुए सरकारी खर्च से कुल मांग में वृद्धि को समायोजित करेगा।

यह सिद्धांत डेविड रिकार्डो द्वारा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित किया गया था और बाद में हार्वर्ड के प्रोफेसर रॉबर्ट बैरो द्वारा इसका विस्तार किया गया था। इस कारण से, रिकार्डियन तुल्यता को बैरो-रिकार्डो तुल्यता प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है।

Q. 148) हेडलाइन मुद्रास्फीति (headline inflation) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति की एक माप है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें जैसे वस्तुएं शामिल हैं, जो बहुत अधिक अस्थिर होती हैं।
2. विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति अधिक प्रासंगिक है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 148) Solution (b)

हेडलाइन मुद्रास्फीति टोकरी/बास्केट में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। यह कोर मुद्रास्फीति/इनफ्लेशन से अलग है जो खाद्य और ईंधन वस्तुओं को हेडलाइन मुद्रास्फीति से बाहर करती है।

चूँकि ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और मुद्रास्फीति की गणना में 'विचलन' पैदा होता है, कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में कम अस्थिर होती है।

एक विकसित अर्थव्यवस्था में, खाद्य और ईंधन का घरेलू उपभोग टोकरी/बास्केट का 10-15% और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह टोकरी/बास्केट का 30-40% होता है। इस प्रकार, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति अधिक प्रासंगिक है।

Q. 149) आर्थिक सर्वेक्षण, 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आर्थिक विकास का असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
2. भारत के लिए सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में बदलाव का व्यापक आर्थिक संकेतकों के साथ कमजोर सह-संबंध है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 149) Solution (c)

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार:

- आर्थिक विकास और सामाजिक-आर्थिक परिणामों की तुलना में असमानता और सामाजिक-आर्थिक परिणामों के बीच संबंध भारत में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न है।
- विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत में असमानता और प्रति व्यक्ति आय (विकास) का सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ समान संबंध है।
- आर्थिक विकास का ज़्यादा प्रभाव असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर पड़ता है।
- नागरिकों को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने के लिये भारत को आर्थिक विकास पर ज़ोर देना चाहिये।

आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख है कि:

भारत की संप्रभु/सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Rating) अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों को प्रतिबिंबित नहीं करती है:

- एसएंडपी/मूडीज के लिए A+/A1 और BBB-/Baa3 के बीच रेटिंग वाले देशों के बीच कई मानदंडों पर स्पष्ट अंतर है
- पैरामीटर की सॉवरेन रेटिंग पर प्रभाव के कारण अनिवार्य से काफी कम रेटिंग दी जाती है।

क्रेडिट रेटिंग डिफॉल्ट या चूक की संभावना को चित्रित करती है और इसलिए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उधारकर्ता की इच्छा और क्षमता को दर्शाती है:

- शून्य संप्रभु/सॉवरेन डिफॉल्ट की पृष्ठभूमि के माध्यम से निस्संदेह रूप से भारत की भुगतान की इच्छा का पता चलता है।
- भारत की भुगतान करने की क्षमता का अनुमान कम विदेशी मुद्रा नामित ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार से लगाया जा सकता है।

इस प्रकार, भारत के लिए सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग परिवर्तनों का व्यापक आर्थिक संकेतकों के साथ कोई संबंध नहीं है या कमजोर है।

Q.150) बजट 2021-22 के अनुसार, रुपये का सबसे अधिक प्रतिशत केंद्र सरकार के पास किस रूप में आता है:

- a) जीएसटी (GST)
- b) उधारी (Borrowings)
- c) आयकर (Income Tax)
- d) गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां (Non-Debt Capital Receipts)

Q. 150) Solution (b)

बजट 2021-22 के अनुसार रुपया आता है

मद	प्रतिशत
उधार और अन्य देनदारियां	36%
निगम कर	13%
जीएसटी	15%
गैर-कर राजस्व	6%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	8%
सीमा शुल्क	3%
आयकर	14%
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	5%

Q. 151) बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकरण प्रस्तावित है?

1. सोना
2. यूरिया
3. पेट्रोल
4. चीनी

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1, 2 और 3

- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 3 और 4
- d) केवल 2 और 4

Q. 151) Solution (a)

कृषि अवसंरचना और विकास उपकर या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस:

बजट 2021-22 में 29 वस्तुओं पर एक नई लेवी, कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC) का प्रस्ताव किया गया है।

नए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस का उद्देश्य कृषि बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करने के लिए धन जुटाना है।

सीमा शुल्क की ओर से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं में सोना, चांदी, एल्कोहल पेय पदार्थ, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल, सेब, कोयला, लिग्नाइट और पीट निर्दिष्ट उर्वरक (peat specified fertilizers), मटर, काबुली चना, बंगाल चना, मसूर और कपास शामिल हैं।

आबकारी पक्ष पर, एआईडीसी पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर हालांकि, बजट में पेट्रोल और डीजल पर बेसिक उत्पाद शुल्क (BED) और स्पेशल अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) दोनों को कम किया गया है, ताकि कुल उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।

नया उपकर केवल गैर-ब्रांडेड और ब्रांडेड पेट्रोल-डीजल पर मूल सीमा शुल्क (BCD), मूल उत्पाद शुल्क (BED) और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) में कमी की भरपाई करेगा। इस प्रकार यह उपभोक्ताओं के लिए कर विस्तार को नहीं बढ़ाएगा।

Q. 152) केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्रा योजना (MITRA scheme) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
2. इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है।
3. इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 152) Solution (b)

केंद्रीय बजट 2021 के दौरान वित्त मंत्री द्वारा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क (MITRA) योजना की घोषणा की गई थी।

इस योजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग बनाना है:

- कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाना,
- बड़े निवेश को आकर्षित करना
- रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देना

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनाने में सक्षम बनाने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना।
- 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे।

घरेलू कपड़ा और परिधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5%, मूल्य के संदर्भ में उद्योग के उत्पादन का 7% और देश की निर्यात आय का 12% योगदान देता है। भारत विश्व में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत विश्व में कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह उद्योग भारत में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा नियोक्ता है क्योंकि इसमें 60% से अधिक कार्यबल की पूर्ति होती है। राष्ट्रीय स्तर पर, 60 से 80% श्रमिक परिधान क्षेत्र में महिलाएं हैं, जिनमें से लाखों अनौपचारिक, असंगठित या गृह-आधारित इकाइयों में कार्यरत हैं।

Q. 153) केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. निवेश क्षेत्र में एफडीआई (FDI) को बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।
2. बीमा क्षेत्र में एफडीआई में वृद्धि से भारत में बीमा उत्पादों की लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 153) Solution (b)

केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में अनुमेय FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति दी गई थी।

इस घोषणा के अनुवर्तन में संसद ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था और वित्त मंत्रालय ने 'भारतीय बीमा कंपनियों (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2021' को अधिसूचित किया है।

इस कार्यवाही का महत्व:

- बीमा को एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसमें लोगों का दीर्घकालिक धन होता है। अतीत में इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली।
- वर्तमान संशोधन एक समर्थकारी संशोधन है जो कंपनियों को जरूरत पड़ने पर विदेशी पूंजी तक पहुंच प्रदान करता है। यह स्वरूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि एफडीआई कैप में वृद्धि का मतलब है कि बीमा कंपनियां अब विदेशी स्वामित्व वाली और वर्तमान स्थिति के मुकाबले नियंत्रित हो सकती हैं, जिसमें वे केवल भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन हैं।
- विदेशी स्वामित्व में 74% की वृद्धि के परिणामस्वरूप भविष्य में बीमा उत्पादों के संदर्भ में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जा सकता है। यह भारत में बीमा उत्पादों की लागत को कम करने में भी मदद करेगा।
- यह एक विदेशी कंपनी को अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने, प्रबंधन को नियंत्रित करने और लिए गए नीतिगत निर्णयों का अधिकार देगा।
- इस कदम से सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत की बीमा पैठ या प्रीमियम में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में केवल 3.76 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक औसत 7 प्रतिशत से अधिक है।
- एक उच्च एफडीआई सीमा बीमा कंपनियों को उनकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी तक पहुंचने में मदद करेगी।
- बीमा एक लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय है। कंपनियों को ब्रेक ईवन (breakeven) और लाभदायक बनने में 7-10 साल लगते हैं। 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से विदेशी बीमा कंपनियों की ओर से अधिक रुचि दिखाई दे सकती है जो इस व्यवसाय में विशेषज्ञ हैं और जो तथाकथित 'धैर्यवान' पूंजी लाते हैं।
- अधिक एफडीआई कैप का मतलब यह होगा कि बीमा कंपनियों के अधिक प्रवर्तक अब पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं या अपने बीमा संयुक्त उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। यह कई राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को भी राहत प्रदान करेगा जो अपनी नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार पर निर्भर हैं और जिन्हें 'नॉन-कोर' व्यवसाय (non-core business) के रूप में माना जाता है, में अधिक धन लगाने से हतोत्साहित किया जा रहा है।

Q. 154) सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण की वसूली के लिए डिफॉल्टर की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है।
2. एनबीएफसी के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम ऋण आकार 50 लाख रु. है

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Answer (a)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 जिसे सरफेसी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण की वसूली के लिए आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों (डिफॉल्टर्स की) की नीलामी करने की अनुमति देता है।

अधिनियम गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली के लिए तीन वैकल्पिक तरीके प्रदान करता है, अर्थात्:

- प्रतिभूतिकरण
- संपत्ति पुनर्निर्माण
- न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा का प्रवर्तन

इस अधिनियम के तहत भारत की प्रथम परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC), एआरसीआईएल की स्थापना की गई थी।

केंद्रीय बजट 2021-22 में, वित्त मंत्री ने सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण वसूली के लिए पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के न्यूनतम ऋण आकार को मौजूदा 50 लाख रुपये से घटाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की।

- अधिनियम के तहत कार्यवाही से ऋणदाताओं को अपना बकाया तेजी से वसूल करने में मदद मिलती है।
- यदि कोई ऋणदाता सरफेसी अधिनियम का सहारा नहीं ले सकता है, तो उसे दीवानी अदालतों में मामले दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।
- सरफेसी के तहत वसूली केवल सुरक्षित ऋणों पर लागू होती है, और उधारदाताओं को उनके पास गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी करने की अनुमति देता है, ताकि उन उधारकर्ताओं से बकाया वसूल किया जा सके जिन्होंने ऋण पर डिफॉल्ट किया है।
- यह गृह ऋण, संपत्ति पर ऋण, और संपार्श्विक के विरुद्ध ऋण पर लागू होता है जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का लाभ लेते हैं।
- सरफेसी अधिनियम के तहत, एक ऋणदाता 60 दिनों के नोटिस के बाद संपत्ति या गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा ले सकता है। ऋणदाता भौतिक कब्जा ले सकते हैं या गिरवी रखी गई संपत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और किसी अदालत या तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना उन्हें खरीदार को बेच या हस्तांतरित कर सकते हैं।
- एक बार जब संपत्ति की नीलामी हो जाती है, तो ऋणदाता अपनी बकाया राशि काट लेता है और शेष धनराशि, यदि कोई हो, का भुगतान संपत्ति के मालिक को करता है।

वित्त उद्योग विकास परिषद, एनबीएफसी के लिए एक प्रतिनिधि निकाय, ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए उपलब्ध वसूली प्रक्रियाओं के बीच कुछ स्तर की समानता लाने के लिए सीमा को कम करने का सुझाव दिया था, क्योंकि पहले वित्त कंपनी अधिनियम के तहत ₹ 1 लाख से अधिक के ऋणों के लिए वसूली शुरू कर सकते हैं।

Q. 155) केंद्रीय बजट 2021-22 में, एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई थी:

- a) उड़ीसा
- b) गुजरात

- c) अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
- d) तमिलनाडु

Q. 155) Solution (d)

बजट 2021 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक बहुउद्देश्यीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।

समुद्री शैवाल की खेती एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें तटीय समुदायों के जीवन को बदलने की क्षमता है और यह बड़े रोजगार और अतिरिक्त आय प्रदान करेगा।

भारत में व्यावसायिक रूप से शोषित समुद्री शैवाल प्रजातियों में मुख्य रूप से कप्पाफाइकस अल्वारेजी, ग्रेसिलेरिया एडुलिस, गेलिडिएला एसरोसा, सरगैसम सप और टर्बिनेरिया सप शामिल हैं। समुद्री शैवाल को वाणिज्यिक उत्पादों जैसे कि कर्नेजेनन (Karrageenan) और अगर के लिए महत्व दिया जाता है, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड, उर्वरक, तलछट और अन्य उच्च मूल्य वाले उत्पादों जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मीस्यूटिकल्स के उत्पादन के लिए विभिन्न जीवन शैली रोगों के खिलाफ उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है।

समुद्री शैवाल पार्क का विकास अल्पपोषित और वंचित सीमांत समुदायों के एक बड़े वर्ग की पोषण सुरक्षा को संबोधित करने में एक लंबा मार्ग तय करेगा।

Q. 156) ऑपरेशन ग्रीन योजना (Operation Green Scheme) निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है:

- 1. आम
- 2. गेहूं
- 3. आलू
- 4. प्याज

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1, 2 और 3
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 3 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q. 156) Solution (c)

ऑपरेशन ग्रीन योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक पहल है।

इस योजना का उद्देश्य फलों और सब्जियों के उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण संकटग्रस्त बिक्री से बचाना और फसल के बाद के नुकसान को कम करना है।

पात्र फसलें:- फल- आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, खट्टे, अनानास, अनार, कटहल; सब्जियां:- फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च (हरी), लंबी भिंडी, प्याज, आलू और टमाटर। भविष्य में कृषि मंत्रालय या राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर कोई अन्य फल/सब्जी जोड़ी जा सकती है

मंत्रालय निम्नलिखित दो घटकों की लागत के 50% की दर से सब्सिडी प्रदान करेगा, लागत मानदंडों के अधीन:

- अधिशेष उत्पादन क्लस्टर से उपभोग केंद्र तक पात्र फसलों का परिवहन; और/या
- पात्र फसलों के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेना (अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए)।

Q. 157) ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (Rural Infrastructure Development Fund – RIDF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस कोष का मुख्य उद्देश्य राज्यों सरकारों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना है ताकि वे चालू ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर सकें।
2. आरआईडीएफ (RIDF) के तहत जारी की गई निधियों का रखरखाव सिडबी द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 157) Solution (d)

ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF) की स्थापना 1995-96 में सरकार द्वारा चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए की गई थी। इस फंड का रखरखाव नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा किया जाता है।

फंड का मुख्य उद्देश्य राज्यों सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करना है ताकि वे चालू ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर सकें।

आरआईडीएफ (RIDF) के तहत वित्तपोषित की जाने वाली गतिविधियों में लघु सिंचाई परियोजनाएं/सूक्ष्म सिंचाई, बाढ़ संरक्षण, जलसंभर विकास/जलभराव वाले क्षेत्रों का सुधार, जल निकासी, वन विकास, बाजार यार्ड/गोदाम, अपना मंडी, ग्रामीण हाट और अन्य विपणन बुनियादी ढांचे, कोल्ड स्टोरेज, बीज/कृषि/बागवानी फार्म, वृक्षारोपण और बागवानी, ग्रेडिंग और प्रमाणन तंत्र जैसे परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएं, आदि, पूरे गांव के लिए सिंचाई उद्देश्यों के लिए सामुदायिक सिंचाई कुएं, मछली पकड़ने के बंदरगाह/जेटी, नदी मत्स्य पालन, पशुपालन और आधुनिक बूचड़खाने शामिल हैं।

योग्य संस्थान हैं:

- राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र

- राज्य के स्वामित्व वाले निगम/राज्य सरकार उपक्रमों।
- राज्य सरकार प्रायोजित/समर्थित संगठन
- पंचायत राज संस्थान/स्वयं सहायता समूह (SHGs) / गैर सरकारी संगठन

वित्त का तरीका: नाबार्ड स्वीकृत राशि को प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी करता है, केवल प्रारंभिक मोबिलाइजेशन अग्रिम @30% पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए और 20% अन्य राज्यों के लिए।

ब्याज दर: 01 अप्रैल 2012 से, नाबार्ड के पास जमा राशि पर बैंकों को देय ब्याज दरों और आरआईडीएफ (RIDF) से नाबार्ड द्वारा वितरित ऋणों को उस समय प्रचलित बैंक दर से जोड़ा गया है।

Q. 158) कंसोलिडेटेड सिंकिंग फण्ड (CSF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह फंड आरबीआई द्वारा प्रशासित है।
2. यह राज्यों की संचित निधि का भाग है।
3. इस फंड का उपयोग केवल राज्य सरकारें ऋणों के ऋणमुक्ति के लिए करती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Q. 158) Solution (c)

Sinking Fund से तात्पर्य उस फंड से है जिसमें कुछ पैसा बचाकर या अलग करके इसलिए रखा जाता है, जिससे ऋण या बॉन्ड का भुगतान किया जा सके। आरबीआई द्वारा 1999-2000 में समेकित डूब कोष (सीएसएफ) की स्थापना की गई थी।

प्रारंभ में, 11 राज्यों - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल - ने सिंकिंग फंड की स्थापना की।

बाद में, 12वें वित्त आयोग (2005-10) ने सिफारिश की कि सभी राज्यों के पास सभी ऋणों के परिशोधन के लिए सिंकिंग फंड होनी चाहिए, जिसमें बैंकों से ऋण, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड की देनदारी आदि शामिल हैं।

निधि को राज्यों की संचित निधि और सार्वजनिक खाते से बाहर रखा जाना चाहिए।

इसका उपयोग ऋणों के मोचन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

योजना के अनुसार, राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष बकाया बाजार ऋण का 1-3% फंड में योगदान कर सकती हैं।

निधि का प्रबंधन आरबीआई नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग द्वारा किया जाता है।

Q. 159) जीआईएस-सक्षम भूमि बैंक प्रणाली (GIS-enabled Land Bank System) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है।
2. इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q. 159) Solution (d)

जीआईएस-सक्षम भूमि बैंक प्रणाली सभी औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधित जानकारी - कनेक्टिविटी, इंफ्रा, प्राकृतिक संसाधन और इलाके, खाली भूखंडों पर प्लॉट-स्तरीय जानकारी, गतिविधि की रेखा और संपर्क विवरण का वन-स्टॉप रिपोजिटरी (one-stop repository) है।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा विकसित किया गया है।

इसका उद्देश्य देश में इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक संभावित निवेशकों के लिए उपलब्ध भूमि के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

Q.160) आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में कुल एफडीआई (FDI) प्रवाह में सेवा क्षेत्र का लगभग 80% हिस्सा है।
2. भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान 48 प्रतिशत है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.160) Solution (c)

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार:

संपर्क गहन सेवा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ; विशेष रूप से उप-क्षेत्र जैसे पर्यटन, विमानन और आतिथ्य, कोविड-19 (COVID-19) महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। भारत का सेवा क्षेत्र लगभग 16% अनुबंधित है।

सेवा क्षेत्र का भारत के जीवीए में 54% से अधिक और भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 4/5 हिस्सा है। सेवा क्षेत्र के कुल निर्यात का 48% हिस्सा है जो हाल के वर्षों में वस्तुओं के निर्यात से बेहतर है।

